45वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

18/2, सत्संग विहार मार्ग,
विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के पास), नई दिल्ली 110067

दूरभाष. नंबर: 011 26569303, 26569780. 26569784

https://www.nipfp.org.in

45वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

01 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021

मुद्रण एवं प्रकाशन

सचिव

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक
स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)

18/2, सत्संग विहार मार्ग,
विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के पास),
नई दिल्ली 110067
दूरभाष. नंबर: 011 26569303, 26569780, 26569784
फैक्स: 91-11-26852548
ईमेल: nipfp@nipfp.org.in
वेबसाइट: www.nipfp.org.in

सम्पादन: : अमिता मन्हास

डिज़ाइन एवं कवर आर्ट: रोहित दत्ता

मुद्रक:

ईमेल:

दूरभाष.

विषय सूची

परिचय 1

अनुसंधान गतिविधियाँ 7

निष्पादित अध्ययन 7

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए निष्पादित अनुसंधान गतिविधियां 7

वित्त मंत्रालय के लिए निष्पादित अनुसंधान गतिविधियां.. 9

अन्य संस्थानोंसंगठनों के लिए/ निष्पादित अनुसंधान गतिविधियां 12

जारी अध्ययन 19

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जारी अध्ययन..19

वित्त मंत्रालय के लिए जारी अध्ययन..20

अन्य संस्थानों/संगठनों के लिए जारी अध्ययन 21

नई परियोजनाओं की पहल 32

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए प्रारंभ की गयी नई परियोजनाएं 32

अन्य संस्थानोंसंगठनों के लिए प्रारंभ की गयी नई परियोजनाएं/ 32

कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन 34

प्रशिक्षण कार्यक्रम.. 36

प्रकाशन और संचार.. 37

पुस्तकालय और सूचना केंद्र.. 38

ई- संसाधन 39

पुस्तकालय कर्मचारी गतिविधियाँ :2020-2021 42

कंप्यूटर केंद्र **43**

संकाय गतिविधियों के मुख्य बिंदु................................ 44

अनुलग्नक... 76

अनुलग्नक I: अध्ययनों की सूची 2020-21 77

अनुलग्नक II: एनआईपीएफपी: कार्यशील लेख श्रृंखला.................... 84

अनुलग्नक III: एनआईपीएफपी: आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला 86

अनुलग्नक IV: शासी निकाय के सदस्यों की सूची......................... 87

अनुलग्नक V: मूल्यांकित प्रकाशनों की सूची 92

अनुलग्नक VI: एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री 96

अनुलग्नक VII: स्टाफ सदस्यों की सूची (31 मार्च 2021 तक) 109

अनुलग्नक VIII: प्रायोजक, कॉर्पोरेट, स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची (31 मार्च 2021 तक) 114

अनुलग्नक IX: वित्त और लेखा 115

1 परिचय

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं निति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली की 45 वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान संस्थान के कार्यों का विवरण निम्नलिखित है। कोविड -19 महामारी की शुरुआत के कारण यह वर्ष संस्थान के लिए एक अभूतपूर्व स्थिति का द्योतक था। इसका संस्थान के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि यद्यपि हमें सीमित क्षमता के साथ प्रबंधन करना था तथापि अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रतिबद्धता को बनाए रखना था। एनआईपीएफपी संकाय के कई सदस्य और कर्मचारी वर्ष के दौरान कोविड -19 से संक्रमित हुए। मार्च-मई 2020 के दौरान संस्थान परिसर पचास दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और आधिकारिक बैठकें, शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन प्रणाली से आयोजित किए गए थे, जो की संस्थान के लिए एक अनूठी पहल थी।

पूरे वर्ष के दौरान, कोविड -19 प्रोटोकॉल लागू थे, जिसमें संकाय और कर्मचारी कार्यालय में क्रमबद्ध तरीके से आंशिक रूप से उपस्थित हुए थे। अब जब हम अपनी सामान्य स्थिति की और लौट रहें हैं इस अवधि में सम्पादित कार्य विपरीत परिस्थितियों में संस्थान के सामूहिक प्रयास और शैक्षणिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। वर्तमान और पिछली वार्षिक रिपोर्टों की एक डिजिटल प्रति संस्थान की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।

संस्थान का परिचय

एनआईपीएफपी की स्थापना 1976 में राजकीय अर्थशास्त्र और नीतियों के अनुसंधान केंद्र के रूप में की गई थी। संस्थान को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, कई राज्य सरकारों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की संयुक्त पहल पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीएफपी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है

संस्थान लोक वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, नीति समर्थन और क्षमता निर्माण का कार्य करता है। इसके मूल अधिदेशों में से एक साक्ष्य आधारित नीति इनपुट प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों को तैयार करने और सुधारने में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की सहायता करना है।

अपने अस्तित्व के 45 वर्षों में, संस्थान भारत में एक प्रमुख प्रबुद्ध मंडल के रूप में उभरा है और सरकार के सभी स्तरों पर नीतिगत सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाए रखा है, और भारत और विदेशों दोनों में

अन्य शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध बनाए हैं। यद्यपि संस्थान को वित्त मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है, यह अनुसंधान और नीति निर्माण के कामकाज में एक स्वतंत्र गैर-सरकारी चरित्र रखता है।

शासकीय मंडल

संस्थान की शासी निकाय ने 18 जून 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 5 अप्रैल 2020 से 4 अप्रैल 2024 तक चार वर्षों की अवधि के लिए खुद को पुनर्गठित किया। डॉ उर्जित पटेल अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय के प्रमुख हैं। वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री तरुण बजाज, राजस्व सचिव, श्री अजय सेठ, सचिव (आर्थिक मामलों) और डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व डॉ. राजीव रंजन, प्रभारी सलाहकार, मौद्रिक नीति विभाग के द्वारा और नीति आयोग सुश्री अन्ना रॉय, वरिष्ठ सलाहकार के द्वारा किया जाता है।

प्रायोजक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

प्रायोजक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं: श्री समीर कुमार सिन्हा, आईएएस, प्रमुख सचिव (वित्त), असम सरकार; श्री संजय एम कौल, आईएएस, सचिव (वित्त व्यय), केरल सरकार; और श्री मनोज सौनिक, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि श्री शमशेर सिंह रावत, प्रधान वित्त सचिव (एफएसी), आंध्र प्रदेश सरकार, श्री आई.एस.एन. प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार और श्रीमती स्मारकी महापात्रा, पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग के सचिव ने शासी निकाय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

श्री. प्रसन्ना बी, ग्लोबल हेड - मार्केट्स (सेल्स, ट्रेडिंग एंड रिसर्च) आईसीआईसीआई बैंक। श्री विनीत अग्रवाल, अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), और श्री उदय शंकर, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), संस्थाओं के नामित सदस्य हैं।

शासी निकाय ने अपनी पिछली बैठक में, दो प्रख्यात अर्थशास्त्री क्रमशः डॉ. एम. गोविंदा राव, पूर्व सदस्य, चौदहवें वित्त आयोग और डॉ. ज्योत्सना जालान, प्रोफेसर- अर्थशास्त्र, सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेज,, कलकत्ता को शासी निकाय के सदस्यों के रूप में शामिल किया

सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि डॉ. पूनम गुप्ता, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और सुश्री यामिनी अय्यर, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) हैं। सीए तरुण जे. घिया, काउंसिल के सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शासी निकाय के सह-चयनित सदस्य हैं।

डॉ पिनाकी चक्रवर्ती शासी निकाय के वर्तमान निदेशक और पदेन सदस्य हैं। डॉ. आर. कविता राव, प्रोफेसर, ने एक वर्ष की अवधि के लिए अक्टूबर 2020 से बोर्ड में एनआईपीएफपी संकाय का प्रतिनिधित्व किया। डॉ. लेखा चक्रवर्ती बोर्ड में संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाली नई बोर्ड सदस्य हैं।

शासी निकाय में विशेष आमंत्रित श्री जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय और श्री एम अजीत कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं। (विवरण के लिए अनुलग्नक IV देखें।)

निष्पादित एवं चल रही परियोजनाओं का सारांश

रिपोर्टिंग वर्ष में हमारे शोध लक्ष्यों, कराधान और राजस्व, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय प्रबंधन, व्यापक आर्थिक मुद्दे, अंतर सरकारी वित्तीय संबंध, और राज्य योजना और विकास आदि प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत टीमों द्वारा प्राप्त किया गया।

इसके अलावा, एनआईपीएफपी ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रोजगार सृजन, माल और सेवा कर (जीएसटी) के राजस्व प्रभाव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के वित्तीय पहलुओं बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए पेंशन और बीमा पूल का उपयोग, विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए नई तकनीक और पोषण सार्वजनिक व्यय समीक्षा जैसे सुव्यवस्थित नीति अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कई अध्ययन पूरे किए। हमारे विद्वतापूर्ण प्रकाशन अर्थव्यवस्था के राजस्व और व्यय दोनों पक्षों के विविध आयामों को समेटते है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कोविड-19 पैकेज का विश्लेषण और जीएसटी की दक्षता पर सरकारी खर्च का विश्लेषण शामिल है। संस्थान ने राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बाद की वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण शोध भी शुरू किया है।

हम राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं का बहुत बारीकी से निगरानी और अपने राज्यों के वित्त डेटा बैंक को लगातार अद्यतन करते रहते हैं। यह डाटा बैंक हमारा अनूठा संसाधन है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, हमने राज्य के वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोधपत्र प्रकाशित किए। संस्थान ने राज्य के वित्त पर पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के निहितार्थ पर चर्चा करने के लिए दो वेबिनार आयोजित किए, जिसमें प्रमुख राज्यों के वित्त सचिवों सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। हमने पारस्परिक हित के क्षेत्रों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ), म्यूनिख, जर्मनी के साथ सहयोग कर एक वैश्विक वैचारिक पहुँच बढ़ाने सम्बन्धी मुख्य पहल की है।

अखिल भारतीय और अन्य सेवाओं के कनिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संस्थान ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक अर्थशास्त्र में चौदहवें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का भी संचालन किया। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) और विश्व बैंक के साथ अनुसंधान साझेदारी शुरू की गई, जबकि मौजूदा भागीदारों के साथ काम जारी रहा तथा आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, शोध में राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के लिए प्रासंगिक कई मुद्दों को शामिल किया गया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एनआईपीएफपी ने अपने अधिदेश की प्रासंगिकता के मुद्दों पर वर्ष के दौरान कई कार्यशालाओं, बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया।

संस्थान ने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के साथ साझेदारी में 11 जून 2020 को नई दिल्ली में "नौकरियां, विकास और स्थिरता: भारत की रिकवरी के लिए एक नया सामाजिक अनुबंध" रिपोर्ट का प्रमोचन माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से एक समारोह में करवाया।

19 जून 2020 को नई दिल्ली में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से `इंडियाज इकोनॉमिक एजेंडा कोविड एंड पोस्ट कोविड 'पर एक आधे दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संस्थान ने 22 अक्टूबर 2020 को ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट-लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (जीआरआई-एलएसई), क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के साथ संयुक्त रूप से 'सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड -19' पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। यह गोलमेज सम्मेलन आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए आयोजित किया गया।

पांचवां पांच संस्थान बजट संगोष्ठी - 'द कोविड 19 बजट: केंद्रीय बजट 2021-22 का विश्लेषण- 8 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। पांच संस्थान - सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सी पि आर) इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर),इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ), नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और एनआईपीएफपी ने इस संगोष्ठी को एक साथ ऑनलाइन आयोजित किया।

23 फरवरी 2021 को, एनआईपीएफपी ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के लिए भारत में धारणीय वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की।

10 और 11 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के लिए 'कर विवाद समाधान' पर राष्ट्रमंडल से कर प्रशासकों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर दो वेबिनार और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव और वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन की संरचना 10 मार्च और 15 मार्च 2021 को विश्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए गए थे।

30-31 मार्च 2021 को 'आर्थिक सिद्धांत और नीति' पर दो दिवसीय वेब सम्मेलन का आयोजन किया गया।

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी प्रशिक्षुओं के 2019 बैच के लिए 8-12 फरवरी 2021 को लोक वित्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 1-13 फरवरी 2021 को लोक वित्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 22 फरवरी से 5 मार्च 2021 तक विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवाँ पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम। डॉ. विवेक देबरॉय, अध्यक्ष, ईएसी-पीएम ने उद्घाटन भाषण दिया और डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत ने उद्घाटन सत्र के दौरान विशिष्ट व्याख्यान दिया।

वर्ष 2020-21 के दौरान यात्रा पर प्रतिबंधों के कारण, संस्थान ने अपनी प्रक्रियाओं को संशोधित किया और सफलतापूर्वक काम करने के एक ऑनलाइन मोड में परिवर्तित हो गया, जिसमें घर से काम करना शामिल था। ऑनलाइन कामकाज में प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी, कागजात का प्रसार और संकाय और शोध कर्मचारियों द्वारा शोध निष्कर्ष भी शामिल थे।

आत्मनिर्भरता प्राप्ति प्रतिवेदन

एनआईपीएफपी को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अपने मुख्य कर्मचारियों के वेतन व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। वेतन व्यय का शेष भाग तथा अन्य प्रशासनिक एवं पूंजीगत व्यय संस्थान के अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है। अनुदान के अलावा, संस्थान विभिन्न मंत्रालयों के लिए परियोजनाएं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर राजस्व भी अर्जित करता है। संस्थान के अपने संसाधनों से पूरा किया गया व्यय 2019-2020 में 66.75 प्रतिशत और 2020-21 में 59.10 प्रतिशत था।

विकास

नियुक्तियां

- डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती 15 अक्टूबर 2020 को निदेशक, एनआईपीएफपी के रूप में शामिल हुए।
- डॉ. एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, 22 जून 2020 को एनआईपीएफपी से प्रतिनियुक्ति पर बेस यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के कुलपति के रूप में शामिल हुए।
- सुश्री सोनम सिंह ने 15 फरवरी 2021 को वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

त्यागपत्र

- डॉ. अजय शाह, प्रोफेसर ने 15 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया।
- डॉ. रथिन रॉय, निदेशक ने 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया।
- डॉ. रंजन कुमार मोहंती, सहायक प्रोफेसर ने 30 सितंबर 2020 को इस्तीफा दे दिया।.

निधन

- शासी निकाय के सदस्य डॉ. शैबल गुप्ता का 28 जनवरी 2021 को निधन हो गया।
- डॉ. सतद्रू दास, सहायक प्रध्यापक का, 11 मई 2021 को निधन हो गया।

2 अनुसंधान गतिविधियाँ

निष्पादित अध्ययन

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए निष्पादित अनुसंधान गतिविधियां

1. **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रोजगार सृजन पर अध्ययन। दिसंबर 2018-सितंबर 2020**

   प्रायोजक: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

   दल: एन.आर. भानुमूर्ति, भाबेश हजारिका, दिनेश कुमार नायक, कनिका गुप्ता, तन्वी ब्रम्हे, अशोक भाकर

   उद्देश्य: प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य '2020 तक सभी के लिए आवास' के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह अध्ययन कार्यक्रम के प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था पर इसके समग्र प्रभाव का विश्लेषण करता है। पीएमएवाई-यू के तहत किए गए निवेश के रोजगार प्रभाव का आकलन करते हुए, अध्ययन ने अनुमान लगाया कि कार्यक्रम ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न किया। अध्ययन में लाभार्थी परिवारों को कुछ मूर्त और अमूर्त लाभों के संदर्भ में योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है।

2. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के स्थानिक नियोजन घटक के कार्यान्वयन के लिए कानूनी विचारों का अध्ययन, 29 जनवरी-30 मार्च, 2021**

   प्रायोजक: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

   दल: इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, करण गुलाटी

   यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक विशेष अनुरोध पर स्वैच्छिक आधार पर की गई थी और काम के लिए कोई मानदेय नहीं लिया गया था।

   उद्देश्य: अध्ययन एक शोध उत्पाद है जिसका उद्देश्य निम्न प्रशनों पर एक रिपोर्ट तैयार करना है

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों की पहचान करें:
  - कृषि भूमि पर भू-राजस्व विभागों का अधिकार क्षेत्र, और यह संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियमों के तहत गाँवों के समूहों के लिए स्थानिक योजनाएँ, और ज़ोनिंग विनियमन और प्रवर्तन तंत्र तैयार करने के योजना के उद्देश्यों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

- अनुसूची V और VI क्षेत्रों में स्थानिक योजना तैयार करने और उसके प्रवर्तन के लिए विशेष विचार, और पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, और वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा शासित ग्राम पंचायतें।
- दो नमूना राज्यों के अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियमों को अधिसूचित करने और लागू करने के निहितार्थ।

- एसपीएमआरएम के सफल कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए मुद्दों को कम करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें तैयार करें।

3. वर्ष 2017-18 के लिए सिक्किम सरकार द्वारा राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा। दिसंबर 2020 से जून 2021

प्रायोजक: सिक्किम सरकार
दल: प्रताप रंजन जेना और सतद्रू सिकदर
उद्देश्य: समीक्षा रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के वित्तीय रुख और एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन किया। संस्थान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखा गया था और यह स्थापित जवाबदेही संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व था। राज्य सरकार के एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित एक स्वतंत्र वित्तीय समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है। जबकि वित्त आयोगों ने राजकोषीय परिषदों के गठन का सुझाव दिया, सिक्किम के एफआरबीएम अधिनियम में इसके एफआरबीएम अधिनियम की स्वतंत्र समीक्षा का प्रावधान है।

4. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखा परीक्षा। 27 दिसंबर 2019 - 30 जुलाई 2020।

प्रायोजक: केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार।
दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला और विभा कुमारी
उद्देश्य: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को उप-धारा (1)(बी) के तहत सूचीबद्ध प्रकृति की जानकारी का स्वतः खुलासा करने की आवश्यकता है। सरकारी विभागों को भी सूचना का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है जो आरटीआई आवेदकों द्वारा सबसे अधिक बार मांगी जाती है और इसे अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रावधान के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आगे निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय / सार्वजनिक प्राधिकरण को हर साल प्रत्येक मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का ऑडिट करवाना चाहिए और मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) को निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। . सीआईसी ने एनआईपीएफपी को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों के तीसरे पक्ष के ऑडिट करने का काम सौंपा है। अब तक, एनआईपीएफपी ने 2019-20 के लिए असाइनमेंट पूरा कर लिया है, और चूंकि यह एक वार्षिक अभ्यास होगा, संस्थान आने वाले वर्षों के लिए काम जारी रखेगा। एनआईपीएफपी ने बिना किसी अतिरिक्त भुगतान/शुल्क आदि के राजस्व विभाग के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य पूरा किया है।

5. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए जीएसटी का राजस्व प्रभाव। 6 जुलाई 2020 - 25 फरवरी 2021।**
प्रायोजक: वाणिज्य एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार।
दल: सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
उद्देश्य: इसकी शुरूआत के बाद, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) ने प्रारम्भ से ही राज्य सरकारों के स्वयं के कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा समाहित कर लिया है। जीएसटी के राजस्व महत्व को देखते हुए, जीएसटी से राजस्व प्राप्ति से जुडे संभावित राजस्व जोखिमों को समझना अलग-अलग राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जीएसटी संग्रह में आई कमी एक अन्य क्षेत्र है जो राज्यों को राजस्व झटके के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसलिए राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की तलाश करें और राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर अनुपालन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जीएसटी प्रशासन को मजबूत करें। राज्यों की उभरती राजस्व चुनौतियों के लिए जीएसटी प्रणाली के गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकें।
इस संदर्भ में, व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जीएसटी संग्रह में दिल्ली के राजस्व प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक अध्ययन करने के लिए एनआईपीएफपी से संपर्क किया।

6. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय पहलू: प्रभाव और भविष्य के लिए सीख। जनवरी 2019 से जुलाई 2020**
प्रायोजक: नीति आयोग, भारत सरकार
दल: मीता चौधरी और रंजन कुमार मोहंती
उद्देश्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अगला चरण अगले साल शुरू होने वाला है। इस अध्ययन में राज्यों के स्वास्थ्य व्यय में योजना के वित्तीय योगदान का विश्लेषण किया गया और उन्हें प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों पर प्रकाश डाला गया। विश्लेषण से पता चला है कि इस योजना ने राज्यों में स्वास्थ्य खर्च में असमानता को कम करने में योगदान दिया और स्वास्थ्य पिरामिड के निचले स्तरों में धन जोड़ा। हालांकि, अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन करने वाले 'उच्च फोकस' वाले राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में योजना का योगदान सीमित था। राज्यों में पूरक आदानों की कमी, क्षमता के मुद्दों और कमजोर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ने योजना के प्रदर्शन को प्रभावित किया

वित्त मंत्रालय के लिए निष्पादित अनुसंधान गतिविधियां

1. **दीपम में विनिवेश की प्रक्रिया पर शोध। 30 सितंबर 2020**
प्रायोजक: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
दल: रेणुका साने, सुदीप्तो बनर्जी, सृष्टि शर्मा, कार्तिक सुरेश
उद्देश्य: इस अनुसंधान का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालना है
    - दीपम की पंचवर्षीय दृष्टि योजना;
    - विनिवेश के लिए वर्तमान दृष्टिकोणों की समीक्षा;

- विनिवेश के नए रूप
- पहले से पूर्ण विनिवेश कार्य विवरणों का विश्लेषण
- शेयरों की बिक्री नियमित और पूर्वानुमेय आधार पर करने के तरीके।

2. **भौतिक स्टाम्पिंग और ई-स्टाम्पिंग की वर्तमान प्रणाली की जाँच करना और उसमें सुधार के उपाय सुझाना। 2021**
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य: देश भर में स्टांप शुल्क के भुगतान और संग्रह के लिए विखंडन और तत्संबंधी वर्तमान लागु व्यवस्था अक्षमताओं को दूर करने की जांच तथा एक समान तंत्र विकसित करने के लिए अध्ययन।

3. **निजी निवेश पर कोविड-19 के प्रभाव का प्रारंभिक आकलन।** 2021
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य: भारत में निजी निवेश पर कोविड-19 के प्रारंभिक प्रभाव पर शोध

4. **चीनी संप्रभु डिजिटल मुद्रा पर आलेख** 2021
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य:. चीन द्वारा परीक्षण के आधार पर शुरू की गई राज्य संचालित डिजिटल मुद्रा, इसके तौर-तरीके, अंतर्निहित प्रौद्योगिकियां और कमियों का लेखा जोखा।

5. **वर्तमान पेंशन योजनाओं का आकलन।** 2021.
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य: 10 प्रमुख केंद्रीय पेंशन योजनाओं का लाभ पर्याप्तता, शासन, स्थिरता और कवरेज पर आकलन।

6. **क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित कानून के मसौदे सहित अन्य मामलों के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान करना।** 2021
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य: 2019-20 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अद्यतनीकरण के लिए कई नए क्षेत्र और आगे के शोध प्रश्न।

7. **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मूल्यांकन।** 2021
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम

उद्देश्य: हितधारकों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और योजना की प्रभावशीलता और पहुंच में सुधार के लिए सुझाव।

8. **मुद्रास्फीति के प्रमुख कारकों की जांच - अंशदान आधारित पद्यति** । 2021
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य: भारत में मुद्रास्फीति के व्यवहार की जांच करने के अलावा, समग्र शीर्ष मुद्रास्फीति में वस्तु-वार अंशदान का अध्ययन।

9. **फिनटेक और एमएसएमई फाइनेंसिंग।** 2021
   प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
   दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
   उद्देश्य: कैसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पारिस्थितिकी तंत्र में क्रेडिट अंतर को कम कर सकते हैं, और संवितरण के लिए लगने वाले समय को काफी कम कर सकते हैं।

10. **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर टिप्पणी** । 2021
    प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
    दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
    उद्देश्य: निम्नांकित शीर्षकों पर अभिलेख प्रस्तुत किये गए: क) अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुति और ख) फिच रेटिंग्स से प्राप्त प्रश्नों की सूची पर प्रस्तुति

11. **वित्तीय बाजार प्रभाग और इसके संभावित प्रभाव से संबंधित घोषणाओं के साथ बजट** 2021-22 **के बाद बाजार प्रतिक्रिया पर आलेख** । 2021
    प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
    दल: सब्यसाची कर और डीईए टीम
    उद्देश्य: वित्तीय बाजार प्रभाग से संबंधित बजट 2021-22 की घोषणाओं और इसके संभावित प्रभाव के साथ-साथ बाजार की प्रतिक्रिया पर एक आलेख पत्र तैयार किया गया ।

12. **इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश में पेंशन और बीमा पूल का उपयोग। जून 2020-मई 2021**
    प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
    दल: सब्यसाची कर और मैक्रो-फाइनेंस समूह
    उद्देश्य: इस अध्ययन के द्वारा उद्देश्य थे
    - कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ भारत में पेंशन और बीमा उद्योग की संरचना और विनियमन का तुलनात्मक अध्ययन करना; तथा
    - बुनियादी ढांचा क्षेत्र और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)/उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ)/स्टार्टअप में पेंशन और बीमा कोष के साथ निवेश कोष के प्रवाह को

बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना और भारतीय पेंशन और बीमा पूलों को विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय मध्यम और दीर्घकालिक सुधारों की पहचान करना।

13. **विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए नई तकनीकें। जून 2020-मई 2021**
प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
दल: सब्यसाची कर और मैक्रो-फाइनेंस समूह
उद्देश्य: यह आलेख बिग डाटा और मशीन लर्निंग का सकल घरेलु उत्पाद, मुद्रास्फीति के पूर्वानूमान से सम्बंधित अनुसन्धान, साहित्य की समालोचनात्मक समीक्षा तथा विकासशील देशों के सन्दर्भ में इनकी उपयुक्तता का विश्लेषण है । डाटा संग्रह से सम्बंधित मुद्दों तथा बिग डाटा का पुनरीक्षण तथा इन् तकनीकों का विकासशील देशों खासकर भारत के सन्दर्भ में हानि-लाभ का आंकलन किया गया ।

14. **केंद्रीय बैंक प्रशोध द्वारा निर्गत डिजिटल मुद्राएं। जून 2020-मई 2021**
प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग
दल: सब्यसाची कर और मैक्रो-फाइनेंस समूह
उद्देश्य: इस कार्यपत्र ने थोक और खुदरा / सामान्य प्रयोजन केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) दोनों के लिए प्रमुख डिजाइन विशेषताएं, सीबीडीसी को शुरू करने के लिए प्रेरणा, सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों जैसे वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति, सीमा पार भुगतान आदि के लिए व्यावहारिक निहितार्थ और सीबीडीसी जारी करने के लिए प्रमुख कानूनी और नियामक विचार मूलभूत विषयों की पहचान की । भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सीबीडीसी जारी करने के हानि-लाभ की पहचान की।

अन्य संस्थानों/संगठनों के लिए निष्पादित अनुसंधान गतिविधियां

1. **अन्य संस्थानों/संगठनों के लिए पूरी की गई शोध गतिविधियां**
प्रायोजक: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
दल: इला पटनायक, राधिका पांडे, मेधा राजू, हरलीन कौर, रचना शर्मा
उद्देश्य: प्रस्तावित ढांचा दो साल के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) और एनआईपीएॅफ़पी के बीच एक औपचारिक शोध कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, एनआईपीएफपी निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा
    - विभिन्न अनुसंधान विषयों से संबंधित मुद्दों पर नीति निर्माण में सीएजी को अनुसंधान और विश्लेषणात्मक समर्थन;
    - शासन, लोक प्रशासन और निष्पादन, और पैसे के कीमत वसूली से संबंधित प्रश्नों पर सिफारिश प्रदान करना;
    - सार्वजनिक वित्त (कराधान, सरकारी ऋण और व्यय सहित) और वित्तीय विनियमन के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सहायता प्रदान करना; तथा

- सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित विभिन्न क्षेत्रों पर तकनीकी सहायता और अनुसंधान प्रदान करना जिसमें लेखा परिक्षण के विभिन्न, मानकों की पहचान शामिल होगी।

2. **इथियोपिया में अंतर सरकारी वित्तीय संबंध (प्रमाणन कार्यक्रम: एनआईपीएफपी, भारत; फेडरेशन ऑफ फोरम, कनाडा; हाउस ऑफ फेडरेशन, इथियोपिया और मेल्स जेनावी लीडरशिप अकादमी, इथियोपिया)। 2019-2020**
प्रायोजक: सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।
दल: लेखा चक्रवर्ती और मनीष गुप्ता
उद्देश्य: भागीदार संस्थानों के साथ समन्वय में प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तैयार करना और बिशोफ्टा, अदीस अबाबा में दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान प्रस्तुति।

3. **राज्य के बजट 2018-19 का विश्लेषण: प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां। 2019-20**
प्रायोजक: सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।
दल: लेखा चक्रवर्ती मनीष गुप्ता और अमनदीप कौर
उद्देश्य:. यह अध्ययन गेट्स फाउंडेशन के अनुदान द्वारा समर्थित शोध परियोजना, 'सार्वजनिक वित्त में नवाचार' का परिणाम है। डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती के नेतृत्व में निष्पादित इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय 'भारत में 28 राज्यों की बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियां' है। डॉ. चक्रवर्ती ने अगस्त 2019 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एनआईपीएफपी की वार्षिक राज्य वित्त बैठक के दौरान इस अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। टीम के अन्य सदस्य प्रो. लेखा चक्रवर्ती, डॉ मनीष गुप्ता और सुश्री अमनदीप कौर हैं। 21-23 अगस्त 2019 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की 75 वीं बैठक में लेखा चक्रवर्ती द्वारा बजट विश्वसनीयता पर थीम पेपर प्रस्तुत किया गया था। पूर्ण परियोजना रिपोर्ट को 2020 में एनआईपीएफपी मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया गया था।

4. **सार्वजनिक पोषण व्यय की समीक्षा: गुजरात से साक्ष्य। अगस्त 2018 - दिसंबर 2020**
प्रायोजक: सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: अमनदीप कौर और लेखा चक्रवर्ती (रुजेल श्रेष्ठ, कोमल जैन, अनिंदिता घोष और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)
उद्देश्य: राष्ट्रीय पोषण मिशन की पृष्ठभूमि में, यह लेख गुजरात राज्य में सार्वजनिक पोषण व्यय की समीक्षा करता है। एंथ्रोपोमेट्रिक (मानवशास्त्रीय) डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि कुपोषण अभी भी राज्य में एक मूक आपात स्थिति है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। एक बहु-क्षेत्रीय ढांचे में पोषण के लिए राजकोषीय स्थान का विश्लेषण किया गया था और राज्य के बजट का केवल एक नगण्य हिस्सा पोषण संबंधी खर्च के लिए आवंटित किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के सार्वजनिक व्यय आधारित विश्लेषण से पता चला है कि उपयोग की गयी इकाइयों के स्वरुप में भेद दिखता है, और राजकोषीय अंकन विश्लेषण से पता चलता है कि जो आवंटित किया गया है और जो खर्च किया गया है, उसके बीच बहुत बड़ा विभेद है। परिणाम पैरामीटर का तुलनात्मक

अध्ययन गुजरात के साथ अन्य राज्यों तथा अंतर-जिला अंतरों को दिखाते हैं जो कुपोषण से संबंधित हैं, जो मानवशास्त्रीय संकेतकों में बने रहते हैं। यह अध्ययन राज्य में सार्वजनिक-पोषण व्यय समीक्षा को मजबूत करने का आह्वान करता है ।

5. **भारत में कोविड 19 और राजकोषीय-मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएँ। मार्च-दिसंबर, 2020**
प्रायोजक:स्व-आरंभिक परियोजना, दो लेख (अनुसंधान सहयोग) प्रकाशित
दल: लेखा चक्रवर्ती और दिव्या रंगन
उद्देश्य: इस पहल के तहत तैयार किए गए दो लेख इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और प्रज्ञान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (आरबीआई रिसर्च इंस्टीट्यूट) के जर्नल में प्रकाशित हुए थे। इन पत्रों ने भारत में महामारी के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं को देखा।
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित लेख को बाद में उमा कपिला द्वारा संपादित किताब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल किया गया।

6. **भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश के निर्धारक: अधिकतम एन्ट्रॉपी एन्सेम्बल। अगस्त 2018-दिसंबर 2020**
प्रायोजक: स्व-आरंभ की गई परियोजना, (फोर्डहम विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क के साथ अनुसंधान सहयोग)।
दल: लेखा चक्रवर्ती
उद्देश्य:. इस पहल के तहत तैयार किए गए दो पेपर प्रकाशित किए गए, एक हृषिकेश विनोद और सीआर राव द्वारा संपादित सांख्यिकी की हैंडबुक में, एल्सेवियर पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशितऔर दूसरा पेपर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ ।

7. **जेंडर बजटिंग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अगस्त 2019-दिसंबर 2020।**

प्रायोजक: स्व-आरंभ की गई परियोजना, (अनुसंधान सहयोग)
दल: लेखा चक्रवर्ती
उद्देश्य: इस पहल के तहत तैयार किए गए दो पेपर एडवर्ड एल्गर हैंडबुक में "संघवाद और लिंग" श्रृंखला पर प्रकाशित किए गए थे और मई 2021 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्रॉफर्ड स्कूल में टैक्स एंड ट्रांसफर पॉलिसी इंस्टीट्यूट (टीटीपीआई) के (AusTax) औसटैक्स नीति ब्लॉग के रूप में प्रकाशित हुए थे।

8. **टीचिंग नोट: मल्टी लेवल गवर्नमेंट का सिद्धांत। 2020।**

प्रायोजक: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
दल: मुकेश आनंद और राहुल चक्रवर्ती
उद्देश्य: बहु-स्तरीय सरकारी प्रणाली में शासन, सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित संबंधों, विशेष रूप से वित्तीय, की परिकल्पना करता है। पिछले कुछ वर्षों में, ऐसी प्रणालियों में दूरगामी परिवर्तन हुए हैं जिससे

'निजी कॉर्पोरेट निकाय' और 'अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां' भी शासन में भाग लेती हैं। ये एक पदानुक्रमित रूप से 'संघवाद के सहकारी ढांचे' में संक्रमण की सुविधा प्रदान करते हैं।

9. **हिमाचल प्रदेश की जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (बीएसएपी) को अद्यतन करना और लाहौल-पांगी और किन्नौर परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीएसएपी को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति तैयार करना। 27 मार्च 2021।**

प्रायोजक: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

दल: रीता पांडे, रथिन रॉय, प्रिया यादव, अनुजा मल्होत्रा और गरिमा जसुजा

उद्देश्य:

- वर्तमान राज्य प्राथमिकताओं के आधार पर और जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण की राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ संरेखण में हिमाचल प्रदेश की मौजूदा जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (बीएसएपी) को अद्यतन करना ।
- हिमाचल प्रदेश में बीएसएपी योजना को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करना।
- हिम तेंदुए के परिदृश्य के संरक्षण के लिए दो वित्तीय समाधानों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया दस्तावेज तैयार करा - लाहौल-पांगी लैंडस्केप और किन्नौर लैंडस्केप।

10. **हिमाचल प्रदेश में लाहौल-पांगी और किन्नौर परिदृश्य के लिए जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना और वित्त समाधान। 27 मार्च 2021।**

प्रायोजक: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

दल: रीता पांडे, रथिन रॉय, प्रिया यादव, अनुजा मल्होत्रा और गरिमा जसुजा

उद्देश्य:

- राज्य में लाहौल-पांगी और किन्नौर परिदृश्य में जैव विविधता के लिए खतरों की पहचान करना और उनमें जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें करना।
- हिम तेंदुए के परिदृश्य के संरक्षण के लिए दो वित्तीय समाधानों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया दस्तावेज तैयार करें - लाहौल-पांगी लैंडस्केप और किन्नौर लैंडस्केप।

11. **सिक्किम की जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (बीएसएपी) को अद्यतन करना और कंचनजंगा - ऊपरी तीस्ता घाटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीएसएपी को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति तैयार करना। 22 मार्च 2021।**

प्रायोजक: यूएनडीपी

दल: रीता पांडे, रथिन रॉय, प्रिया यादव और अनुजा मल्होत्रा

उद्देश्य:

- सिक्किम की मौजूदा जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (बीएसएपी) को वर्तमान राज्य प्राथमिकताओं के आधार पर और जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण की राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ संरेखण में अद्यतन करना।

- सिक्किम में बीएसएपी को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करना।
- उत्तरी सिक्किम जिले में स्थित हिम तेंदुए के परिदृश्य, खांगचेंदज़ोंगा लैंडस्केप के संरक्षण के लिए एक या दो वित्तीय समाधानों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया दस्तावेज़ तैयार करना।

12. भारतीय राज्यों के लिए कर प्रयास और दक्षता को मापना। नवंबर 2018-अप्रैल 2020।

प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: आर कविता राव, डीपी सेन गुप्ता, सच्चिदानंद मुखर्जी, सुरांजलि टंडन और श्री हरि नायडू

उद्देश्य: भारत के संघीय ढांचे ने कुछ सिद्धांतों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कराधान शक्तियों को विभाजित किया। हालांकि, जीएसटी की शुरुआत के साथ राज्यों ने कई करों पर अधिकार क्षेत्र खो दिया है, क्योंकि कई राज्य करों को नए कर में शामिल कर लिया गया था। राज्यों को परिणामी राजस्व हानियों की सीमा स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर, राज्यों की राजस्व स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। राज्य सरकारों द्वारा कर प्रयासों के बावजूद, स्वयं के कर राजस्व में सुधार मामूली है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, राज्यों को अपने स्वयं के कर राजस्व में सुधार के लिए अन्य मौजूदा करों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीएसटी के बाद के शासन में राज्यों को प्रमुख राजस्व देने वाले कर, उत्पाद कर और स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क हैं, यह अध्ययन भारत के प्रमुख राज्यों की करग्राही क्षमता और प्रयासों का आंकलन करता है ।

13. डिजिटलीकरण से उपजती कर चुनौतियां। 31 मार्च 2021

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: सुरांजलि टंडन

उद्देश्य: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने आधार क्षरण लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) कार्यक्रम के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान पर काम किया है। इस परियोजना का उद्देश्य समावेशी ढांचे के भीतर देशों के लिए उपयुक्त समाधान खोजना है, जिसमें भारत भी शामिल है।

14. राज्यों के बजट के राज्य वित्त डेटा का अद्यतन: 2021-22 उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में संकाय के उपयोग के लिए सूचना का संकलन और मैक्रो टेबल बनाना। 1 अप्रैल 2020 - 30 जून 2020

प्रायोजक:एनआईपीएफपी

दल: रोहित दत्ता और अमर नाथ

उद्देश्य: राज्य के बजट की प्रस्तुति के तुरंत बाद सूचना को सॉफ्ट कॉपी में संकलित किया गया और संकाय के साथ साझा किया गया

15. संबंधित राज्यों के वित्त लेखा 2017-18 से सार्वजनिक वित्त सूचना को अद्यतन करना और इसे डिजिटल प्रारूप में संकाय के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्ण।

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: रोहित दत्ता और अमर नाथ

उद्देश्य:संकाय के लिए सूचना को डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

16. भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान: वेक्टर त्रुटि सुधार तंत्र बनाम। गैर-स्थिर समय श्रृंखला के लिए गतिशील कारक मॉडल दृष्टिकोण (सितंबर 2019 - सितंबर 2020)

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: रुद्रानी भट्टाचार्य और मिगांक्षी कपूर (बिट्स, पिलानी)

उद्देश्य: आर्थिक एजेंटों द्वारा आर्थिक निर्णय लेने और मौद्रिक नीति के समय पर कार्यान्वयन के लिए मुद्रास्फीति दर का लघु से मध्यम अवधि का पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में, हम भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल (वाईओवाई) मुद्रास्फीति के लिए दो वैकल्पिक पूर्वानुमान मॉडल विकसित करते हैं, जो बड़ी संख्या में व्यापक आर्थिक संकेतकों का उपयोग करते हैं। उपभोगता मुद्रास्फीति और इसके भावी अस्थिर और सह-एकीकृत इस मुद्दे को हल करने के लिए, हम उपभोगता मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी करने के लिए गैर-स्थिर समय श्रृंखला के लिए संशोधित वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (वीईसीएम) और गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) को नियोजित करते हैं। हम पाते हैं कि रूट मीन स्क्वायर एरर (आरएमएसई) के संदर्भ में, वीईसीएम मॉडल डीएफएम मॉडल की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करता है। हालांकि, डाइबोल्ड-मारियानो परीक्षण का उपयोग करते हुए दोनों मॉडलों में समान भविष्यवाणी सटीकता पाई गई है।

17. भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को एकीकृत करने में ई-नाम कितना प्रभावी है? प्याज बाजार से सबूत अप्रैल 2020 - मार्च 2021।

प्रायोजक:एनआईपीएफपी

दल: रुद्राणी भट्टाचार्य और सबरनी चौधरी

उद्देश्य: बाजार के विकृत नियमों और विनियमों की एक श्रृंखला भारत में एक एकीकृत कृषि बाजार के विकास में बाधा डालती है। राज्यों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि विपणन को विकसित करने के लिए विभिन्न सुधार उपाय किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने 2016 में कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करने की दिशा में पहले कदम के रूप में ई-एनएएम की स्थापना की। ई-एनएएम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) मंडियों को एकीकृत करता है। यह पेपर इस बात की जांच करता है कि क्या ई-एनएएम की शुरूआत

ने भारत में प्याज बाजारों के स्थानिक एकीकरण में सुधार किया है। संयोग विश्लेषण का उपयोग करते हुए, अध्ययन ने महाराष्ट्र, कर्नाटक के प्याज बाजार मूल्य एकीकरण की जांच की, 2010-2016 (ई-एनएएम से पहले) और 2016-2019 (ई-एनएएम के बाद) की अवधि के लिए भारत के औसत थोक प्याज मूल्य के साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल। यह 2016-2019 की अवधि के लिए बाजार एकीकरण के पक्ष में साक्ष्य प्रदान करता है, जबकि 2010-2016 के दौरान राज्यों में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई संबंध पाए जाते हैं। वास्तव में, सबूत बताते हैं कि 2016 में ई-एनएएम की शुरुआत से भारत में प्याज के लिए बाजार एकीकरण में सुधार हुआ है।

18. नाउकास्टिंग इंडियाज क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ: ए फैक्टर-ऑगमेंटेड टाइम वेरीइंग रिग्रेशन गुणांक मॉडल। नवंबर 2019 - दिसंबर 2020

प्रायोजक: एनआईपीएफपी और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर)

दल: रुद्रानी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मुंडले (एनसीएईआर), बोर्नाली भंडारी (एनसीएईआर) और सबरनी चौधरी

उद्देश्य: लघु से मध्यम अवधि की नीतियों के समय पर कार्यान्वयन के लिए अर्थव्यवस्था की नब्ज को वास्तविक समय में मापना आवश्यक है। इस अध्ययन में, हम अब तिमाही-दर-वर्ष जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, जो अनिवार्य रूप से तिमाही QT के लिए जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहा है, जब QT के लिए जीडीपी संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है, उच्च आवृत्ति संकेतकों (हम अपने विश्लेषण के लिए मासिक संकेतकों का उपयोग करते हैं) से जानकारी का उपयोग करते हुए। वह विशेष तिमाही QT। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मासिक संकेतकों के एक बड़े सेट से अनुमानित अनदेखे कारकों के एक सेट पर वापस आ जाती है, जहां प्रतिगमन गुणांक समय के साथ भिन्न होते हैं, और इस प्रकार अंतर्जात रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों का ध्यान रखते हैं। मॉडल का अनुमान राज्य-अंतरिक्ष प्रारूप में है। हम पाते हैं कि यह मॉडल डायनेमिक फैक्टर मॉडल जैसे वैकल्पिक मॉडलों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ में आने वाले मोड़ को बेहतर तरीके से पकड़ता है।

जारी अध्ययन

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जारी अध्ययन

1. **केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व, व्यय और बजट आवंटन का आकलन। अप्रैल 2019, ड्राफ्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत की गई**

   प्रायोजक: गृह मंत्रालय, भारत सरकार
   दल: मीता चौधरी, अमेय सप्रे
   उद्देश्य: केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के राजस्व और व्यय पर अध्ययन - विधायिका के साथ और बिना - के कई वित्तीय आयाम हैं क्योंकि अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों के व्यय गृह मंत्रालय के बजट के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। अध्ययन ने संघ शासित प्रदेशों के राजस्व और व्यय की स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया है और एक बजट आवंटन तंत्र का प्रस्ताव किया है जो उनके लिए निधि आवंटन में निष्पक्षता लाएगा, विशेष रूप से उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ विधायिका नहीं हैं । यह अध्ययन वित्त मंत्रालय के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेशों को निधि आवंटन के एक महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करता है और उनमें वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है।

2. **गर्भवती महिला मजदूरों के बीच बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर सशर्त नकद हस्तांतरण का प्रभाव: मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, मध्य प्रदेश से साक्ष्य। फरवरी 2020 और जून 2021**

   प्रायोजक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
   दल: भाबेश हजारिका, दिनेश कुमार नायक, एन.आर. भानुमूर्ति, कनिका गुप्ता, मनीष प्रसाद
   उद्देश्य: मध्य प्रदेश सरकार 2018 से पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए राज्य-विशिष्ट सशर्त नकद हस्तांतरण योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना (एमएमएसएसपीएसवाई) लागू कर रही है। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और माटाओं के स्वास्थ्य पर, अध्ययन इस बात का विश्लेषण करने पर केंद्रित है कि पंजीकृत गर्भवती महिला मजदूरों के बीच एमएमएसएसपीएसवाई ने किस हद तक बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। यह योजना के कार्यान्वयन के बारे में योजना जागरूकता, फंड प्रवाह (डिजाइन और देरी), व्यय प्रोफ़ाइल और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य व्यक्तियों की धारणा जैसे कार्यान्वयन और शासन के मुद्दों का भी विश्लेषण करता है।

3. **मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम, 2017-18 और 2018-19 के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा। फरवरी 2021 से सितंबर 2021 तक।**

   प्रायोजक: मध्य प्रदेश सरकार
   दल: प्रताप आर. जेना

उद्देश्य: अध्ययन में 2017-18 और 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रदर्शन और एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। अध्ययन में राज्य के वित्त का विस्तृत मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है जिसमें राजस्व प्रदर्शन, खर्च प्राथमिकताएं, बजट प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। अध्ययन एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन करेगा। अध्ययन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

4. **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई): डिजाइन रूपरेखा, उभरते पैटर्न और सरकार को लागत। अक्टूबर 2020 - अक्टूबर 2021।**

प्रायोजक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, भारत सरकार
दल: मीता चौधरी,द्वीपोबोती ब्रह्मा और प्रीतम दत्ता
उद्देश्य: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के माध्यम से निचले 40 प्रतिशत आबादी के लिए देशव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। यह प्रमुख योजना अगले कुछ वर्षों में सार्वजनिक व्यय की एक महत्वपूर्ण राशि के हिस्से को आकर्षित करेगी। हम पहले तीन वर्षों में योजना की पहुंच और दावों की जांच करते हैं ताकि उभरती रूपरेखा और राजकोषीय बोझ के साथ-साथ योजना पर सार्वजनिक खर्च की प्रभावशीलता पर उनके प्रभाव को उजागर किया जा सके।

5. **तमिलनाडु छठे राज्य वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे। दिसंबर 2020 के बाद**

प्रायोजक: छठा राज्य वित्त आयोग, तमिलनाडु सरकार
दल: पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, संप्रीत कौर
उद्देश्य: अध्ययन में तमिलनाडु के छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा सामना किए गए मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जो कोविड -19 महामारी के प्रकाश में अपने संदर्भ की शर्तों को संबोधित करते हैं, जिसने स्थानीय सरकारों के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, और स्थानीय निकाय अनुदान की सिफारिश की। वित्त आयोग। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि की अपनी अंतिम रिपोर्ट में स्थानीय निकाय अनुदानों में पर्याप्त वृद्धि की सिफारिश की। हालाँकि, इन अनुदानों का लाभ उठाने के लिए, राज्य को कई प्रवेश-स्तर की शर्तों को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त, इसके अनुदान का एक बड़ा हिस्सा सशर्त अनुदान था।

वित्त मंत्रालय के लिए जारी अध्ययन

1. **भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी के लिए संशोधित नियमावली। जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक।**

प्रायोजक:आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय।
दल: अमर नाथ एचके, मनीष गुप्ता, श्रीहरि नायडू
उद्देश्य: राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण में हाल के परिवर्तनों, राज्यों के बजट के लिए केंद्रीय समर्थन, कर संरचना (जीएसटी की शुरूआत) और योजनाओं को बंद करने के मद्देनजर, भारतीय

सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी (आईपीएफएस) की सामग्री में बदलाव की आवश्यकता है। कुछ वर्गों को बंद करने की आवश्यकता है जबकि अन्य को पुनर्गठन की आवश्यकता है। अध्ययन निम्न बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

- उन अध्यायों/अनुभागों/सारणियों की जांच करना जिन्हें बंद किया जा सकता है;
- हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी को कहां शामिल करने की आवश्यकता है;
- मौजूदा तालिका प्रारूपों में जोड़ने या हटाने का सुझाव तथा
- एक प्रारूप तैयार कर दो साल के लिए डेटा मूल प्रारूप में प्रस्तुत करना।

अन्य संस्थानों/संगठनों के लिए जारी अध्ययन

1. **अर्थव्यवस्था की स्थिति: ईएसी-पीएम को तिमाही आकलन और विकास पर दृष्टिकोणात्मक रिपोर्ट। नवंबर 2020 से अक्टूबर 2021**
   प्रायोजक: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम)
   दल: पिनाकी चक्रवर्ती, आर. कविता राव, लेखा चक्रवर्ती, सब्यसाची कर, पीआर जेना, मनीष गुप्ता, रुद्रानी भट्टाचार्य, अमेय सप्रे, दिनेश कुमार नायक, श्रुति त्रिपाठी
   उद्देश्य: अर्थव्यवस्था की स्थिति के त्रैमासिक मूल्यांकन पर एक लेख, जिसमें विकास, मुद्रास्फीति, केंद्र और राज्य सरकारों के कर संग्रह में रुझान, मौद्रिक और राजकोषीय नीति में विकास के रुझान शामिल हैं।

2. **भारत में सार्वजनिक खरीद तंत्र: एल-1 के लिए विकल्पों की खोज। फरवरी 2020 और जून 2021।**
   प्रायोजक: स्वयं की पहल
   दल: भाबेश हजारिका, आयुषी जैन
   उद्देश्य: वर्तमान अध्ययन भारत में सार्वजनिक खरीद के तंत्र पर केंद्रित है। कई दशकों से, अब, वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं में सार्वजनिक खरीद के लिए न्यूनतम लागत चयन (एल 1) पद्धति का पालन किया जाता रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), निति आयोग, फिक्की आदि जैसे विभिन्न संस्थानों ने इसे अधिक उपयुक्त तरीके से बदलने की आवश्यकता का सुझाव दिया है जो खरीद के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं दोनों पर केंद्रित है। यह अध्ययन सार्वजनिक खरीद तंत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालता है और एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) का सुझाव देता है जो हर पहलू में अधिक कुशल है।

3. **भूमि बाजारों को बेहतर बनाना। 8 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2021**
   प्रायोजक: ओमिदयार नेटवर्क
   दल: इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, करण गुलाटी, विराज जोशी, विशाल त्रेहन, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सारंग मोहरीर, गुंटास कौर उप्पल, नमिता गोयल, आंशी शर्मा
   उद्देश्य: भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है और संभवत: भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम सुधार वाले क्षेत्रों में से एक है। पिछले दो दशकों में विकास की बढ़ी हुई गति और परिणामी

शहरीकरण ने भूमि बाजारों में मांग-संचालित परिवर्तनों को जन्म दिया है। इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है:

- प्रशासनिक डिजाइन और क्षमता में सुधार के लिए भूमि प्रशासन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करना ।
- अक्षमताओं को कम करने, लेन-देन की लागत कम करने और भूमि बाजारों में बेहतर संपत्ति अधिकार बनाने के लिए भूमि पर अधिकारों और प्रतिबंधों की भूमिका को समझना।
- भूमि बाजारों में बाजार की विफलताओं और भूमि को नियंत्रित करने वाले नियमों की भूमिका और डिजाइन को समझना।

4. न्याय चुनौती के लिए डेटा। दिसंबर 2020 से जून 2021 तक।

प्रायोजक: वयम फोरम फॉर सिटिजनशिप

दल: इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, करण गुलाटी

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य भारत की अनुबंध प्रवर्तन मशीनरी को समझने के लिए एक डेटासेट बनाना है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

- समय श्रृंखला डेटासेट अनुबंध प्रवर्तन मुकदमे पर केस-स्तर, राज्यों के चुनिंदा जिलों और उच्च न्यायालयों में अनुबंधों से संबंधित विवादों पर नज़र रखना। डेटा को समय-समय पर उत्पाद के रूप में जारी करना ।
- अनुबंध प्रवर्तन सूचकांक, जो उपरोक्त डेटा से उत्पन्न होगा। इस आधार पर विभिन्न न्यायालयों और राज्यों के प्रदर्शन की निगरानी और तुलना करने के लिए समय-समय पर सूचकांक की गणना की जाएगी। तब उत्पन्न परिणामों का उपयोग नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

  प्रयोग करने योग्य डेटा की उपलब्धता पर निर्भर, उद्देश्य नियमित अभिव्यक्ति मिलान या वर्गीकरण एल्गोरिदम पर निर्णय/आदेश के असंरचित पाठ से अनुबंध प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक जानकारी निकालने के लिए एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग मॉड्यूल का विकास करना ।

5. फार्मास्युटिकल ड्रग्स और गुणवत्ता नियंत्रण की सार्वजनिक खरीद पर एक अध्ययन। जून 2020 से अप्रैल 2021 तक।

प्रायोजक: ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, इंक।

दल: इला पटनायक, हरलीन कौर, मधुर मेहता, आशिम कपूर, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

उद्देश्य: अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- सार्वजनिक खरीद पर केंद्र और राज्य सरकार के खर्च पर शोध;
- खरीद प्रक्रिया मूल्यांकन;
- निविदा प्रक्रिया;
- नीतियों को काली सूची में डालना;
- भारत दवा उद्योग में दवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक खरीद प्रणाली का लाभ कैसे उठा सकता है;

- दवाओं की खरीद के लिए विशिष्ट सार्वजनिक खरीद कानून की आवश्यकता है या नहीं;
- राज्यों को दवाओं की आपूर्ति करने वाली राष्ट्रीय कंपनियों की रूपरेखा;
- नॉट ऑफ़ स्टैण्डर्डाइज़्ड क्वालिटी (NSQ) दवाएं किसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन(सीडीएससीओ) समय-समय पर सुगम पोर्टल पर। खरीद प्रक्रिया में यह जानकारी क्या भूमिका निभाती है और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं।

6. **'विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों' पर आईसीएसएसआर-एमएचए परियोजना के लिए प्रलेखन केंद्र। मई 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)
दल: इला पटनायक, आशिम कपूर, रचना शर्मा
उद्देश्य: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने हाल ही में भारत में विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रायोजित एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में, एनआईपीएफपी आईसीएसएसआर को अध्ययन विषय से संबंधित एक डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए दस्तावेजों को इकट्ठा करने में सहायता कर रहा है। एनआईपीएफपी डिजिटल लाइब्रेरी का डिजाइन और रखरखाव करेगा, जिसमें प्राथमिक सामग्री जैसे संविधान सभा की बहस, कानूनी दस्तावेज, नीति दस्तावेज, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज और अनुबंध शामिल होंगे।

7. **ग्लोबल साउथ में राजकोषीय संघवाद। अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: लेखा चक्रवर्ती, गुरलीन कौर, अमनदीप कौर, जेनेट फरीदा जैकब, अनिंदिता घोष, दिव्य रंगन
उद्देश्य: ग्लोबल साउथ में संघवाद की सम्मेलन कार्यवाही की तैयारी। इस परियोजना में केन्या, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल और भारत के राजकोषीय संघवाद - राजस्व असाइनमेंट, व्यय असाइनमेंट, अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण - पर चर्चा की गई है।

8. **बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त: गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना का राज्य-स्तरीय विश्लेषण। अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर (अनिंदिता घोष के साथ (दिसंबर 2020 तक) और जेनेट फरीदा जैकब
उद्देश्य: स्कूली उम्र के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे अब 'प्रभावी रूप से स्कूल से बाहर' की श्रेणी में हैं। वे 'डिजिटल डिवाइड' (इंटरनेट तक पहुंच की कमी) के कारण शिक्षा से वंचित हैं - एक ऐसी स्थिति जो महामारी के कारण सामने आई है।
इस अध्ययन में, हम कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, महामारी के प्रति भारत की केंद्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकार की प्रतिक्रियाओं के विशिष्ट संदर्भ में बाल बजट का पता लगाते हैं। इन विशिष्ट राज्यों के बाल बजट पर हमारे अध्ययन से निष्कर्ष

वित्त मंत्रालय को केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जवाबदेही के लिए एक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन उपकरण के रूप में बाल बजट को मजबूत करने में मदद करेंगे।

9. **पर्यावरण/पारिस्थितिकीय वित्तीय स्थानान्तरण। 2019 से अगस्त 2020 तक।**
प्रायोजक: स्व-पहल
दल: लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, दिव्या रंगन
उद्देश्य: यह लेख कोविड -19 महामारी की पृष्ठभूमि में भारत में पारिस्थितिक वित्तीय क्षेत्र में फ्लाईपेपर प्रभावों के अनुभवजन्य साक्ष्य की पड़ताल करता है। पैनल डेटा मॉडल का उपयोग करते हुए, हम विश्लेषण करते हैं कि क्या अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण या राज्य के स्वयं के राजस्व का प्रभाव राज्य स्तर पर पारिस्थितिकी पर व्यय प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। अर्थमितीय विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य की अपनी आय के बजाय कुल अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण उप-राष्ट्रीय सरकारी स्तरों पर पारिस्थितिक व्यय को निर्धारित करता है। फ्लाईपेपर प्रभावों की प्रभावकारिता के प्रमाण या तो नौकरशाही के वित्तीय व्यवहार या पारिस्थितिक वित्तीय स्थान की बहिर्जातता के बारे में आर्थिक एजेंटों के वित्तीय भ्रम से उत्पन्न होते हैं। परिणाम तब होते हैं, जब मॉडल पारिस्थितिक परिणामों और जनसांख्यिकीय चर के लिए नियंत्रित होते हैं। तथापि, अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण के अलग-अलग स्तरों पर - अनुदान और कर हस्तांतरण - फ्लाईपेपर प्रभावों के साक्ष्य मिश्रित हैं। इस परिणाम के नीतिगत निहितार्थ हैं और यह राज्य सरकार के स्तर पर पारिस्थितिक व्यय पर अंतर-सरकारी हस्तांतरण की प्रभावकारिता के बारे में वित्त मंत्रालय को अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है।

10. **राजकोषीय नीति के लिए अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था । फरवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: स्व-पहल (अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी के साथ अनुसंधान सहयोग)
दल: लेखा चक्रवर्ती
उद्देश्य:. देखभाल अर्थव्यवस्था की सांख्यिकीय अदृश्यता चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में सभी राज्यों के लिए प्रकाशित समय उपयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 1993 के तहत आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए एक अभिनव डेटासेट है, जिसने अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों के घरेलू और सामाजिक स्तरों को शामिल करने के लिए उत्पादन सीमा का विस्तार किया। इन अनुमानों के जेंडर बजटिंग के लिए नीतिगत निहितार्थ हैं। यह लेख वित्त मंत्रालय द्वारा चल रही जेंडर बजटिंग पहलों के लिए (देखभाल अर्थव्यवस्था पर) विश्लेषणात्मक बैकअप प्रदान करेगा।

11. **शिक्षा और स्वास्थ्य में लैंगिक समानता और वित्तीय स्थान पर लैंगिक बजट की क्षेत्रीय व्यय प्रभावशीलता: एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अध्ययन। सितंबर 2019 से दिसंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: स्व-आरंभ की गई परियोजना (पहले संस्करण अटलांटा में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की बैठकों में प्रस्तुत किया गया था)
दल: लेखा चक्रवर्ती

उद्देश्य: यह लेख एशिया- प्रशांत क्षेत्रों के देशों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था ढांचे के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में लिंग के 'समान रूप से वितरित समकक्ष' चर पर लिंग बजट की प्रक्रियाओं और विश्लेषणात्मक ढांचे के विशेष संदर्भ के साथ, राजकोषीय नीति प्रथाओं के प्रभाव का अनुभवजन्य रूप से विश्लेषण करता है। -प्रशांत क्षेत्र। एनआईपीएफपी जेंडर बजटिंग में अग्रणी रहा है और 2004 में जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया। यह देखते हुए कि राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जेंडर बजटिंग की एनआईपीएफपी पद्धति अपरिवर्तित बनी हुई है, हम इस टाइम सीरीज डेटा का उपयोग लैंगिक समानता परिणामों और वित्तीय स्थान पर जेंडर बजट के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं।

12. **कोविड -19 और एशिया प्रशांत में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का विश्लेषण। अगस्त 2020 से मई 2021 तक।**

प्रायोजक: स्व-आरंभ

दल: लेखा चक्रवर्ती (अमनदीप कौर, दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)

उद्देश्य: पेपर आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों के राजकोषीय और मौद्रिक नीति घटकों का विश्लेषण करता है, जिसमें लिंग और मानवाधिकार मूल्यांकन शामिल हैं। इसके चार विशिष्ट घटक हैं:

- खाद्य सुरक्षा,
- सामाजिक सुरक्षा,
- सामाजिक आधारभूत संरचना और सेवा प्रावधान और
- आर्थिक गतिविधि और रोजगार।

एशिया प्रशांत देशों के अनुभवजन्य साक्ष्य महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने में वित्त मंत्रालय को अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अध्ययन मई 2021 में एनआईपीएफपी मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। मुख्य अध्याय को मई 2021 में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्रॉफर्ड स्कूल में टैक्स एंड ट्रांसफर पॉलिसी इंस्टीट्यूट (टीटीपीआई) के ऑसटैक्स पॉलिसी ब्लॉग के रूप में भी प्रकाशित किया गया है।

13. **भारत में श्रम के बीज संतोष-असंतोष । मई 2020।**

प्रायोजक: स्व-आरंभ

दल: मुकेश आनंद और राहुल चक्रवर्ती

उद्देश्य: परिचालन अधिशेष (समग्र पूंजी पर वापसी) की तुलना में कर्मचारियों के मुआवजे (श्रम पर वापसी) पर (प्रभावी) कर की उच्च दर न केवल श्रम की मांग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, बल्कि पूंजी को गहरा करने की आव्यशकता को और बल प्रदान करता है । इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में हाल के संशोधनों की एक संकीर्ण प्रयोज्यता श्रमिकों की मजदूरी की उम्मीद को कम करती है और श्रम आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के स्थिर विकास की सुविधा के लिए, यह लेख निम्नांकित सुझाव देता है (ए) कर क्षेत्र को पुनर्संतुलित करना जो वर्तमान में पूंजी से श्रम से मूल्यवर्धन के पक्ष में है, (बी) कानूनों को लागू करने और श्रम मांग अनुसूची को सुचारू बनाने

के लिए श्रम-इनपुट थ्रेसहोल्ड को समाप्त करना , और (सी) न्यूनतम पारिश्रमिक को सही आकार देने के लिए प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना ताकि मजदूरी की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और श्रम आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा सके।

14. **भारत में सामाजिक पेंशन: एक सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम का अग्रदूत। जुलाई 2021।**
प्रायोजक: स्व-आरंभ
दल: मुकेश आनंद और राहुल चक्रवर्ती
उद्देश्य: भारत में सामाजिक पेंशन की चर्चा एक सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम के एक घटक के रूप में की जाती है। भारत में मौजूदा कार्यक्रम को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संदर्भित किया गया है और विशेष रूप से दक्षता और पर्याप्तता (लाभार्थियों की) और सेवा प्रदान करने (लाभों की) में दक्षता पर मूल्यांकन किया गया है।

15. **कर नीति और अनुपालन के प्रति दृष्टिकोण का आकलन। मार्च 2021 से मार्च 2022 तक।**
प्रायोजक:बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: आर कविता राव
उद्देश्य: कर नीति और कर प्रशासन के प्रति करदाताओं के दृष्टिकोण और अनुपालन पर उनके प्रभाव पर काफी मात्रा में शोध किया जा रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि करदाताओं का अनुपालन व्यवहार कई तरह के कारकों से प्रभावित होता है जैसे कर अनुपालन के प्रति आंतरिक दृष्टिकोण, सामाजिक मानदंड, साथ ही करदाता की अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। भारत में, इस क्षेत्रों में अभी तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ है । यह अध्ययन भारत में आयकर के संबंध में अनुपालन के संबंध में लोगों के दृष्टिकोण और धारणाओं का दस्तावेजीकरण करने का प्रस्ताव करता है। इस तरह के अध्ययन से हम अनुपालन में सुधार के लिए उन मुद्दों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जिन पर करदाता सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे ।

16. **डेटा गवर्नेंस नेटवर्क। अप्रैल 2019 से सितंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: आईडीएफसी फाउंडेशन और ओमिदयार नेटवर्क
दल: रेणुका साने, ऋषभ बेली, स्मृति परशीरा, फैजा रहमान, वरुण सेन बहल, त्रिशी गोयल
उद्देश्य: अध्ययन के तहत प्रस्तावित अनुसंधान क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
    - पहचानें कि गोपनीयता नीतियों की समझ क्या है- क्या उम्र, शिक्षा, खुफिया भागफल, अंग्रेजी के साथ आराम, शहरीकरण, इंटरनेट-आधारित सेवाओं से परिचित जैसे कारक, सभी एक भूमिका निभाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति प्रस्ताव पर क्या मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन भारत में गोपनीयता अधिकारों की विभिन्न अवधारणाओं और तौर-तरीकों (अभिव्यक्ति के) का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण का भी प्रस्ताव करता है।
    - डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (डीपीए) के लिए एजेंसी का डिज़ाइन। डेटा सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर चल रहे काम से एक नया नियामक, डेटा सुरक्षा प्राधिकरण बनाने की उम्मीद है। डीपीए को महत्वपूर्ण नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के साथ सौंपे जाने की उम्मीद है। इस अध्ययन

में, हम डीपीए के निर्माण के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं।

- भारत में वर्तमान निगरानी संबंधी कानून, नीतियां और तंत्र। अध्ययन में मौजूदा प्रणालियों में कमियों की पहचान करने और नीतिगत पहलों का सुझाव देने का प्रस्ताव हैनिगरानी कानूनों में सुधार के लिए।
- ड्रोन, सीसीटीवी, चेहरे की पहचान, सेल टावर ट्रैकिंग, एन्क्रिप्शन टूल्स इत्यादि जैसी विशिष्ट तकनीकों/अनुप्रयोगों के उपयोग के आसपास गोपनीयता के मुद्दों का अध्ययन करना।

17. भारत के लिए उपभोक्ता वित्त में एक शिकायत निवारण प्रबंधन ढांचे की व्यवस्था । 5 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक।

प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: रेणुका साने, मिथिला ए सारा, अनन्या गोयल, सुदीप्तो बनर्जी, सृष्टि शर्मा, कार्तिक सुरेश, सुरेश कुमार, मधुर मेहता, कुसन बिस्वास, करण गुलाटी, अदिति डिमरी

उद्देश्य: अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं क्या हैं और एक अच्छे जीआरएम के सिद्धांत क्या हैं । जीआरएम को और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है, विशेष रूप से काफी गरीब आबादी वाले बड़े देशों में।
- किसी समस्या का सामना करने पर उपभोग्ता परिवार क्या करते हैं, यह समझने के लिए मौजूदा उत्पादों और जीआरएम के साथ उपभोक्ता के अनुभवों का मूल्यांकन करें।
- उपभोग्ता परिवारों पर मौजूदा जीआरएम के प्रभाव का मूल्यांकन करें' वित्तीय बाजारों में भागीदारी पर निर्णय लेने और पिछले अनुभव का विश्लेषण करने के लिए और वे भौतिक संपत्तियों में अतिरिक्त प्रवाह से कैसे संबंधित हैं।
- इस विविधता का मूल्यांकन करें कि कैसे घरेलू प्रतिक्रियाएं उनकी विशेषताओं से भिन्न होती हैं। यह अध्ययन कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर यह समझने का भी प्रयास करेगा कि क्या उच्च आय वाले परिवारों में कम आय वाले परिवारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन होता है: क्या गरीबों को अनुपात से अधिक कल्याण ह्रास का सामना करना पड़ता है; जोखिम की भूख के आधार पर उनकी प्रतिक्रिया में अंतर कैसे किया जा सकता है यह उनकी समय वरीयता की दरों से किस प्रकार भिन्न है?

18. स्कूली शिक्षा पर जेंडर सेंसिटिव बजटिंग पर अध्ययन। 2019

प्रायोजक: शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन (एनसीई)

दल: सुकन्या बोस और अनुराधा डे, सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रसार (CORD)

उद्देश्य: जेंडर बजट एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो सरकार के बजट की छानबीन करता है ताकि उसके लिंग-विभेदित प्रभाव को प्रकट किया जा सके और महिलाओं के सामने आने वाले लिंग-आधारित नुकसान को दूर करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अधिक प्राथमिकताओं की वकालत की जा सके। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर बजटिंग की

नीतियों और प्रथाओं को लागू करना है। क्या जेंडर बजट मौजूद हैं? यदि हाँ, तो लड़कियों की शिक्षा की योजना बनाने और उन्हें प्राथमिकता देने के एक साधन के रूप में ये कितने अर्थपूर्ण हैं? बजट में परिलक्षित लड़कियों पर शिक्षा खर्च का पैटर्न क्या है? अधिक सार्थक जेंडर बजटिंग अभ्यास के लिए डेटा में किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है?

19. **सरकारी स्कूलों से बाहर निकलने की जांच अप्रैल 2019।**
प्रायोजक: अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट, 2018
दल:सुकन्या बोस, प्रियंता घोष, मनोहर बोड़ा और अरविंद सरदाना (एकलव्य)
उद्देश्य: यह अध्ययन सरकारी स्कूलों से बाहर निकलने की घटना को गहराई से समझने का प्रयास करता है, जिसमें पिरामिड के निचले भाग में निकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कम फीस वाले निजी स्कूल (एलएफपीएस) सरकारी स्कूलों के करीबी विकल्प के रूप में उभरे हैं, हालांकि स्कूली शिक्षा में इस बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। अध्ययन एलएफपीएस क्षेत्र के आकार को स्थापित करने की कोशिश करता है, ऐसी जानकारी जो किसी भी योजना और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी स्कूली शिक्षा की अतिरिक्त मांग को सार्वजनिक स्कूली शिक्षा पर अधिक निवेश के माध्यम से राज्य से आपूर्ति प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हम अनुमान लगाते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विस्तार के लिए सार्वजनिक संसाधन की जरूरत है। निजी स्कूलों के नियमन पर औपचारिक नीति, इसकी विभिन्न व्याख्याएं और क्षेत्र में वास्तविक प्रथाओं की जांच दिल्ली के एलएफपीएस के संदर्भ में की जाती है।

20. **भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रोइकोनोमेट्रिक मॉडलिंग (निरंतरता)। फरवरी 2021**
प्रायोजक: स्वयं की पहल
दल: एनआर भानुमूर्ति और सुकन्या बोस
उद्देश्य: इसका उद्देश्य नीति अनुकरण अभ्यासों के माध्यम से विभिन्न बाहरी झटकों को देखते हुए वर्तमान व्यापक आर्थिक नीति विकल्पों के उत्तर खोजना है। नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करते हुए एनआईपीएफपी मैक्रो-इकोनोमेट्रिक मॉडल के पुन: आकलन के आधार पर विकास, मुद्रास्फीति, बाहरी और राजकोषीय संतुलन पर बाहरी झटकों के प्रभाव के सिमुलेशन पर काम किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित एफआरबीएम रोडमैप का मैक्रो-परिणामों पर प्रभाव का भी आंकलन किया जा रहा है ।

21. **महामारी वर्ष 2020 में राज्यों के राजस्व और व्यय की रूपरेखा। सितंबर 2020, संभावित समाप्ति तिथि अक्टूबर 2021।**
प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल:मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता, रोहित दत्ता, राशि मित्तल, गरिमा नैन, रागिनी
उद्देश्य: यह अध्ययन 2019-20 (संदर्भ वर्ष) की तुलना में 2020-21 में भारत के प्रमुख राज्यों के राजस्व और व्यय में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। राजस्व में, हम केंद्र सरकार से घटक-वार परिवर्तन और हस्तांतरण की जांच करते हैं। व्यय में, हम महामारी के दौरान आर्थिक क्षेत्रों में खर्च के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र के खर्च की रक्षा में राज्यों में विभिन्न प्रतिक्रिया को समझने

के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण करते हैं। सीएजी द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल आंकड़े, राज्यों में प्रधान महालेखा परीक्षक (पीएजी) के कार्यालय द्वारा संकलित मासिक सिविल लेखा और राज्य के बजट में उपलब्ध कराए गए संशोधित आंकड़ों का उपयोग निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है।

22. **स्वास्थ्य और शासन गुणवत्ता पर सार्वजनिक खर्च की क्षमता। अगस्त 2020, संभावित समाप्ति तिथि जून 2021**
प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF)
दल: द्वीपोबोती ब्रह्मा, मीता चौधरी और रागिनी
उद्देश्य: निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य प्रणालियां अक्षमताओं से ग्रस्त हैं, जिसके कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणाली का प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है और खराब स्वास्थ्य परिणाम आते हैं। इस अध्ययन में हम भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य में सार्वजनिक खर्च की दक्षता की जांच करते हैं। राज्य-स्तरीय पैनल डेटा और स्टोकेस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण का उपयोग करते हुए, हम पहले विभिन्न राज्यों के लिए सार्वजनिक खर्च में तकनीकी दक्षता का अनुमान लगाते हैं। हम सबसे कम और तकनीकी रूप से कुशल राज्यों की पहचान करते हैं। हम राज्यों में तकनीकी दक्षता और शासन की गुणवत्ता के बीच संबंधों की जांच करते हैं और दक्षता और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार के कई तरीकों पर चर्चा करते हैं।

23. **गुजरात में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का अंतर-राज्य वितरण: क्षैतिज और लंबवत इक्विटी। नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक।**
प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: मीता चौधरी, जय देव दुबे
उद्देश्य: यह अध्ययन गुजरात राज्य में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च के अंतर-राज्य वितरण पर केंद्रित है, राज्य-स्तरीय सार्वजनिक खर्च पर अधिकांश साक्ष्य राज्य-स्तरीय योगों तक ही सीमित हैं और राज्य के भीतर वितरण पर सीमित ध्यान दिया गया है। हम राज्य के भीतर क्षैतिज (जिले में) और ऊर्ध्वाधर (देखभाल के स्तरों के पार) इक्विटी दोनों की जांच करते हैं। यह अध्ययन भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च के अंतर-राज्यीय वितरण पर हमारे चल रहे काम का विस्तार है।

24. **भारत में कर विवादों का विश्लेषण (निरंतरता)। 31 मार्च 2020**
प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: सुरांजलि टंडन और आदित्य रेड्डी
उद्देश्य: इस परियोजना में भारत में अंतरराष्ट्रीय कर विवाद समाधान तंत्र की विस्तृत समीक्षा और भारत में विवाद समाधान प्रणाली में सुधार के तरीके खोजने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की एक अंतरराष्ट्रीय तुलना की गई ।

25. **भारत में वित्तीय बाजारों का कराधान (निरंतरता)। 31 मार्च 2020**
प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
दल: सुरांजलि टंडन, आर कविता राव और आदित्य रेड्डी

उद्देश्य: निगमों द्वारा पूंजी और निवेश निर्णयों का चुनाव ऋण और इक्विटी के विभिन्न व्यवहार पर निर्भर करता है। यह परियोजना उपकरणों के कर उपचार और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विस्तृत समीक्षा प्रदान करती है।

26. क्या भारत में मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की उम्मीद को बांधती है? सितंबर 2019-दिसंबर 2021।

प्रायोजक: प्रोफेसर पीआर ब्रह्मानंद अनुसंधान अनुदान, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु, 2018-19

दल: रुद्राणी भट्टाचार्य

उद्देश्य: भारत ने 2015 में लक्षित मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति व्यवस्था आधारित हुई। इस नियम-आधारित मौद्रिक नीति व्यवस्था के तहत, नीतिगत दर में परिवर्तन तर्कसंगत आर्थिक एजेंटों की मुद्रास्फीति की अपेक्षा को बदलकर आर्थिक गतिविधियों और वर्तमान मुद्रास्फीति दर को प्रसारित करता है। यह अध्ययन अनुभवजन्य रूप से जांच करता है कि क्या मौद्रिक नीति भारत में आर्थिक एजेंटों की मुद्रास्फीति की उम्मीद को रोक सकती है। हमारे विश्लेषण में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा का सर्वेक्षण आधारित माप निजी एजेंटों की मुद्रास्फीति की अपेक्षा को दर्शाता है। एक सह-एकीकृत वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) मॉडल का उपयोग करते हुए, हम भारत में ब्याज दर चैनल के माध्यम से मध्यम लेकिन महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति संचरण पाते हैं। हालांकि, देश में मौद्रिक नीति के संचालन से मुद्रास्फीति की उम्मीद असंबद्ध प्रतीत होती है।

27. भारत में विनिमय दर अस्थिरता पर विदेशी मुद्रा नीति के झटके के प्रभाव को मापना। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: रुद्रानी भट्टाचार्य, और शुभंकर मयंक (समर इंटर्न, अप्रैल-मई, 2020)

उद्देश्य: विनिमय दर की स्थिरता हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी मौद्रिक नीति व्यवस्था कुछ भी हो। यह लेख प्रमुख घटनाओं (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू महत्व दोनों) का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद रुपया-डॉलर विनिमय दर को प्रभावित किया, और गार्च मॉडलिंग, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन और बूस्टेड रिग्रेशन ट्री का उपयोग करके विदेशी मुद्रा नीति के झटके के प्रभाव को रुपया-डॉलर विनिमय दर की अस्थिरता पर प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास किया।

28. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को समझना और उनका मूल्यांकन करना। फरवरी से जून 2021

प्रायोजक: विश्व बैंक

दल: पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, अमनदीप कौर

उद्देश्य: वित्त आयोग के स्थानान्तरण राज्यों को कुल हस्तांतरण का दो-तिहाई से अधिक का हिस्सा है। उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशीलता, राजकोषीय स्थिरता और राजकोषीय स्थान के संदर्भ में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। केंद्र

और राज्यों के बीच राजकोषीय स्थिरता, परिणाम आधारित क्षेत्रीय अनुदान, और स्थानीय स्तर पर वित्त और सेवा वितरण को मजबूत करना पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह अध्ययन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वित्तीय स्तिथि पर आयोग की सिफारिशों के प्रभाव पर चर्चा करता है।

29. **राज्यों के बजट के राज्य वित्त डेटा का अद्यतन- 2022-23: उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में संकाय के उपयोग के लिए सूचना का संकलन और मैक्रो टेबल बनाना। 1 अप्रैल 2021, संभावित समापन तिथि 30 जून 2022।**

प्रायोजक:एनआईपीएफपी

दल: रोहित दत्ता और अमर नाथ

उद्देश्य: 2022-23 तक बजट पेश होने के तुरंत बाद सॉफ्ट कॉपी में संकाय सदस्यों को राज्य के वित्त पर संकलित जानकारी उपलब्ध कराना।

30. 2018-19 के वित्त लेखों से लोक वित्त की जानकारी को अद्यतन करना और इसे डिजिटल प्रारूप में संकाय के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करानासंबंधित राज्यों। **प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजना अद्यतन**

प्रायोजक:एनआईपीएफपी

दल: अमर नाथ, हरि नायडू और रोहित दत्ता

उद्देश्य: जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

नई परियोजनाओं की पहल

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए प्रारंभ की गयी नई परियोजनाएं

1. **राज्य वित्त आयोग के लिए नियमावली। फरवरी 2021**

   प्रायोजक:केरल सरकार
   दल: पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, दिनेश कुमार नायक, वासुकी नंदन, स्मृति मेहरा
   उद्देश्य: यह अध्ययन राज्य वित्त आयोगों के कामकाज से संबंधित बुनियादी मुद्दों की जांच करता है। यह स्थानीय सरकारों के संबंध में केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों का भी विश्लेषण करता है और विभिन्न राज्यों में अपनाई गई कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी प्रकाश डालता है।

2. **भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन: सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) और निवेश में योगदान। 4 मार्च 2021।**
   प्रायोजक: कारपोरेट कार्य मंत्रालय
   दल: इला पटनायक, प्रमोद सिन्हा, मधुर मेहता
   उद्देश्य: कई अध्ययनों ने नए आधार वर्ष जीडीपी श्रृंखला के साथ कार्यप्रणाली संबंधी चिंताओं को उजागर किया है और दो आधार वर्ष श्रृंखला का उपयोग करके प्राप्त विकास अनुमानों में असंगत प्रवृत्तियों पर चर्चा की है। फर्मों के वार्षिक वित्तीय विवरणों का उपयोग करके विकास के अनुमान पर पहुंचने का प्रयास करने पर अपेक्षाकृत कम साहित्य है। इससे हमें विकास की कहानी के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह अध्ययन आर्थिक विकास को मापने के लिए एक प्रमुख मीट्रिक सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) के आधार पर विकास अनुमान उत्पन्न करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में फर्मों के वार्षिक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव करता है।

अन्य संस्थानों/संगठनों के लिए प्रारंभ की गयी नई परियोजनाएं

1. **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन: ज्ञान और नवाचार नेटवर्क। फरवरी 2021।**
   प्रायोजक: विश्व बैंक
   दल: पिनाकी चक्रवर्ती, लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, दिनेश कुमार नायक, अमनदीप कौर
   उद्देश्य: यह परियोजना सरकारी संचालन और सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य सरकारों के बीच सहकर्मी से सहकर्मी सीखने और अनुभव साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

2. **महामारी के बाद बजट प्रबंधन: उप-राष्ट्रीय स्तर पर बजट विश्वसनीयता के अनुभव से सीखना। मार्च 20021**
   प्रायोजक: एनआईपीएफपी
   दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह

उद्देश्य: वर्तमान में व्याप्त आर्थिक संकट और राजस्व की कमी को देखते हुए, महामारी के बाद के बजट प्रबंधन के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से, कुशलतापूर्वक और पारदर्शी रूप से सुरक्षित और उपयोग करना आवश्यक है। योजना के अनुसार बजट को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप खर्च की प्राथमिकताओं में बदलाव हो सकता है, घाटे के लक्ष्य से अधिक हो सकता है, और महत्वपूर्ण सेवा वितरण वादों पर समझौता हो सकता है। यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक गहरी आर्थिक मंदी ने सरकारी वित्त को तनाव में डाल दिया है। यह पेपर नियोजित गतिविधियों को लागू करने और राजकोषीय तनाव का जवाब देने की उनकी क्षमता की व्याख्या करने के लिए भारत में राज्यों की बजट विश्वसनीयता का आकलन करता है। यह बेहतर सेवा वितरण और विकास के लिए वित्तीय साधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

3 कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन

S. No.	Title	Organized by	Date and Venue
1	माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार ने 'नौकरियां, विकास और स्थिरता: भारत की वसूली के लिए एक नया सामाजिक अनुबंध' पर सीईईडब्ल्यू-एनआईपीएफपी रिपोर्ट लॉन्च की।	एनआईपीएफपी और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित	11 जून 2020, नई दिल्ली
2	'भारत का आर्थिक एजेंडा कोविड और पोस्ट कोविड' पर आधा दिवसीय संगोष्ठी (डॉ. रथिन रॉय)	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनआईपीएफपी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया	19 जून 2020, नई दिल्ली
3	पांचवां पांच-संस्थान बजट संगोष्ठी 2021: 'द COVID-19 बजट: केंद्रीय बजट 2021-22 को अनपैक करना'	पांच संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित: सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ, एनसीएईआर और एनआईपीएफपी	8 फरवरी 2021 ज़ूम पर
4	'पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर वेबिनार: निरंतरता, परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता का विश्लेषण'	एनआईपीएफपी और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित	10 मार्च 2021 नई दिल्ली
5	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर वेबिनार: पोस्ट कोविड राजकोषीय वास्तुकला और FRBM'	एनआईपीएफपी और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित	15 मार्च 2021 नई दिल्ली
6	आर्थिक सिद्धांत और नीति पर दो दिवसीय 2021 वेब सम्मेलन	समन्वयक: एनआईपीएफपी के डॉ रुद्रानी भट्टाचार्य	30-31 मार्च 2021 नई दिल्ली
7	कर विवाद समाधान पर राष्ट्रमंडल से कर प्रशासकों के दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए आयोजित	समन्वयक: डॉ सुरांजलि टंडन	10-11 मार्च 2021 (ऑनलाइन)

8	भारत में स्थायी वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के साथ गोलमेज बैठक आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए आयोजित	समन्वयक: डॉ सुरांजलि टंडन	23 फरवरी 2021। एनआईपीएफपी (ऑनलाइन)
9	'सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड -19' पर एक गोलमेज सम्मेलन का सह-आयोजन किया आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए आयोजित	समन्वयक: डॉ सुरांजलि टंडन (जलवायु परिवर्तन पर ग्रंथम अनुसंधान संस्थान - एलएसई, जलवायु बांड पहल और पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से)	22 अक्टूबर 2020 एनआईपीएफपी (ऑनलाइन)

4 प्रशिक्षण कार्यक्रम

S.No.	Title	Day and Date	Venue	Programme/ Co-ordinator
1.	भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन ऑफ़लाइन)	सोमवार, 1 फरवरी 2021 - शुक्रवार 12 फरवरी 2021	एनआईपीएफपी	अमेय सप्रे
2.	भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन ऑफ़लाइन)	सोमवार, 8 फरवरी- शुक्रवार, 12 फरवरी 2021	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य
3.	विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवाँ पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन) (ऑनलाइन)	सोमवार, 22 फरवरी - शुक्रवार, 5 मार्च 2021	वेबिनार	अमेय सप्रे

5 प्रकाशन और संचार

संस्थान का द्वि-वार्षिक न्यूज़लेटर जनवरी 2020 और जुलाई 2020 में प्रकाशित हुआ था। इन न्यूज़लेटर्स में परियोजनाओं, संकाय गतिविधियों और घटनाओं पर अपडेट शामिल थे। जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के अंक तैयार किए जा रहे हैं और 2021 में प्रकाशित होने के लिए निर्धारित हैं। एनआईपीएफपी के अनुसंधान संकाय और उनके सहयोगियों द्वारा लिखित कुल 34 कार्य पत्र एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत प्रकाशित किए गए थे। रिपोर्टिंग वर्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 47 ब्लॉग लेख प्रकाशित हुए। ब्लॉग यहां उपलब्ध है। http://nipfp.org.in/blog/ प्रकाशन इकाई संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करने का कार्य भी करती है: http://www.nipfp.org.in

ट्विटर पर एनआईपीएफपी के सोशल मीडिया अकाउंट, @nipfp_org, का प्रभावी ढंग से उपयोग अपने शोध कार्य और घटना की जानकारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति मंडलों में प्रसारित करने के लिए किया गया।

संस्थान के प्रसार प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, अकादमिक पेपर व्यापक रूप से हितधारकों के बीच वितरित किए गए, हालांकि वेबसाइट अपडेट और ईमेलर्स। (एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर्स की सूची के लिए अनुलग्नक II, मूल्य प्रकाशनों के लिए अनुलग्नक V और संकाय प्रकाशित सामग्री के लिए अनुलग्नक VI देखें)।

6 पुस्तकालय और सूचना केंद्र

एनआईपीएफपी पुस्तकालय और सूचना केंद्र सार्वजनिक वित्त और नीति के क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय नीति, सूक्ष्म और मैक्रोइकॉनॉमिक्स, उद्योग अध्ययन, योजना और विकास, आर्थिक सिद्धांत और कार्यप्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर समृद्ध संसाधन सामग्री के साथ एक शोध पुस्तकालय है। , पर्यावरण और प्राकृतिक अर्थशास्त्र, शहरी अर्थशास्त्र और शहरी वित्त, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, संघवाद और विकेंद्रीकरण।

पुस्तकालय तीन मंजिलों में फैला हुआ है और इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ पर्याप्त जगह है। पाठकों का क्षेत्र दैनिक पत्रिकाओं, अध्ययन डेस्क और वाईफाई सुविधाओं की सुविधाओं के साथ-साथ पाठकों को पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। पुस्तकालय समारोह और सेवा के सभी परिचालन पहलुओं को एक एकीकृत जावाबीन (ईजेबी) आधारित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज यानी लिबसिस-7.0 का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

पुस्तकालय सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और शनिवार को सुबह 9.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक कार्यात्मक रहता है।

पुस्तकालय संग्रह

इसमें 65,788 से अधिक पुस्तकें और अन्य दस्तावेज हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, पुस्तकालय ने अपने संग्रह में 129 नए दस्तावेज़ और अन्य संस्थानों के 10 वर्किंग पेपर जोड़े, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाज दोनों के प्रकाशनों का एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। पुस्तकालय को आईएमएफ डिपॉजिटरी प्रोग्राम के तहत दो नए प्रकाशन और भारत की जनगणना, डेटा स्रोत आदि पर 10 सीडी-रोम भी प्राप्त हुए।

पुस्तकालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दस्तावेजीकरण ब्यूरो (आईबीएफडी) से विभिन्न प्रकाशनों तक पहुंच के लिए ई-सदस्यता भी ली है। इस सदस्यता के माध्यम से, संस्थान ने अपने संकायों और शोधकर्ताओं को ई-पत्रिकाओं, ई-पुस्तकों, ग्लोबल टैक्स एक्सप्लोरर कॉम्पैक्ट प्लस (ऑनलाइन) की एक आकाशगंगा के माध्यम से एक समृद्ध सुविधा प्रदान की है।

जर्नल्स

पुस्तकालय निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता पत्रिकाओं, डेटाबेस और अन्य ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, प्राप्त करता है और उनका रखरखाव करता है।

विशेष	कुल संख्या
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं	31
राष्ट्रीय पत्रिकाएं	45
पत्रिका	16

निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता के तहत जर्नल: 1. अमेरिकी आर्थिक संघ 2. लोक प्रशासन के लिए अमेरिकन सोसायटी 3. वित्तीय अध्ययन संस्थान 4. सार्वजनिक वित के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान	12
निम्नलिखित ऑनलाइन डेटाबेस के तहत जर्नल: 1. विज्ञान प्रत्यक्ष: अर्थशास्त्र, अर्थमिति और वित्त बंडल 2. OUP ऑनलाइन आर्थिक जर्नल बंडल संग्रह 3. JSTOR (बिजनेस कलेक्शन I और II) 4. पूर्ण पाठ संस्करण के साथ एकॉनलाइट 5. स्टाटा जर्नल	3418

अखबार और पत्रिकाएं

क्रमांक	राष्ट्रीय समाचार पत्र	प्रिंट / ऑनलाइन
1.	बिज़नेस लाइन	छाप
2.	बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड + वॉल स्ट्रीट जर्नल	छाप ऑनलाइन
3.	इकोनॉमिक टाइम्स	छाप
4.	रोजगार समाचार	छाप
5.	वित्तीय एक्सप्रेस	छाप
6.	इंडियन एक्सप्रेस	छाप
7.	मिंट	छाप
8.	नवभारत टाइम्स (हिंदी)	छाप
9.	टेलीग्राफ (कोलकाता संस्करण)	छाप
10.	हिन्दू	ऑनलाइन
1 1	हिंदुस्तान टाइम्स	छाप
12.	द स्टेट्समैन	छाप
13.	टाइम्स ऑफ इंडिया	छाप
	अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र	
1.	फाइनेंसियल टाइम्स	ऑनलाइन

ई- संसाधन

ई-जर्नल्स डेटाबेस

क्र.सं.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1.	ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन आर्थिक जर्नल बंडल संग्रह	http://www.oxfordjournals.org	आईपी आधारित
2.	JSTOR (बिजनेस कलेक्शन I और II)	http://www.jstor.org	आईपी आधारित
3.	एल्सेवियर: साइंस डायरेक्ट जर्नल्स: इकोनॉमिक्स, अर्थमितीय और वित्त विषय बंडल	http://www.sciencedirect.com	आईपी आधारित
4.	पूर्ण पाठ के साथ एकॉनलाइट	http://www.search.ebscohost.com	आईपी आधारित

ई-डेटाबेस

Sl.No.	Name of the Database	Web-Link	Mode of Accessibility
क्र.सं.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1.	ओईसीडी कराधान पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
2.	ओईसीडी अर्थशास्त्र आईलाइब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
3.	ओईसीडी गवर्नेंस आईलाइब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
4.	आईबीएफडी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन	http://www.ibfd.org	यूजर आईडी/पासवर्ड आधारित एक्सेस (5 यूजर्स तक)
5.	आईएमएफ पुस्तकालय	http://www.elibrary.imf.org	आईपी आधारित
6.	स्टाटा जर्नल	http://www.stata-journal.com	पीडीएफ उपलब्ध
7.	EPWRF इंडिया टाइम सीरीज़	http://www.epwrfits.in	आईपी आधारित
8.	सीईपीआर (चर्चा पत्र)	http://www.cepr.org	(चयनित के लिए उपयोगकर्ता)
9.	अंतर्राष्ट्रीय कराधान	http://www.internationaltaxation.taxmann.com	यूज़र आईडी/ पासवर्ड आधारित एक्सेस
10.	मनुपात्रा (डीईए परियोजना के तहत)	www.manupatra.com	यूज़र आईडी / पासवर्ड आधारित एक्सेस

कॉर्पोरेट डेटाबेस

Sl.No.	Name of the Database	Web-Link	Mode of Accessibility
क्र.सं.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1.	सीएमआईई: आर्थिक आउटलुक	http://www. Economicoutlook.cmie.com	आईपी आधारित
2.	सीएमआईई: प्रोवेसआईक्यू	http://www.prowess.cmie.com	आईपी आधारित
3.	सीएमआईई: कैपेक्स	http://www.capex.cmie.com	आईपी आधारित

ई-बुक्स डेटाबेस

क्र.सं.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1.	एडवर्ड एल्गर ई-किताबें	https://www.elgaronline.com/browse?access=user&level=parent	आईपी आधारित
2.	**अर्थशास्त्र पर स्प्रिंगर ई-पुस्तकें विषय बंडल	http://www.link.springer.com	आईपी आधारित

ध्यान दें:**यह स्प्रिंगर डेटाबेस 2016 से बंद कर दिया गया था और इसकी पहुंच 2005 से 2015 तक ही उपलब्ध है।

वर्तमान जागरूकता सेवा

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए दस्तावेज़, लेख, समाचार पत्र लेख नियमित रूप से डेटाबेस में जोड़े जा रहे हैं और प्रकाशित बुलेटिन के रूप में जारी किए जा रहे हैं:

- आर्टिकल अलर्ट सर्विस (अखबार की कतरनों का नवीनतम परिवर्धन)
- करंट अवेयरनेस सर्विस (पुस्तकों का नवीनतम परिवर्धन)

- वर्तमान सामग्री सेवा (पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं की सामग्री पृष्ठों के लिए एक मासिक बुलेटिन)
- बजट पूर्व और बाद का विशेष बुलेटिन

पुस्तकालय एनआईपीएफपी संकाय सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से करंट अवेयरनेस सर्विस - ग्रंथ सूची सेवा और संदर्भ सेवा के साथ-साथ बुक अलर्ट और आर्टिकल अलर्ट भी प्रदान करता है।

संसाधन के बंटवारे

एनआईपीएफपी पुस्तकालय व्यापक संसाधन साझाकरण और दस्तावेज़ वितरण सेवा के लिए विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) के साथ सदस्यता रखता है। वर्ष के दौरान, पुस्तकालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुस्तकालयों से 27 दस्तावेज उधार लिए और 25 दस्तावेज समान प्रतिष्ठित पुस्तकालयों को अंतर-पुस्तकालय संसाधनों के व्यापक प्रसार के लिए उधार दिए। वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 44 बाहरी शोधार्थियों और नीति निर्माताओं ने पुस्तकालय का दौरा किया और इस तरह के समृद्ध संसाधनों से लाभान्वित हुए।

(REPEC) रेपेक (अर्थशास्त्र में शोध पत्र)

रेपेक अर्थशास्त्र और संबंधित विज्ञान में अनुसंधान के प्रसार को बढ़ाने के लिए 102 देशों में सैकड़ों वैश्विक स्वयंसेवकों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस परियोजना का केंद्र वर्किंग पेपर्स, जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स, बुक्स चैप्टर्स का एक ऑनलाइन विकेन्द्रीकृत ग्रंथ सूची डेटाबेस है, जो ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा बनाए रखा जाता है। एनआईपीएफपी पुस्तकालय ने संस्थान के वर्किंग पेपर्स के मेटाडेटा को अपलोड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषय भंडार आरईपीईसी (अर्थशास्त्र पर शोध पत्र) में भी भाग लिया है। 2020-21 के दौरान रेपेक में 34 वर्किंग पेपर अपलोड किए गए। एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर्स को 2,321 बार खोजा गया, एक्सेस किया गया और डाउनलोड किया गया और सार को विश्व स्तर पर 10,769 बार देखा गया।

रेपेक वर्किंग पेपर सीरीज़ 2020-2021 के एक्सेस स्टैटिस्टिक्स (डाउनलोड और अमूर्त दृश्य की संख्या, अप्रैल 2020-मार्च 2021)

महीना	डाउनलोड	सार दृश्य
2020-04	202	901
2020-05	172	781
2020-06	217	772
2020-07	160	732
2020-08	173	777
2020-09	197	871
2020-10	157	865
2020-11	237	921
2020-12	177	1067
2021-01	229	1022
2021-02	173	931

2021-03	227	1129
कुल	2321	10769

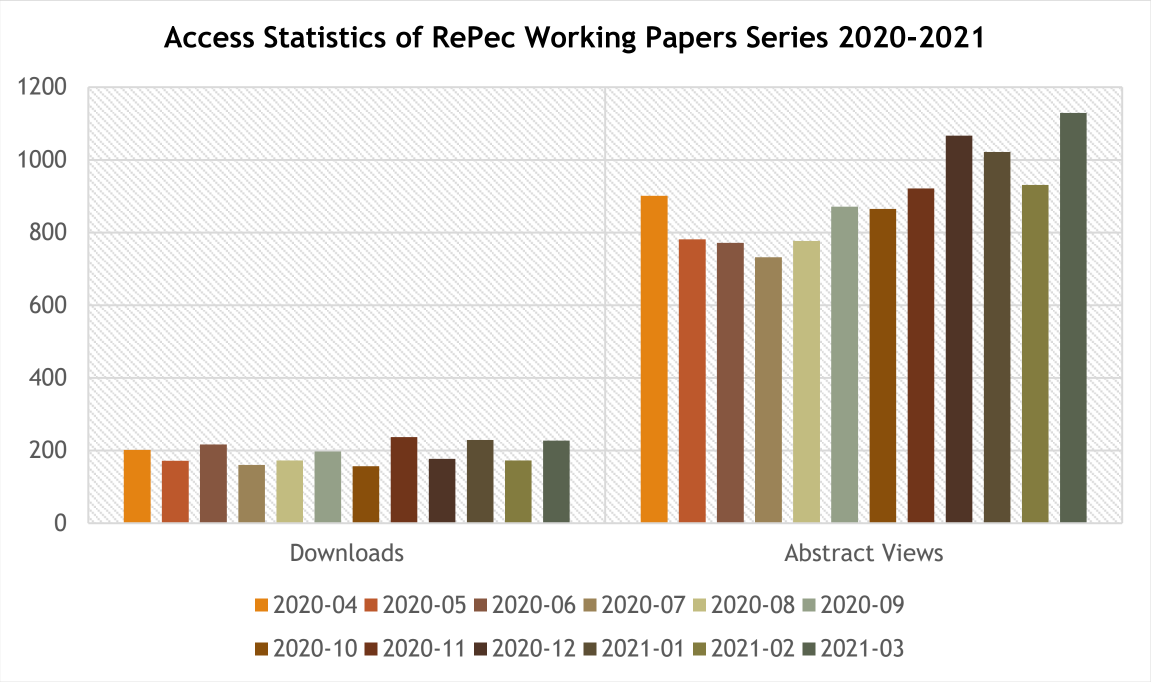

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि नवंबर 2020 में वर्किंग पेपर्स की अधिकतम संख्या – 237 – डाउनलोड की गई और मार्च 2021 में वर्किंग पेपर्स की अधिकतम संख्या – 1,129 – देखी गई।

रेप्रोग्राफिक सेवाएं

एनआईपीएफपी पुस्तकालय संकाय सदस्यों और बाहरी शोधार्थियों को पुस्तकालय संसाधन सामग्री की पारंपरिक रिप्रोग्राफिक सेवा प्रदान करता है। हमारे रिप्रोग्राफी रोस्टर की मुस्तैदी को उपयोगकर्ताओं ने स्वीकार किया है। वर्ष के दौरान उपयोगकर्ताओं को उनके शोध कार्य के लिए लगभग 3,000 पृष्ठों की फोटोकॉपी सामग्री प्रदान की गई। किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए एनआईपीएफपी लाइब्रेरी में रिप्रोग्राफिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

पुस्तकालय कर्मचारी गतिविधियाँ: 2020-2021

संगोष्ठी, सम्मेलन, संगोष्ठी, कांग्रेस

- सारिका गौर, ने 4 नवंबर 2020 को ऑनलाइन मोड में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (DELNET) की 28वीं एजीएम में भाग लिया।

कंप्यूटर केंद्र

एनआईपीएफपी का कंप्यूटर केंद्र अकादमिक बिरादरी के साथ-साथ संस्थान के अन्य पदाधिकारियों जैसे लेखा, प्रशासन, सभागार, पुस्तकालय और प्रकाशन और संचार को महत्वपूर्ण सहायता सेवा प्रदान करता है। कंप्यूटर केंद्र संकाय और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी पुरानी प्रणालियों को लगातार बदलता रहता है। एनआईपीएफपी परिसर पूरी तरह से वाईफाई सक्षम है। संस्थान की इंटरनेट सुविधा (nipfp.org.in) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा समर्थित है। वेबसाइट का प्रबंधन एक प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय और लेखा विभाग को नियमित संचालन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाता है। जबकि संस्थान के पुस्तकालय को LIBSYS और कौशल के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, लेखा विभाग के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए EX खाते और पेरोल सॉफ्टवेयर प्रदान किए जाते हैं। कम्प्यूटर केन्द्र कम्प्यूटर समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये समग्र नीति मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है।

संकाय गतिविधियों के मुख्य बिंदु

पिनाकी चक्रवर्ती

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

– एनआईपीएफपी में 1 फरवरी 2021 को भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन व्याख्यान दिया ।

– एनआईपीएफपी में भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कोविड के संदर्भ में उभरते वित्तीय मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 2021।

– एनआईपीएफपी में भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय संघवाद: सिद्धांत, भारतीय परिप्रेक्ष्य और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें' पर एक व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 2021

– राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी-प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान दिए। पहला 'पब्लिक डेट सस्टेनेबिलिटी एंड एफआरबीएम' और दूसरा 'पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें: मुद्दे और निहितार्थ' पर था। 12 फरवरी 2021।

– विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान दिए। 25 फरवरी और 3 मार्च 2021।

– विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन व्याख्यान (ऑनलाइन) दिया। 5 मार्च 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

– अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई द्वारा आयोजित तीसरे विश्व सांख्यिकी दिवस में 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-दुनिया को जोड़ना' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 20 अक्टूबर 2020।

– सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (सीटीआरपीएफपी), कोलकाता द्वारा पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों के वाणिज्यिक कर अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यशाला में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। 3 दिसंबर 2020।

– वित्तीय नीति संस्थान, कर्नाटक द्वारा आयोजित कर्नाटक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'महामारी के समय में राज्य वित्त' पर एक विशेष और विशिष्ट व्याख्यान ऑनलाइन देने के लिए आमंत्रित किया। 29 दिसंबर 2020।

- अर्थशास्त्र विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा आयोजित विलियम मेयर बंदोबस्ती संगोष्ठी, 2020-21 के लिए 'राज्य वित्त' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 8 जनवरी 2021।
- पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और आगामी बजट' पर एक वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 25 जनवरी 2021।
- संसदीय अनुसंधान और लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE), लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में 'बजट और प्रत्यक्ष कर के सामान्य प्रावधान' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 1 फरवरी 2021।
- केरल सरकार द्वारा आयोजित 'केरल लुक्स अहेड' नामक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'संघवाद और विकास वित्तपोषण' पर एक सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 फरवरी 2021।
- बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बजट के बाद की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 फरवरी 2021
- पुणे इंटरनेशनल सेंटर, पुणे द्वारा आयोजित 'केंद्रीय बजट 2021-22' पर एक पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 6 फरवरी 2021
- सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही (पीईएफए) द्वारा आयोजित '21वीं सदी में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन: बेहतर नीति निर्माण के लिए डेटा का दोहन' पर एक ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व बैंक द्वारा पीएफएम पर वैश्विक रिपोर्ट के शुभारंभ पर एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। सचिवालय। 24 फरवरी 2021
- यूनिसेफ द्वारा आयोजित बजट 2021-22 पर एक वेबिनार में 'पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें और राज्यों के वित्त के लिए इसके निहितार्थ' की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 मार्च 2021
- विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय NITI द्वारा आयोजित 'सतत प्रभाव के लिए एम एंड ई प्रथाओं को संस्थागत बनाना' विषय पर 'निगरानी, मूल्यांकन और सीखने' पर दो दिवसीय आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन में 'परिणाम-आधारित बजट' पर एक सत्र में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। आयोग। 18 मार्च 2021।
- रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन' पर एक पाठ्यक्रम में 'वित्तीय प्रबंधन - चुनौतियां और अवसर' पर एक ऑनलाइन वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया। 22 मार्च 2021।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- कोविड-19 के प्रभाव और राज्य के वित्त पर लॉकडाउन के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए 'राज्य वित्त: स्थिरता और विकास पर प्रभाव' पर एक वेबिनार में पैनलिस्ट। वेबिनार की मेजबानी ब्रिकवर्क रेटिंग्स, मुंबई ने की। 11 नवंबर 2020
- ईएसी-पीएम को प्रस्तुति। 11 दिसंबर 2020।
- माननीय उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष 'जीएसटी के राजस्व प्रभाव का विश्लेषण' रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रस्तुति। 16 दिसंबर 2020 (डॉ सच्चिदानंद मुखर्जी के साथ)।

- नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर प्रमुख थिंक टैंकों के साथ चर्चा में भाग लिया। 9 फरवरी 2021।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और अन्य संगठनों के लिए किए गए विविध अनुसंधान/सलाहकार गतिविधियां

- मार्च 2021 (आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय) में इसके सदस्य सचिव के अनुरोध पर सरकार द्वारा नियुक्त FRBM अधिनियम संशोधन समिति के लिए संदर्भ की शर्तों की समीक्षा की गई और उन पर टिप्पणी की गई। समिति को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए संभावित वित्तीय समायोजन पथ पर एक विस्तृत पेपर प्रस्तुत किया गया था।
- संस्थान के संकाय सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए देय हिस्से पर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा की, और टिप्पणियों को गृह मंत्रालय के साथ साझा किया गया था।
- एनआईपीएफपी से लोक ऋण प्रबंधन के निष्पादन लेखापरीक्षा पर मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, डॉ. प्रताप रंजन जेना और डॉ. मनीष गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से एक नोट तैयार किया गया था और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजा गया था।
- संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र द्वारा आयोजित 'बजट और प्रत्यक्ष कर के सामान्य प्रावधान' पर एक पैनल चर्चा में विचार प्रस्तुत किए। 1 फरवरी 2021।
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर संसद सदस्यों को संबोधित किया। 17 मार्च 2021।

रथिन रॉय

आमंत्रित व्याख्यान

- 'राजकोषीय और मौद्रिक प्रतिक्रिया: कितना क्षमता उपलब्ध है?' पर एक सत्र में ऑनलाइन पैनलिस्ट माइंडमाइन इंस्टीट्यूट, हीरो एंटरप्राइजेज द्वारा आयोजित। 27 अप्रैल 2020। अन्य वक्ता थे: शेरीन भान, प्रबंध संपादक, सीएनबीसी-टीवी18, डॉ दुव्वुरी सुब्बाराव, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, डॉ प्राची मिश्रा, प्रबंध निदेशक, ग्लोबल मैक्रो रिसर्च और चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट, गोल्डमैन सैक्स और सुनील कांत मुंजाल। , अध्यक्ष हीरो एंटरप्राइजेज।
- UNESCAP दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020' पर एक नीति संवाद में ऑनलाइन पैनलिस्ट। 13 मई 2020।

- फिक्की द्वारा आयोजित 'द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द न्यू नॉर्मल: राइजिंग टू द चैलेंज' पर फिक्की केएएस वर्चुअल डायलॉग्स की न्यू नॉर्मल सीरीज में तीसरे डायलॉग के प्रख्यात वक्ता। 15 मई 2020।
- नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु द्वारा आयोजित 'समकालीन भारत की कोविड-19 राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 16 मई 2020।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सीआईआई वार्षिक सम्मेलन 2020 में पूर्ण सत्र 'गेटिंग ग्रोथ बैक' में विशेष भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 जून 2020।
- भारत में असमानता से संबंधित मुद्दों पर विचार मंथन में भाग लिया, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, नई दिल्ली, 16 जून 2022 द्वारा आयोजित कोविड -19 के संदर्भ में।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'इंडियाज इकोनॉमिक एजेंडा कोविड एंड पोस्ट कोविड' नामक सम्मेलन में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 19 जून 2020।
- भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी-प्रशिक्षु बैच और दो भूटानी राजनयिकों के 2019 बैच के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारतीय अर्थव्यवस्था आगे देख रहे हैं, विशेष रूप से एक पोस्ट-कोविड वर्ल्ड' विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र में एक ऑनलाइन वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (एसएसआईएफएस), नई दिल्ली द्वारा आयोजित। 3 जुलाई 2020।
- भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई द्वारा आयोजित "सीईओ पैनल: 7वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव" में ऑनलाइन भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 10-11 जुलाई 2020।
- जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'रिवाइविंग इंडियाज इकोनॉमी - व्हाट द गुड डॉक्टर्स से' पर एक वेबिनार में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 14 जुलाई 2020।
- दूसरे चरण के आईएएस अधिकारियों के 2018 बैच के लिए 'कोविड से संबंधित व्यवधान के मद्देनजर अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार और तत्काल उपाय' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 16 जुलाई 2020।
- यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित 'एक पोस्ट कोविड-19 यूके इकोनॉमी' पर एक वेबिनार में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 22 जुलाई 2020
- एसोचैम द्वारा आयोजित 'आर्थिक दृष्टिकोण: महामारी के बाद' पर एक विशेष भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। 25 जुलाई 2020। चर्चा में समग्र वृहद-आर्थिक स्थिति, समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति और मांग पक्ष के उपाय, आत्मनिर्भरता- आत्मानिर्भर भारत, निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति और प्रमुख क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों सहित प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया।
- सीईईडब्ल्यू सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (सीईईडब्ल्यू-सीईएफ) द्वारा आयोजित 'रिफाइनेंसिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन' पर चर्चा करने के लिए एक वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 29 जुलाई 2020। वेबिनार में 'आरई-फाइनेंसिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड पीरियड सब्सिडाइज्ड क्रेडिट एन्हांसमेंट फॉर डोमेस्टिक आरई बॉन्ड' शीर्षक से अक्षय ऊर्जा के लिए सब्सिडी वाले क्रेडिट एन्हांसमेंट डिज़ाइन स्टडी पर सीईईडब्ल्यू-सीईएफ की रिपोर्ट लॉन्च की गई। आभासी

घटना ने भारत में ऊर्जा संक्रमण के वित्तपोषण के लिए आवश्यक प्रमुख जोखिमों और महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला।

- पुणे इंटरनेशनल सेंटर, पुणे द्वारा आयोजित 'भारत - आर्थिक नीति निर्माण और विकास पोस्ट-कोविड' पर भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम के साथ बातचीत सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया। 5 अगस्त 2020।
- जीडीपी वृद्धि, केंद्र और राज्यों की कर उछाल, जीएसटी मुआवजा, राजस्व घाटा अनुदान और वित्तीय समेकन पर अंतिम चर्चा के लिए पंद्रहवीं वित्त आयोग सलाहकार परिषद की बैठक में भाग लिया। 5 सितंबर 2020।
- इकोनॉमिक्स सोसाइटी, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक स्पीकर समिट में 'भारतीय मैक्रो इकोनॉमिक्स की राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 15 सितंबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- 'कोविड आफ्टरमैथ: कैन सस्टेनेबल फाइनेंस हेल्प इंडिया शेप ए ग्रीन एंड इनक्लूसिव रिकवरी?' नामक वेबिनार में एक ऑनलाइन चर्चा में भाग लिया। 19 अगस्त 2020 (ऑनलाइन)
- विल्टन बैठक में ऑनलाइन भाग लिया, 'यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण'। 26 अगस्त 2020

एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित कार्यशाला/सेमिनार/बैठकें/सम्मेलन

- माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार ने 'नौकरियां, विकास और स्थिरता: भारत की वसूली के लिए एक नया सामाजिक अनुबंध' पर सीईईडब्ल्यू-एनआईपीएफपी रिपोर्ट का शुभारंभ किया। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 11 जून 2020।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से 'इंडियाज इकोनॉमिक एजेंडा कोविड एंड पोस्ट कोविड' पर आधे दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 19 जून 2020 (डॉ. रथिन रॉय)

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य, वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति;
- सदस्य, UNESCAP के लिए विशेषज्ञ समूह (एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण)।
- फेलो, कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ सोसाइटी।
- सदस्य, भारत सलाहकार समिति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) एक सतत वित्तीय प्रणाली की जांच।
- सदस्य, समावेशी विकास पर मेटा परिषद, विश्व आर्थिक मंच, जिनेवा।

- सदस्य, भारत में जैव विविधता वित्त पहल के लिए तकनीकी सलाहकार समूह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (8 मई 2015 से आगे)
- सदस्य, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) समीक्षा समिति आरआईएस में संकाय पदों और उनके वेतनमानों की व्यापक समीक्षा करने के लिए।
- सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष के ज्ञान/अनुसंधान पहल पर कोर ग्रुप कमेटी।
- सदस्य, अनुसंधान सलाहकार परिषद (आरएसी), आरआईएस।
- शहरीकरण सलाहकार बोर्ड, द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (IIHS), बैंगलोर।
- सदस्य, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज (एफएसडब्ल्यूजी) भारत से।
- सदस्य, सतत विकास पर 2017 उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) में भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNRs) तैयार करने के लिए टास्क फोर्स।
- सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) 'वित्तीय क्षेत्र' पर।
- मूल्यांकन निगरानी समिति (ईएमसी), विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग के अध्यक्ष।
- सदस्य, राष्ट्रीय संचालन समूह (एनएसजी) 'ज्ञान और अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्किंग और भागीदारी के लिए तंत्र' विकसित करने पर। यह "समवेश: नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक प्रस्ताव" का हिस्सा है।
- सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (26 सितंबर 2017 से 25 सितंबर 2019)।
- सदस्य, अग्रानुक्रम सलाहकार बोर्ड। मई 2018 आगे
- विशेष आमंत्रित, संचालन समिति, एसडीजी वित्तीय सुविधा, यूएनडीपी
- सदस्य, रोजगार पर टास्क फोर्स, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। 31 अगस्त 2019 तक।
- प्रतिष्ठित मानद प्रोफेसर, आईआईटी, कानपुर में आर्थिक विज्ञान विभाग (1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक दो साल की अवधि के लिए)।
- सदस्य, मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन परिषद, राजस्थान सरकार फरवरी 2020 से मार्च 2022 तक।
- सदस्य, 21 फरवरी 2020 से नीति आयोग की राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) परियोजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति।
- राज्य को फिर से खोलने और विशेष रूप से आर्थिक नीतियों पर सलाह देने में पंजाब सरकार की सहायता के लिए एक समिति के सदस्य।
- सदस्य, सलाहकार बोर्ड, नीति स्कूल, गीतम विश्वविद्यालय।

सरकार के लिए किए गए विविध अनुसंधान/सलाहकार गतिविधियां भारत का, वित्त मंत्रालय और अन्य संगठनों

- अप्रैल 2020 में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर टास्क फोर्स को डॉ रथिन रॉय और डॉ मनीष गुप्ता द्वारा समर्थन प्रदान किया गया ।

आर कविता राव

एनआईपीएफपी कार्यक्रम में व्याख्यान

- विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान में उभरते मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 22 फरवरी 2021।
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में कर नीति डिजाइन में चुनौतियां' पर व्याख्यान दिया। 12 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान, अप्रत्यक्ष कर - जीएसटी 'और' कराधान में मुद्दे ' दिया। क्रमशः 2 और 3 फरवरी 2021

आमंत्रित व्याख्यान

- 'भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर: क्या लॉकडाउन का प्रभाव खत्म हो गया है?' पर चर्चा में पैनलिस्ट सुनील मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 14 मार्च 2021।
- 'क्या भारत के ईंधन करों के सुधार इसकी आर्थिक सुधार का समर्थन कर सकते हैं?' विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) द्वारा आयोजित 'संकट में अवसर: ऊर्जा करों की भूमिका और भारत की हरित वसूली में प्रोत्साहन' पर एक वेबिनार में। 10 मार्च 2021।
- औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के संकाय के लिए औद्योगीकरण, कॉर्पोरेट क्षेत्र और विकास पर दो सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 'जीएसटी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए इसके प्रभाव' पर एक व्याख्यान दिया। 23 फरवरी 2021।
- प्रयास (एनर्जी ग्रुप), पुणे द्वारा आयोजित गिरीश संत मेमोरियल इवेंट 2021 के हिस्से के रूप में 'एनर्जी: टैक्सेस एंड ट्रांजिशन इन इंडिया' पर चर्चा में पैनलिस्ट। 10 फरवरी 2021।
- 18 दिसंबर 2020 को वैकल्पिक रणनीतियों पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और वर्किंग ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- पीएच.डी. के लिए बाहरी रेफरी। थीसिस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

इला पटनायक

आमंत्रित व्याख्यान

– इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा आयोजित 'फाइनेंसिंग डिजास्टर रेजिलिएशन' पर इंडक्शन लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 4 सितंबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- नीति आयोग द्वारा आयोजित 'भारत के माननीय प्रधान मंत्री के साथ बजट पूर्व परामर्श' पर एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया। 8 जनवरी 2021।
- इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज द्वारा आयोजित 'इंडियाज सेल्फ-रिलायंस: ओल्ड आइडिया या न्यू डायरेक्शन' पर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 10 दिसंबर 2020।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित 'कोविड -19 महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था: एक सतत और मजबूत वसूली की नीतियां' पर एक उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 16 अक्टूबर 2020।
- आईडीएफसी संस्थान द्वारा आयोजित 'भारत की पोस्ट कोविड -19 आर्थिक सुधार का आकलन' पर एक वेबिनार में वक्ता के रूप में भाग लिया। 12 अक्टूबर 2020।
- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'कोविड के बाद विश्व व्यवस्था बदलने' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 6 अगस्त 2020।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा आयोजित सत्रहवें भारत नीति फोरम में भाग लिया। 13-16 जुलाई 2020।
- भारतीय विदेशी विद्वानों और छात्रों के साथ 'एक आत्मानिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को किक-स्टार्टिंग' पर लाइव इंटरेक्टिव सत्र में भाग लिया। 23 मई 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- आधिकारिक मौद्रिक और वित्तीय संस्थान फोरम (OMFIF) के सलाहकार परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त - फरवरी 2021।

अजय शाह

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- सुनील अब्राहम, ArtEZ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस: टुवड्र्स ग्रेटर साइबर सॉवरिन्टी' नामक वेबिनार में एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया। 13 अगस्त 2020.
- आईडीएफसी संस्थान द्वारा आयोजित त्रैमासिक गोलमेज सम्मेलन में 'डिजिटल सार्वजनिक सामान और खेल के मैदान: सैद्धांतिक और प्रासंगिक विश्लेषण की आवश्यकता' पर एक आभासी सत्र में भाग लिया। 4-5 अगस्त 2020।
- द एस्या सेंटर और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के शासन के लिए सुधार प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए एक आभासी बहु-हितधारक विचार-मंथन सत्र में भाग लिया। 31 जुलाई 2020।
- 27 जुलाई 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित प्रो. कौशिक बसु, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा 'द महामारी एंड द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी: इंडियाज बिग अपॉर्चुनिटी एंड बिग रिस्क' पर एक वेब व्याख्यान में भाग लिया। .
- इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित 'डिजिटल हेल्थ रिकॉड्र्स एंड प्राइवेसी' पर वर्चुअल राउंडटेबल में भाग लिया। 27 जुलाई 2020।
- तक्षशिला संस्थान द्वारा आयोजित `रेगुलेटर्स: क्यों और कैसे' पर एक आभासी सत्र का आयोजन किया। 18 जुलाई 2020।
- लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी एंड प्रयास (एनर्जी ग्रुप) द्वारा आयोजित 'ग्रिड-स्केल बैटरी स्टोरेज: कॉस्ट्स, वैल्यू, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 8 जुलाई 2020।
- टीआईई पुणे द्वारा आयोजित 'व्हाई इज नॉट स्टिल ए इकोनॉमिक सुपरपावर एंड व्हेयर आर द ग्रीन शूट्स' पर भाग लिया और एक आभासी वार्ता दी। 8 जुलाई 2020।
- एक वेबिनार में एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया जिसमें डॉ. प्रद्युम्न भागवत, फ्लोरेंस स्कूल ऑफ रेगुलेशन, इटली ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित 'इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ: चॉइस एंड बैरियर' पर एक पेपर प्रस्तुत किया। 1 जुलाई 2020।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित ओईसीडी के रेगुलेटरी पॉलिसी डिवीजन में वरिष्ठ नीति विश्लेषक श्री डैनियल ट्रनका द्वारा 'ओईसीडी देशों में नियामक नीति और विनियमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 24 जून 2020।
- श्री एरिक थॉमसन, संस्थापक, लिफाफा अर्थशास्त्र, और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा आयोजित पूर्व ओईसीडी नियामक विशेषज्ञ द्वारा 'विनियमों के सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय प्रभाव के लागत-लाभ विश्लेषण' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 17 जून 2020।

- डॉ. नचिकेत मोर, विजिटिंग साइंटिस्ट, द बैनियन एकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ, द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 'पोस्ट-कोविड पब्लिक हेल्थ पॉलिसी चैलेंजेस' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 17 जून 2020।
- सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित 'डूइंग रिसर्च' पर इंटर्नशिप बैच से वर्चुअल बातचीत की। 7 जून 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- निदेशक मंडल, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी प्राइवेट लिमिटेड, 1993 से।
- निदेशक मंडल, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, 2006-2020।
- निदेशक मंडल, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2014 से।
- निदेशक मंडल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2017 से ।

एन.आर. भानुमूर्ति

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य, अगस्त 2019 से भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों को "वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज"पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव)।
- सदस्य, जून 2019 से ग्रामीण विकास मंत्रालय, निगरानी और मूल्यांकन पर उच्च स्तरीय सलाहकार समिति (अध्यक्ष: सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
- सदस्य, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए समिति - 2019 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए, अक्टूबर 2019 से (अध्यक्ष: डॉ नागेश सिंह)।
- सदस्य, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
- सदस्य, उप-राष्ट्रीय लेखा समिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जून 2018 से (अध्यक्ष: प्रो. रवींद्र एच. ढोलकिया)।
- सदस्य, गन्ना और चीनी उद्योग पर टास्क फोर्स, दिसंबर 2018 से नीति आयोग (अध्यक्ष: प्रो रमेश चंद)।
- सदस्य, विशेषज्ञों की स्थायी तकनीकी समिति, भारतीय एक्ज़िम बैंक।
- सदस्य, बोर्ड ऑफ इंडिया टुडे इकोनॉमिस्ट्स, 2017 से।
- सदस्य, शासी निकाय, उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स अकादमी, नई दिल्ली।
- सदस्य, संपादकीय सलाहकार बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक समसामयिक पत्र।
- जूरी सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अनुसंधान पुरस्कार - 2020, एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया।
- सदस्य, आरबीआई वार्षिक सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार - 2019 के लिए समिति, आरबीआई।

- सदस्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए ओडिशा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का पांचवां आम समीक्षा मिशन, नवंबर 2019।
- सदस्य, कर्नाटक के जीएसडीपी के आकलन के लिए समिति, कर्नाटक निगरानी प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार, सितंबर 2019 से (अध्यक्ष: प्रमुख सचिव, योजना)।
- सचिव, द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी।
- मैनेजिंग ट्रस्टी, द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट।

लेखा चक्रवर्ती

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सरकार के अर्थशास्त्र' और 'वित्तपोषण मानव विकास: लिंग बजट' पर व्याख्यान दिया। 8 और 9 फरवरी 2021

भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षाधीनों के लिए सार्वजनिक वित्त पर पाठ्यक्रम के लिए 'सरकार के अर्थशास्त्र' और 'वित्तपोषण मानव विकास: लिंग बजट' पर व्याख्यान दिया। 9 और 11 फरवरी 2021

विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत' और 'मानव विकास के लिए कोविड समय में वित्तीय चुनौतियां' पर व्याख्यान दिया। 14 फरवरी और 1 मार्च 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- सेंट पॉल कॉलेज, एर्नाकुलम, केरल में 'कोविद 19 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता: वित्तीय और मौद्रिक प्रतिक्रिया' पर वेबिनार में अतिथि वक्ता। 6 मई 2020।
- 'वर्चुअल डायलॉग्स: द न्यू नॉर्मल सीरीज़' में पैनलिस्ट; डायलॉग टू: द न्यू नॉर्मल एंड इवोल्यूशन इन जेंडर रोल्स - द जेंडर लेंस टू #COVID-19 'फिक्की में। 8 मई 2020
- टाटा स्टील में एक्सपर्ट स्पीक, 'मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी रिस्पॉन्स टू कोविड -19'। 18 मई 2020
- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन स्टडीज, तिरुवनंतपुरम में पैनलिस्ट, 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन और कोविड -19', केंद्र-राज्य संबंधों पर वेबिनार। 16 मई 2020।
- श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'कोविड -19 के आर्थिक परिणाम और पुनर्प्राप्ति का मार्ग' पर वेबिनार में अतिथि वक्ता। 13 अप्रैल 2020।
- शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'मौद्रिक और राजकोषीय नीति प्रतिक्रिया' पर वेबिनार में अतिथि वक्ता। 30 अप्रैल 2020।
- अच्युता मेनन सेंटर, त्रिशूर, केरल में 'लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव' पर वेबिनार में अतिथि वक्ता। 5 जून 2020।

- आत्मानिर्भर भारत: एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी में 'स्टार्ट अप के लिए सरकारी पहल' पर वेबिनार। दिल्ली, 29 अगस्त 2020।
- मैक्रोइकॉनॉमिक्स में जेंडर को एकीकृत करना - पूजा मेहरा भाग I और भाग II के साथ पॉडकास्ट, 8 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2020। हर रोज अर्थशास्त्र, पॉडकास्ट।
- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बैंकिंग शिखर सम्मेलन में 'महामारी के लिए केंद्रीय बैंक नीति प्रतिक्रिया' पर अतिथि वक्ता। 10 अक्टूबर 2020।
- नीरमन (एक नागरिक समाज संगठन), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'कार्यक्रम मूल्यांकन में लिंग का एकीकरण' पर वेब वार्ता। https://neeerman.co.in 19 नवंबर 2020,
- गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे में 'पब्लिक इकोनॉमिक्स' पर एक मॉड्यूल / कोर्स दिया। 3-7 नवंबर 2020।
- कनाडा के उच्चायोग, नई दिल्ली के राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक मामलों के प्रभाग द्वारा आयोजित 'आर्थिक महामारी पैकेज - मौद्रिक और राजकोषीय - भारत और कनाडा' में आमंत्रित वक्ता। 17 नवंबर 2020।
- लोक अर्थशास्त्र पर अतिथि वक्ता: अर्थशास्त्र और अनुसंधान केंद्र के स्नातकोत्तर विभाग, महाराजा महिला कॉलेज, तिरुवनंतपुरम में प्रेरण कार्यक्रम में। 18 नवंबर 2020
- सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी, लॉ एंड पॉलिसी (सी-हेल्प), इंडियन लॉ सोसाइटीज लॉ कॉलेज, पुणे में 'जेंडर बजटिंग: लीगल फ्रेमवर्क एंड हेल्थ सेक्टर' पर वर्चुअल मीटिंग। 20 नवंबर 2020।
- 'महामारी और लैंगिक असमानता की स्थिति के लिए मौद्रिक-राजकोषीय नीति प्रतिक्रिया'। इंपैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएमपीआरआई) में वेब पॉलिसी टॉक और स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट। 21 नवंबर 2020।
- कैनेडियन इंटरनेशनल सेंटर, टोरंटो और मंक स्कूल के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक वेब पैनल में 'भारतीय वित्तीय संघवाद और महामारी के लिए मैक्रो-वित्तीय प्रतिक्रिया' पर पैनलिस्ट। 27 नवंबर 2020।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता- रेडियोसोफिया के लिए 'राजकोषीय नवाचार के रूप में जेंडर बजटिंग' पर पॉडकास्ट। 28 नवंबर 2020।
- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, तमिलनाडु सरकार और यूनिसेफ 'जेंडर बजटिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा' पर वेब सम्मेलन में अध्यक्ष। 2 दिसंबर 2020।
- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन स्टडीज, तिरुवनंतपुरम में 'राज्य वित्त 2020-21 पर आरबीआई अध्ययन' पर वेबिनार में वक्ता। 3 दिसंबर 2020,
- सामाजिक विज्ञान स्कूल, केरल के एसएसएस विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम में 'महामारी के समय में लैंगिक समानता के लिए सार्वजनिक नीति' पर वेबिनार में वक्ता। 14 दिसंबर 2020,
- बी.आर.अंबेडकर पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, पश्चिम बंगाल और यूनिसेफ द्वारा आयोजित एशिया पैसिफिक जेंडर बजटिंग पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में 'द फिलीपींस एंड कोरियन एक्सपेरिमेंट्स ऑन जेंडर बजटिंग: लीगल फिएट एंड फिस्कल विकेंद्रीकरण फ्रेमवर्क' पर पैनलिस्ट। 14 दिसंबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन (अतिथि व्याख्यान)

- अर्थशास्त्र विभाग, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र संगोष्ठी, इकनोविस्टा 2021 के अध्यक्ष के रूप में, 'भारत में पोस्ट-कोविड -19 विश्व: आर्थिक दृष्टिकोण और नीति चुनौतियां' विषय पर आमंत्रित किया गया। 16 अप्रैल 2021।
- 130वीं बीआर अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, क्लेमेंट टाउन, देहरादून द्वारा आयोजित 'जेंडर इन गवर्नेंस' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'शासन और लिंग बजट का नारीकरण' पर व्याख्यान दिया। 15 अप्रैल 2021।
- हार्वर्ड लॉ स्कूल ह्यूमन राइट्स क्लिनिक के विद्वानों के साथ 'जलवायु परिवर्तन और पानी की पहुंच विशेष रूप से महिलाओं के लिए और बजटीय प्रक्रियाओं' पर 12 अप्रैल 2021 को एक वार्ता दी।
- बंगाल इकोनॉमिक एसोसिएशन के इकतालीसवें वार्षिक सम्मेलन - बंगिया अर्थनीति परिषद में उद्घाटन भाषण दिया। 25 मार्च 2021।
- पंजाब विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 'केंद्रीय बजट 2021' पर व्याख्यान देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 26 मार्च 2021।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 'राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जेंडर बजटिंग' पर व्याख्यान देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 24 मार्च 2021।
- श्रम मंत्रालय के साथ समन्वय में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 'कोविड -19 और भारत के श्रम बाजार पर इसके प्रभाव' पर व्याख्यान देने के लिए अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 26 मार्च 2021।
- साइंस पीओ, पेरिस द्वारा 'भारत और रवांडा में तुलनात्मक लिंग बजट नीतियों' पर अतिथि व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 9 अप्रैल 2021।
- अहमदाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'चुनौतीपूर्ण समय में अर्थशास्त्र' पर एक सम्मेलन में ईएसी-पीएम की आशिमा गोयल के साथ 'समष्टि अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त' पर सत्र में पैनलिस्ट। 6 मार्च 2021।
- अर्थशास्त्र विभाग, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, शारदा विश्वविद्यालय, दिल्ली एनसीआर द्वारा 'जेंडर बजटिंग और महिला कार्यबल भागीदारी के मैक्रोइकॉनॉमिक्स' पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 20 मार्च 2021।
- बिट्स पिलानी द्वारा बिट्स हैदराबाद कैंपस में 'केंद्रीय बजट 2021 और उच्च घाटे की प्रभावशीलता' पर अतिथि व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 11 मार्च 2021।
- एमिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता द्वारा 'केंद्रीय बजट 2021 और वित्तीय प्रोत्साहन' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 मार्च 2021।
- गवर्नमेंट कॉलेज, क्यूपेम, गोवा के छात्रों को 'केंद्रीय बजट 2021 और वित्तीय प्रोत्साहन' पर अतिथि व्याख्यान दिया। 27 फरवरी 2021।

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के रूप में जेंडर बजटिंग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला में 'जेंडर बजटिंग: जवाबदेही के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन उपकरण' पर समापन व्याख्यान दिया। 5 फरवरी 2021।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर द्वारा 'अर्थव्यवस्था और केंद्रीय बजट 2021' पर अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 20 फरवरी 2021।
- महात्मा गांधी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित 'आर्थिक प्रोत्साहन और केंद्रीय बजट 2021' पर एक राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य भाषण दिया। 20 फरवरी 2021।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - मानव संसाधन विकास केंद्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, FIP2021 के लिए "आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज - मौद्रिक और वित्तीय" पर व्याख्यान दिया। 17 फरवरी 2021।
- स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के छात्रों के लिए 'आर्थिक प्रोत्साहन: केंद्रीय बजट 2021' पर एक व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 2021।
- लेडी डोक कॉलेज, मदुरै, तमिलनाडु के छात्रों के लिए 'उच्च राजकोषीय घाटा: केंद्रीय बजट 2021' पर एक वार्ता दी। 12 फरवरी 2021।
- केरल विश्वविद्यालय के श्री नारायण कॉलेज कोल्लम के छात्रों के लिए 'केंद्रीय बजट 2021' पर एक भाषण दिया। 10 फरवरी 2021।
- सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पुणे के छात्रों के लिए 'केंद्रीय बजट 2021' पर एक भाषण दिया। 11 फरवरी 2021।
- सिटीजन फोरम इंडिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बजट 2021' पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया। 6 फरवरी 2021।
- बजट पूर्व चर्चा पैनल में भाग लिया `क्या बजट 2021-22 स्लाइडिंग भारतीय अर्थव्यवस्था को गिरफ्तार कर सकता है? अर्थशास्त्र विभाग, क्राइस्ट कॉलेज, बेंगलुरु द्वारा आयोजित मुद्दे, रणनीतियाँ और आशा'। 29 जनवरी 2021।
- भारतीय उद्योग परिसंघ और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स द्वारा आयोजित 'केंद्रीय बजट 2021 के मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क' पर एक वार्ता दी। 2 फरवरी 2021।
- मुंबई में अर्थशास्त्र के छात्रों, द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) द्वारा आयोजित आर्थिक न्याय सम्मेलन (ईजेसीओएन) में 'महामारी के समय में व्यापक असमानताओं के लिए व्यापक आर्थिक नीति प्रतिक्रिया' पर उद्घाटन व्याख्यान दिया। 29 जनवरी 2021।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पुणे द्वारा आयोजित 'जेंडर बजटिंग और कोविड -19 नीति प्रतिक्रिया' पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में व्याख्यान दिया। . 21 जनवरी 2021।
- मद्रास विश्वविद्यालय में सर विलियम मेयर एंडॉमेंट 2021 व्याख्यान ऑनलाइन में 'सार्वजनिक वित्त और वित्तीय संघवाद' पर विशेष व्याख्यान दिया गया। 8 जनवरी 2021।
- केरल सरकार के वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा में भाग लिया। 1 फरवरी 2021।

– अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान स्कूल, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के छात्रों के लिए 'महामारी के समय में लैंगिक समानता के लिए सार्वजनिक नीति' पर एक व्याख्यान दिया। 14 दिसंबर 2020।
– मंक स्कूल, टोरंटो विश्वविद्यालय और सीआईसी (नागरिकता और आप्रवासन कनाडा) टोरंटो द्वारा आयोजित 'द इंडियन इकोनॉमी' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 27 नवंबर 2020
– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'पब्लिक फाइनेंस, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज' शीर्षक से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की 76वीं कांग्रेस में 'क्लाइमेट चेंज-एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्स इन इंडिया' शीर्षक से एक पेपर (सह-लेखक अमनदीप कौर के साथ) प्रस्तुत किया गया। आइसलैंड, रेकजाविक (ऑनलाइन)। 19-21 अगस्त 2020।
– द्वारा आयोजित 'पब्लिक फाइनेंस, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज' शीर्षक से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की 76वीं कांग्रेस में 'भारत में प्राकृतिक संसाधन कराधान-उछाल' शीर्षक से एक ऑनलाइन पेपर (सह-लेखक इमैनुएल थॉमस और पीयूष गांधी के साथ) प्रस्तुत किया। आइसलैंड विश्वविद्यालय, रेकजाविक। 19-21 अगस्त 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

– सदस्य, चयन समिति, शास्त्री इंडो-कैनेडियन फेलोशिप, 2020 के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए।
– राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे में प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य। 2020
– संपादकीय बोर्ड, नेशनल अर्बन जर्नल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली। 2020।
– सदस्य, गवर्निंग बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जर्मनी। 2020

सब्यसाची कर

आमंत्रित व्याख्यान

– 27 फरवरी 2021 को रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, बेलूर मठ द्वारा आयोजित अर्थोबिशलेशोन वार्षिक कार्यशाला में 'विकास प्रकरण और मंदी' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– स्क्रॉल.इन, द पॉलिटिकल फिक्स से रोहन वेंकटरामकृष्णन द्वारा साक्षात्कार। 18 सितंबर 2020
(https://thepoliticalfix.substack.com/p/friday-q-and-a-sabyasachi-kar-on?utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy)
– मनीकंट्रोल डॉट कॉम, द मैक्रो मिनट्स पॉडकास्ट से अरूप रॉयचौधरी द्वारा साक्षात्कार। 24 दिसंबर 2020 (https://www.moneycontrol.com/news/podcast/macro-minutes-podcast-rbi- should-be-allowed-to-monetize-the-most-productive-part-of-the-deficit-sabyasachi-kar- 6268091.html)

– एडलवाइस इन्फिनिटी, कैल्म एलोकेटर सीरीज से अंकिता पाठक द्वारा साक्षात्कार। 2 फरवरी 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=cUjbxu3YOGc)

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

– सह-संपादक, जर्नल ऑफ साउथ एशियन डेवलपमेंट, सेज पब्लिकेशन्स।
– एसोसिएट एडिटर, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यू, एमराल्ड पब्लिशिंग।
– दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध नेहखोलेन हाओकिप की पीएचडी पर्यवेक्षण।
– जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र से संबद्ध जगदीश साहू का पीएचडी पर्यवेक्षण।
– सीएनबीसी टीवी18 में पैनलिस्ट भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के कार्यवृत्त पर चर्चा। 23 अक्टूबर 2020।
– मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर CNBC TV18 चर्चा में पैनलिस्ट, 1 मार्च 2021।
– मानद विजिटिंग फेलो, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम।
– रिसर्च पार्टनर, ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी डायनेमिक्स रिसर्च नेटवर्क, किंग्स कॉलेज, यूनाइटेड किंगडम।
– आजीवन सदस्य, भारतीय अर्थमितीय सोसायटी।

प्रताप रंजन जेना

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

– भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 3 फरवरी 2021।
– भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही - पीएफएम प्रदर्शन मापन ढांचा' पर व्याख्यान दिया। 5 फरवरी 2021
– भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में समकालीन सार्वजनिक व्यय प्रबंधन प्रणाली' पर व्याख्यान दिया। 9 फरवरी 2021।
– विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 24 फरवरी 2021

आमंत्रित व्याख्यान

- 'सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा' पर सर्टिफिकेट कोर्स में 'भारत में समकालीन सार्वजनिक वित्त' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 29 अगस्त 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य, नीति निर्माण समिति, संवर्ग प्रशिक्षण योजना के समन्वय और कार्यान्वयन व्यवस्था, लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
- सदस्य, ज्ञान केंद्र समिति - सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और अन्य संगठनों के लिए किए गए विविध अनुसंधान/सलाहकार गतिविधियां

- अक्टूबर 2020 में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के प्रदर्शन लेखा परीक्षा पर मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा का अनुरोध किया। रिपोर्ट की समीक्षा की गई और एक नोट के रूप में टिप्पणियां प्रदान की गईं। (डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, डॉ. प्रताप रंजन जेना और डॉ. मनीष गुप्ता)।

मीता चौधरी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में स्वास्थ्य देखभाल वित्त पोषण में सार्वजनिक नीति मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 10 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में स्वास्थ्य देखभाल वित्त पोषण में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 2021
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में स्वास्थ्य देखभाल वित्त पोषण में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 1 मार्च 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, नीति अनुसंधान केंद्र और आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित 'एनीमिया मुक्त भारत के लिए वित्तीय दक्षता बढ़ाने: सबक और अवसर' पर एक वेबिनार के लिए एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। 27 नवंबर 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के विशेषज्ञ समूह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सच्चिदानंद मुखर्जी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान के सिद्धांत और सिद्धांत' और 'वस्तु और सेवा कर' पर दो व्याख्यान दिए। 23 फरवरी 2021।
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) की उभरती चुनौतियों' पर व्याख्यान दिया। 11 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान के सिद्धांत और सिद्धांत' और 'राज्य कर में मुद्दे' पर दो व्याख्यान दिए। 1 और 2 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, (एएससीआई)-आरबीआई प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज में 'व्यापार और पर्यावरण' पर एक व्याख्यान दिया। 10 फरवरी 2021।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में 'केंद्रीय बजट 2021-22' पर व्याख्यान दिया। 4 फरवरी 2021।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में 'अर्थव्यवस्था की स्थिति: केंद्रीय बजट 2021' पर एक संगोष्ठी में 'माल और सेवा कर के राजकोषीय निहितार्थ' पर एक भाषण दिया। 11 मार्च 2021।

एचके अमरनाथ

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्त में डेटा और अनुभवजन्य मुद्दों' पर व्याख्यान दिया। 3 मार्च 2021।
- राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान, 'व्यय का वर्गीकरण' और 'सार्वजनिक वित्त डेटाबेस' दिया। 10 फरवरी 2020।

– भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्त डेटाबेस: भारत में बजट की एक समझ' पर एक व्याख्यान दिया। 12 फरवरी 2020।

आमंत्रित व्याख्यान

– इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड मैनेजमेंट, गाजियाबाद द्वारा आयोजित 'भारतीय संविधान के तहत केंद्र-राज्य संबंध' पर एक राष्ट्रीय वेबिनार में 'संवैधानिक प्रावधान, इक्विटी और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में मुद्दे: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' पर एक व्याख्यान दिया। 20 जून 2020।

रेणुका साने

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

– सार्वजनिक वित्त के चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए 'विनियम एवं बाजार विफलता' विषय पर व्याख्यान दिया। 3 मार्च 2021।

– भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'क्रेडिट बाजार' और 'बाजार की विफलता' पर दो व्याख्यान दिए। 11 फरवरी 2020।

– भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बाजार की विफलता और सरकार की भूमिका' पर व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

– स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ एंड मार्केट रेगुलेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के सहयोग से आयोजित रेगुलेटरी गवर्नेंस पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 'सार्वजनिक नीति और विनियमन के अर्थशास्त्र' और 'नियामक अनुपालन और प्रवर्तन' पर दो व्याख्यान दिए। भारतीय नियामकों का मंच। क्रमशः 20 फरवरी और 27 मार्च 2021।

– इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड द्वारा आयोजित 'ग्रामीण भारत के लिए एक लिंग समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण' सत्र के लिए पैनलिस्ट 10 मार्च 2021।

– दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'दक्षिण एशियाई आर्थिक विकास' पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा कर रहे थे। 26 फरवरी 2021।

– इंडिया वर्चुअल सेमिनार में 'IBC-क्रॉस बॉर्डर, पर्सनल इन्सॉल्वेंसी, ग्रुप इन्सॉल्वेंसी' पर सत्र के लिए पैनलिस्ट: INSOL इंटरनेशनल (एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोफेशनल्स, द्वारा आयोजित भारत पोस्ट कोविड -19 में दिवाला संकल्प,) भारत। 25 फरवरी 2021।

- इंडिया इकोनॉमिक फोरम, स्कोच ग्रुप द्वारा आयोजित 'उपभोग और ऋण' पर चर्चा में पैनलिस्ट। 20 फरवरी 2021।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में आयोजित 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेशक शिक्षा और संरक्षण' पर तीसरी कार्यशाला में चर्चा करते हुए। 17 फरवरी 2021। https://youtu.be/aUWh8kCSqSg।
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के 2019 बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 फरवरी 2021 को 'व्यक्तिगत दिवाला एवं दिवालियापन' विषय पर व्याख्यान दिया।
- स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा आयोजित यूजीसी-स्ट्राइड के बैनर तले 'रैंडमाइज्ड कंट्रोल टेक्निक्स' पर एक सत्र में व्याख्यान दिया। 6 फरवरी 2021।
- 2020 के दूसरे ग्रेजुएट इन्सॉल्वेंसी प्रोग्राम बैच के लिए 'नए सिरे से शुरू प्रक्रिया पर गोलमेज सम्मेलन' में पैनलिस्ट। 6 फरवरी 2021।
- चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान (CFAI), सिंगापुर द्वारा आयोजित पेंशन की स्थिति पर एशिया प्रशांत और क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ऑनलाइन कार्यक्रम में पैनलिस्ट। 19 जनवरी 2021।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित 'डिजिटल युग में उभरते नियामक मुद्दे' संगोष्ठी में 'विकास और आर्थिक संकट में नियामकों की भूमिका' विषय पर चर्चा की। 15 जनवरी 2021।
- कार्नेगी इंडिया के वर्चुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में 'हेल्थ स्टैक' पर एक पैनल पर चर्चा की। 18 दिसंबर 2020।
- वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (SPJIMR), मुंबई के सहयोग से फाइनेंस रिसर्च ग्रुप (अब xKDR फोरम) द्वारा आयोजित इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में 'हाउ हैव कोर्ट्स डील विद कंज्यूमर फाइनेंस डिस्प्यूट्स' नामक एक पेपर प्रस्तुत किया। 16 दिसंबर 2020।
- फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 'भारतीय नियामकों में प्रवर्तन में मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 28 नवंबर 2020।
- आईडीएफसी संस्थान द्वारा आयोजित 'डेटा पारदर्शिता और जवाबदेही' पर वर्चुअल राउंडटेबल में 'एक सक्षम राज्य का निर्माण' शीर्षक सत्र में चर्चा। 12 नवंबर 2020।
- 'हमें नियमन की आवश्यकता क्यों है?' विषय पर व्याख्यान दिया। फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में। 28 नवंबर 2020।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग (डीएमएस) में 'भारत में पेंशन सुधार' पर व्याख्यान दिया। 10 अक्टूबर 2020।
- 'भारत में पेंशन' पर चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान वेबिनार में 'महामारी में पेंशन' पर एक वार्ता दी। 9 अक्टूबर 2020।
- सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन इंडिया की छठी वार्षिक कार्यशाला में एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसका विषय था 'वित्तीय उत्पाद खरीद निर्णय पर सूचना का प्रभाव'। 8 जुलाई 2020।

- एनसीएईआर द्वारा आयोजित 'भारत में निवेशक शिक्षा में निवेश: कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं' विषय पर एक वेबिनार में बात की। 28 दिसंबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- चेन्नई गणितीय संस्थान के साथ 'सरकारी खरीद में आर्थिक मुद्दे' पर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 22 जनवरी 2021।
- 'उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के सीपीएचएस सर्वेक्षण डिजाइन' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 8, 15 और 22 जनवरी 2021।
- एक वेबिनार का आयोजन किया, 'बैकडोर्स टू एनक्रिप्शन: एक व्यवहार्य नीति समाधान?'। 11 दिसंबर 2020।
- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित 'वित्तीय बाजारों में केवाईसी के मुद्दे और भारत की एन्क्रिप्शन संबंधित नीतियां' पर एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया। 10 दिसंबर 2020।
- 10 दिसंबर 2020 को एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित 'भारतीय वित्तीय बाजारों में केवाईसी: इतिहास और आगे का रास्ता' पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया
- आईडीएफसी संस्थान द्वारा आयोजित 'एक सक्षम राज्य का निर्माण' के दूसरे सत्र के दौरान एक वेबिनार में भाग लिया - राज्य और संस्थागत क्षमता के सवालों पर केंद्रित वर्चुअल राउंडटेबल्स की एक श्रृंखला। 3 दिसंबर 2020।
- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित `2 रेजोल्यूशन इन इंडिया' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 12 नवंबर 2020।
- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित 'समथिंग टू कम्पलेन अबाउट: हाउ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स ओवरकम एथनिक डिफरेंसेज' विषय पर वेबिनार में भाग लिया, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी के सब्यसाची दास और लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के विमल बालासुब्रमण्यम ने चर्चा की। 5 नवंबर 2020।
- उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी) के चाड टोमकिन्स द्वारा 'शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण: सीएफपीबी अनुभव' पर वेबिनार में भाग लिया और चर्चा के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के संयुक्त सचिव श्री मनोज पांडेय ने भाग लिया। 15 अक्टूबर 2020।
- कट्स इंटरनेशनल के दीपक सक्सेना द्वारा 'अदालत के बाहर शिकायतों को संबोधित करना: ग्राहक सहायता केंद्र से सबक' और सृष्टि शर्मा द्वारा 'क्षेत्र से शिकायत निवारण पर नोट्स' पर वेबिनार में भाग लिया। 1 अक्टूबर 2020।
- वेबिनार में भाग लिया `भारतीय न्यायालयों ने उपभोक्ता वित्त विवादों से कैसे निपटा है?' करण गुलाटी द्वारा डॉ केपी कृष्णन, सलाहकार, एनसीएईआर के साथ चर्चाकर्ता के रूप में। 17 सितंबर 2020।
- मालविका राघवन, द्वारा रिसर्च द्वारा 'लेन-देन विफलताओं और आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों में निवारण - डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे के भीतर उपभोक्ताओं की सुरक्षा' पर वेबिनार में भाग लिया, और लंदन के क्वीन मैरी विश्वविद्यालय से विमल बालासुब्रमण्यम द्वारा 'ट्विटर फ़ीड का उपयोग कर ग्राहक शिकायतों का अनुमान' पर। . 3 सितंबर 2020।

- आर्टईज़ यूनिवर्सिटी के सुनील अब्राहम द्वारा 'यूपीआई: टुवड्र्स ग्रेटर साइबर सॉवरिन्टी' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। 13 अगस्त 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, नवंबर 2020 द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर गठित टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
- पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण की पेंशन सलाहकार समिति के सदस्य
- व्यक्तिगत दिवाला के कामकाज पर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड समिति के सदस्य।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और अन्य संगठनों के लिए किए गए विविध अनुसंधान/सलाहकार गतिविधियां

- 'डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण' पर एक वेब-आधारित टूलकिट के निर्माण में योगदान दिया। टूलकिट डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों का अवलोकन प्रदान करता है और नियामकों (नीति आयोग) के लिए एक ज्ञान संसाधन है।
-

मुकेश आनंद

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीवाश्म ईंधन की कीमतें: एक विकासशील अर्थव्यवस्था की सुधार दुविधा' पर व्याख्यान दिया गया। 2 मार्च 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पेंशन सुधारों में मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 9 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय और श्रम मुद्दों की बातचीत' पर व्याख्यान दिया। 9 फरवरी 2021।
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में वृद्धावस्था आय सहायता' पर व्याख्यान दिया। 11 फरवरी 2021।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य: भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए संस्थानों की पहचान करने और डोमेन केंद्रित क्षमता निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कार्य समूह।
- जर्नल रेफरी: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मैक्रोइकॉनॉमिक्स और वित्त, सर्वेक्षण, आरबीआई समसामयिक पत्र, विकास और परिवर्तन की समीक्षा।

मनीष गुप्ता

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान दिए - 'स्थानीय सरकार के वित्त में मुद्दे' और 'सरकारी ऋण में रुझान'। 10 फरवरी 2021।
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध' पर व्याख्यान दिया। 12 फरवरी 2021।
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान दिए - 'राज्य वित्त आयोग और स्थानीय सरकार' और 'राज्य वित्त में मुद्दे'। क्रमशः 26 फरवरी और 2 मार्च 2021।
- ऑनलाइन मोड में आयोजित यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिस्ट्स के 25वें वार्षिक सम्मेलन में 'फॉरेस्ट कवर: अलाइनिंग नेशनल एंड सबनेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन ए फेडरल सेटिंग' एक पेपर प्रस्तुत किया। 23 जून से 3 जुलाई 2020 तक।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और अन्य संगठनों के लिए किए गए विविध अनुसंधान/सलाहकार गतिविधियां

- अप्रैल 2020 में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर टास्क फोर्स को डॉ रथिन रॉय और डॉ मनीष गुप्ता द्वारा समर्थन प्रदान किया गया ।
- सितंबर 2020 में, गृह मंत्रालय ने संस्थान से मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अंतिम अध्ययन रिपोर्ट पर विचार/टिप्पणियां साझा करने का अनुरोध किया, जिसका शीर्षक था "स्टडी ऑन एस्टीमेटिंग द ड्यू शेयर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी"। अध्ययन की समीक्षा की और एक नोट के रूप में टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं (डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती और डॉ मनीष गुप्ता)।
- अक्टूबर 2020 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एनआईपीएफपी से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के निष्पादन लेखापरीक्षा पर मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करने का अनुरोध किया। रिपोर्ट की समीक्षा की गई और एक नोट के रूप में टिप्पणियां प्रदान की गईं। (डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, डॉ. प्रताप रंजन जेना और डॉ. मनीष गुप्ता)।

रुद्राणी भट्टाचार्य

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान दिए - 'महामारी के दौरान वृद्धि और मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी' और 'खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को स्थिर करना: मौद्रिक और संरचनात्मक नीतियों की भूमिका'। क्रमशः 4 फरवरी और 5 फरवरी 2021।
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'महामारी के दौरान आर्थिक प्रदर्शन और मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी' पर व्याख्यान दिया। 10 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में 'खाद्य मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति' पर बोलने के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया। 20 अक्टूबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- दो पत्रों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया - 'प्रवासन निर्णय-एजेंट-आधारित मॉडल दृष्टिकोण में निर्माण: यादृच्छिक वर्गीकरण का उपयोग करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए एक समीक्षा और संकल्पनात्मक मॉडल निर्माण' और 'विकासशील अर्थव्यवस्था में मजदूरी असमानता पर एफडीआई प्रभाव: एक सैद्धांतिक विश्लेषण' छठे स्थान पर दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई आर्थिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्रमशः 25 फरवरी और 26 फरवरी 2021।
- अर्थव्यवस्था की एनसीएईआर मिड-ईयर रिव्यू में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। 21 दिसंबर 2020।
- `भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को एकीकृत करने में ई-एनएएम कितना प्रभावी है? एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित आर्थिक सिद्धांत और नीति सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया । 30 मार्च 2021।
- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित आर्थिक सिद्धांत और नीति सम्मेलन में 'निर्मित वस्तुओं में इंट्रा-इंडस्ट्री ट्रेड: ए केस ऑफ इंडिया' पर एक पेपर पर चर्चा की। 31 मार्च 2021।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- वर्तमान में अगस्त, 2019 से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के तहत थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011-12) की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के कार्य समूह के सदस्य।

- पत्रिकाओं के लिए समीक्षक के रूप में आमंत्रित - आर्थिक मॉडलिंग, यूरेशियन आर्थिक समीक्षा, भारतीय विकास और विकास समीक्षा, भारत समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, एशियाई अर्थशास्त्र के जर्नल, मात्रात्मक अर्थशास्त्र के जर्नल, उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मैक्रोइकॉनॉमिक्स और वित्त, आरबीआई समसामयिक पत्र

एनआईपीएफपी (कार्यक्रम समन्वयक) द्वारा आयोजित कार्यशाला/सेमिनार/बैठकें/सम्मेलन

- एनआईपीएफपी द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित आर्थिक सिद्धांत और नीति सम्मेलन, 30-31 मार्च 2021।
- सरकार और अन्य संगठनों के लिए एनआईपीएफपी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भारतीय आर्थिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 8-12 फरवरी 2021, एक आभासी मंच पर एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित। समन्वयक: रुद्रानी भट्टाचार्य
-

सुकन्या बोस

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बुनियादी शिक्षा और सार्वजनिक नीति' पर ऑनलाइन व्याख्यान। 1 मार्च 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शिक्षा के अधिकार के वित्तपोषण' पर ऑनलाइन व्याख्यान। 8 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नई शिक्षा नीति, 2020 पर एक परिप्रेक्ष्य' पर ऑनलाइन व्याख्यान। 9 फरवरी 2021
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्कूल शिक्षा और एनईपी, 2020' पर ऑनलाइन व्याख्यान। 11 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- शिक्षा का अधिकार मंच द्वारा आयोजित 'शिक्षा और केंद्रीय बजट 2021-22' पर वेबिनार में वक्ता। 5 फरवरी 2021।
- शिक्षा का अधिकार मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका शिक्षा पर नीतिगत संक्षिप्त विमोचन पर वेबिनार में वक्ता। 22 जनवरी 2021।
- शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा आयोजित 'एसडीजी4 की स्थिति' पर वेबिनार के लिए 'वित्तपोषण शिक्षा' पर पैनलिस्ट। 22 दिसंबर 2021।

- शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा 'शिक्षा के अधिकार का वित्तपोषण: पंद्रहवें वित्त आयोग की भूमिका' पर एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। 13 अक्टूबर 2021।
- एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित 'एजुकेशन राउंड टेबल ऑन फाइनेंसिंग एजुकेशन' पर पैनलिस्ट। 18 अगस्त 2020।
-

अमेय सप्रे

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'छाया अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं और मापन' पर व्याख्यान दिया। 8 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल बातें' पर व्याख्यान दिया। 11 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीडीपी अनुमान, अवधारणा और संशोधन' पर व्याख्यान दिया। 11 फरवरी 2021
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का परिचय' पर एक व्याख्यान दिया। 23 फरवरी 2021।
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'छाया अर्थव्यवस्था का अनुमान' पर व्याख्यान दिया। 26 फरवरी 2021।
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कर चोरी, एक खेल सैद्धांतिक दृष्टिकोण' पर एक व्याख्यान दिया। 4 मार्च 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली में 'बचत पहेली: भारत में बचत दर में गिरावट' पर व्याख्यान। 20 जनवरी 2021।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के आकलन में मुद्दे' पर व्याख्यान। 25 नवंबर 2020।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में 'औद्योगिक सांख्यिकी' पर व्याख्यान। 25 नवंबर 2020।
- भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय लेखा: अनुमान में मुद्दे' पर व्याख्यान। 24 नवंबर 2020।

- भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीडीपी संशोधन' पर व्याख्यान। 19 नवंबर 2020।
- भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय लेखा में अनुसंधान मुद्दे' पर दो व्याख्यान। 15 और 18 जून, 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षाधीनों, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी एनएसएसटीए का परियोजना मूल्यांकन। अक्टूबर 2020
-

सुरांजलि टंडन

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर' पर व्याख्यान दिया। 3 फरवरी 2021।
- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में प्रत्यक्ष कर नीति' पर व्याख्यान दिया। 2 फरवरी 2021
- भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में प्रत्यक्ष कर नीति' पर व्याख्यान दिया। 9 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

- Universidad Torcuato Di Tella, अर्जेंटीना द्वारा आयोजित वैश्विक कर वार्ता में 'अंतर्राष्ट्रीय कराधान पोस्ट कोविड -19' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 7 अक्टूबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के तहत कराधान: केयर्न एनर्जी बनाम भारत पर एक गोलमेज सम्मेलन' के लिए पैनलिस्ट। 25 मार्च 2021।
- 'कर विवाद समाधान' पर राष्ट्रमंडल से कर प्रशासकों के दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। 10-11 मार्च 2021।
- 'भारत में सतत वित्त' पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। 23 फरवरी 2021।
- सीडीसी यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित जस्ट ट्रांजिशन सम्मेलन में पैनलिस्ट। 19 जनवरी 2021।
- यूसी लोवेन द्वारा आयोजित वैश्विक कर संगोष्ठी में पैनलिस्ट। 10 दिसंबर 2020।

– ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट-एलएसई, क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से 'सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट-कोविड -19' पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 22 अक्टूबर 2020 (आर्थिक मामलों का विभाग)।

एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित कार्यशाला/सेमिनार/बैठकें/सम्मेलन

– 'कर विवाद समाधान' पर राष्ट्रमंडल से कर प्रशासकों के दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। 10-11 मार्च 2021।
– 'भारत में सतत वित्त' पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। 23 फरवरी 2021।
– ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट-एलएसई, क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से 'सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट-कोविड -19' पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 22 अक्टूबर 2020 (आर्थिक मामलों का विभाग)।

सतद्रु सिकदर

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

– विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक वित्त में चौदहवें पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सब्सिडी की अवधारणा और मापन' पर व्याख्यान। 2 मार्च 2021।
– भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'केंद्र सरकार और 14 प्रमुख भारतीय राज्यों की बजट सब्सिडी' पर व्याख्यान। 9 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

– शुक्रवार को स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'बजट की अवधारणा: केंद्रीय बजट 2021-22 पर एक फोकस' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 19 फरवरी 2021।
– शारदा विश्वविद्यालय के बिजनेस स्टडीज स्कूल में 'केंद्रीय बजट और सार्वजनिक नीति प्रतिबिंब' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 6 फरवरी 2021।
– इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग पर सर्टिफिकेट कोर्स में 'सार्वजनिक राजस्व और कराधान' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 9 सितंबर 2020 (सुबह और शाम के बैच)।
– महेस्तला कॉलेज, महेस्तला, पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित 'द नोवेल कोरोनावायरस एंड द इंडियन इकोनॉमी: इंप्लिकेशंस ऑन इनफॉर्मल एंड माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया' पर एक वेबिनार में 'महामारी

के दौरान रिवर्स माइग्रेशन: अंडरटेकन पब्लिक पॉलिसीज का स्नैपशॉट' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 31 अगस्त 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– एएस कॉलेज, खन्ना, पंजाब द्वारा आयोजित 'कोविड-19 एंड रिवर्स माइग्रेशन इन इंडिया' पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 'रिवर्स माइग्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज' पर व्याख्यान दिया । 29 जून 2020।

रंजन कुमार मोहंती

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स और द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'वर्तमान मुद्दों और वित्तीय बाजारों में नीति विकल्प' पर दो दिवसीय वेब-आधारित शोध संगोष्ठी में भाग लिया। 26-27 अगस्त 2020।

– इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छठे IGC-ISI समर स्कूल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भाग लिया। 12-15 जुलाई 2020।

दिनेश कुमार नायक

आमंत्रित व्याख्यान

– आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) और केवी कॉलेज कांताबंजी, संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 'युवाओं के अकादमिक रोजगार पर कोविड -19 के प्रभाव' पर एक वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया। 6 अक्टूबर 2020।

– अंचल कॉलेज, पदमपुर, संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय वेबिनार में 'भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर कोविड महामारी के प्रभाव' पर एक वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया। 12 सितंबर 2020।

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छठे IGC-ISI समर स्कूल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भाग लिया। 12-15 जुलाई 2020।

– वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, एशिया में वित्तीय शिक्षा और एशियाई विकास बैंक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वैश्विक वित्तीय चक्र पर विकास और चुनौतियों पर पाठ्यक्रमों में भाग लिया। 18-21 मई 2020।
– संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रस्तावित एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक डिजाइन करने पर पांच सप्ताह के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। 14 अप्रैल 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

– सदस्य, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ (भारत)
– सदस्य, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था संघ
– सदस्य, द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी
– सदस्य, द इंडियन सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स (आईएनएसईई)
– सदस्य, विकास और पर्यावरण अर्थशास्त्र के लिए दक्षिण एशियाई नेटवर्क
– समीक्षक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर (आईआईएमबी) प्रबंधन समीक्षा

श्री हरि नायडू

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना और गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पर आयोजित एक सम्मेलन में 'सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स के निर्धारक: उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मामला' एक पेपर प्रस्तुत किया। और कराधान (गिफ्ट), तिरुवनंतपुरम। 27 और 28 मार्च 2021।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

– सदस्य, राष्ट्रीय कर संघ (एनटीए), संयुक्त राज्य।

भाबेश हजारिका

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा निर्देशित इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर द्वारा आयोजित छठे IGC-ISI समर स्कूल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भाग लिया। 9-12 जुलाई 2020।

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

- एक पांडुलिपि की समीक्षा की, 'औपचारिक और अनौपचारिक समर्थन और नई शुरुआत का प्रदर्शन: अप: एक क्वांटाइल रिग्रेशन विश्लेषण' जर्नल: यूरेशियन बिजनेस रिव्यू (स्प्रिंगर)
- एक पांडुलिपि की समीक्षा की, 'स्वास्थ्य देखभाल उपयोग, स्वास्थ्य व्यय, और दक्षिण कोरिया में अपूर्ण आवश्यकता पर गरीबी की स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव' जर्नल: पर्यावरण अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (एमडीपीआई):

अमनदीप कौर

भागीदारी/बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

– आइसलैंड विश्वविद्यालय, रेकजाविक द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (ऑनलाइन) की 76 वीं वार्षिक कांग्रेस में 'भारत में जलवायु परिवर्तन व्यय और आर्थिक विकास लिंक: एक अनुभवजन्य विश्लेषण' शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया। 19-21 अगस्त 2020।

रीता पांडे

सरकार और अन्य निकायों/पत्रिकाओं में सदस्यता

– जैविक संसाधनों तक पहुंच और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सदस्य । 2020।

राधिका पांडेय

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

– भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो व्याख्यान - 'पैसे की मांग और आपूर्ति' और 'पूंजीगत खाता उदारीकरण'। 3 फरवरी और 5 फरवरी 2021।

आमंत्रित व्याख्यान

– 'भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले नीतिगत ढांचे और विनियमों' पर व्याख्यान देने के लिए राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान द्वारा अतिथि संकाय के रूप में आमंत्रित किया गया था। 21 जनवरी 2021।
– इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा 'रोजगार परिदृश्य, नीति और आत्मनिर्भर पैकेज के बीच महामारी: प्रभाव, चुनौतियां और आगे का रास्ता' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1 दिसंबर 2020।

अनुलग्नक

अनुलग्नक I: अध्ययनों की सूची 2020-21

अध्ययन पूर्ण

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रोजगार सृजन पर अध्ययन दिसंबर 2018 - सितंबर 2020	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार	एनआर भानुमूर्ति, भाबेश हजारिका, दिनेश कुमार नायक, कनिका गुप्ता, तन्वी ब्रम्हे, अशोक भाकर
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के स्थानिक नियोजन घटक के कार्यान्वयन के लिए कानूनी विचारों का अध्ययन (29 जनवरी 2021 - 30 मार्च 2021)	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD)	इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, करण गुलाटी
3	वर्ष 2017-18 के लिए सिक्किम सरकार द्वारा राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा (दिसंबर 2020 से जून 2021)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना सतद्रु सिकदर
4	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखा परीक्षा (दिसंबर 27, 2019 - 30 जुलाई, 2020)	केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।	सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला और विभा कुमारी
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए जीएसटी का राजस्व प्रभाव (6 जुलाई, 2020 - 25 फरवरी, 2021)	व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय पहलू: भविष्य के लिए प्रभाव और सीख (जनवरी 2019 से जुलाई 2020)	नीति आयोग	मीता चौधरी और रंजन कुमार मोहंती
7	दीपम में विनिवेश की प्रक्रिया पर शोध (30 सितंबर 2020)	निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग	रेणुका साने सुदीप्तो बनर्जी सृष्टि शर्मा कार्तिक सुरेश
8	फिजिकल स्टैम्पिंग और ई-स्टाम्पिंग की वर्तमान प्रणाली की जांच और उसमें सुधार के उपाय सुझाएं (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
9	निजी निवेश पर कोविड-19 के प्रभाव का प्रारंभिक आकलन (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
10	चीनी संप्रभु डिजिटल मुद्रा पर नोट (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
1 1	वर्तमान पेंशन योजनाओं का आकलन (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
12	संबंधित कानून के मसौदे (2021) सहित क्रिप्टो मुद्रा संबंधी मामलों के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान करना	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
13	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) का मूल्यांकन (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
14	मुद्रास्फीति के प्रमुख कारकों की जांच - अंशदायी दृष्टिकोण (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
15	फिनटेक और एमएसएमई फाइनेंसिंग (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
16	सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर नोट (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
17	वित्तीय बाजार प्रभाग और इसके संभावित प्रभाव से संबंधित घोषणाओं के साथ बजट 2021-22 के बाद बाजार प्रतिक्रिया पर नोट। (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
18	फिजिकल स्टैम्पिंग और ई-स्टाम्पिंग की वर्तमान प्रणाली की जांच और उसमें सुधार के उपाय सुझाएं (2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रो. सब्यसाची कर और डीईए टीम
19	इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश में पेंशन और बीमा पूल का उपयोग (जून 2020-मई 2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	सब्यसाची कर और मैक्रो-फाइनेंस समूह
20	विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए नई तकनीकें (जून 2020-मई 2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	सब्यसाची कर और मैक्रो-फाइनेंस समूह
21	सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं (जून 2020-मई 2021)	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय	सब्यसाची कर और मैक्रो-फाइनेंस समूह
22	एनआईपीएफपी-सीएजी अनुसंधान कार्यक्रम, (24 जून 2019 - 8 दिसंबर 2020)	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	इला पटनायक, राधिका पांडे, मेधा राजू, हरलीन कौर, रचना शर्मा
23	इथियोपिया में अंतर सरकारी वित्तीय संबंध "(प्रमाणन कार्यक्रम: NIPFP, भारत; फेडरेशन ऑफ फोरम, कनाडा; हाउस ऑफ फेडरेशन, इथियोपिया और मेल्स ज़नावी लीडरशिप अकादमी, इथियोपिया) – (2019-2020)	सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बीएमजीएफ	लेखा चक्रवर्ती और मनीष गुप्ता
24	राज्य के बजट 2018-19 का विश्लेषण: प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां (2019-20)	सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बीएमजीएफ	लेखा चक्रवर्ती मनीष गुप्ता और अमनदीप कौर
25	पोषण सार्वजनिक व्यय समीक्षा: गुजरात से साक्ष्य (2018 अगस्त -2020 दिसंबर)	सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बीएमजीएफ	अमनदीप कौर और लेखा चक्रवर्ती (रुजेल श्रेष्ठ, कोमल जैन, अनिंदिता घोष और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)
26	भारत में कोविड-19 और राजकोषीय-मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं (मार्च-दिसंबर, 2020)	स्व-आरंभ की गई परियोजना, दो पत्र प्रकाशित (अनुसंधान सहयोग)।	लेखा चक्रवर्ती और दिव्या रंगन
27	भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश के निर्धारक: अधिकतम एन्ट्रॉपी एन्सेम्बल" (अगस्त 2018-दिसंबर 2020)	स्व-आरंभ की गई परियोजना, (फोर्डहम विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क के साथ अनुसंधान सहयोग)।	लेखा चक्रवर्ती (फोर्डहम विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क के साथ अनुसंधान सहयोग)

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
28	जेंडर बजटिंग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था" (अगस्त 2019-दिसंबर 2020)	स्व-आरंभ की गई परियोजना, (अनुसंधान सहयोग	लेखा चक्रवर्ती (अनुसंधान सहयोग)
29	टीचिंग नोट: मल्टी लेवल गवर्नमेंट का सिद्धांत (2020)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	मुकेश आनंद और राहुल चक्रवर्ती
30	हिमाचल प्रदेश की जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (बीएसएपी) को अद्यतन करना और लाहौल-पांगी और किन्नौर परिदृश्य पर ध्यान देने के साथ बीएसएपी को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति तैयार करना (27 मार्च, 2021)	यूएनडीपी	रीता पांडे, रथिन रॉय, प्रिया यादव, अनुजा मल्होत्रा और गरिमा जसुजा
31	हिमाचल प्रदेश में लाहौल-पांगी और किन्नौर परिदृश्य के लिए जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना और वित्त समाधान (27 मार्च, 2021)	यूएनडीपी	रीता पांडे, रथिन रॉय, प्रिया यादव, अनुजा मल्होत्रा और गरिमा जसुजा
32	सिक्किम की जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (बीएसएपी) को अद्यतन करना और कंचनजंगा - ऊपरी तीस्ता घाटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीएसएपी को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति तैयार करना" (22 मार्च, 2021)	यूएनडीपी	रीता पांडे, रथिन रॉय, प्रिया यादव और अनुजा मल्होत्रा
33	भारतीय राज्यों के लिए कर प्रयास और दक्षता को मापना (नवंबर 2018 - अप्रैल 2020)	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	आर कविता राव, डीपी सेन गुप्ता, सच्चिदानंद मुखर्जी, सुरांजलि टंडन और श्री हरि नायडू
34	डिजिटलीकरण से कर चुनौतियां (31 मार्च, 2021)	एनआईपीएफपी	सुरांजलि टंडन
35	राज्यों के बजट के राज्य वित्त डेटा का अद्यतन: 2021-22 उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में संकाय के उपयोग के लिए सूचना का संकलन और मैक्रो टेबल बनाना। (1 अप्रैल 2020 - 30 जून 2020)	एनआईपीएफपी	रोहित दत्ता और अमर नाथ
36	संबंधित राज्यों के वित्त लेखा-2017-18 से सार्वजनिक वित्त सूचना का अद्यतनीकरण और इसे डिजिटल प्रारूप में संकाय के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना। (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्ण)।	एनआईपीएफपी	रोहित दत्ता और अमर नाथ
37	भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान: वेक्टर त्रुटि सुधार तंत्र बनाम। गैर-स्थिर समय श्रृंखला के लिए गतिशील कारक मॉडल दृष्टिकोण (सितंबर, 2019---सितंबर, 2020)	एनआईपीएफपी	रुद्रानी भट्टाचार्य और मिगांक्षी कपूर (बिट्स, पिलानी)

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
38	भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को एकीकृत करने में ई-एनएएम कितना प्रभावी है? प्याज बाजार से सबूत (अप्रैल, 2020--मार्च, 2021)	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य और सबरनी चौधरी
39	भारत की त्रैमासिक जीडीपी वृद्धि को देखते हुए: एक कारक-संवर्धित समय भिन्न प्रतिगमन गुणांक मॉडल (नवंबर 2019 - दिसंबर 2020)	एनआईपीएफपी और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर)	रुद्रानी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मुंडले (एनसीएईआर), बोर्नाली भंडारी (एनसीएईआर), और सबरनी चौधरी

चल रहे अध्ययन

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
1	केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राजस्व, व्यय और बजट आवंटन का आकलन (अप्रैल, 2019, मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत अक्टूबर, 2020)	गृह मंत्रालय	मीता चौधरी, अमेय सप्रे
2	गर्भवती महिला मजदूरों के बीच बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर सशर्त नकद हस्तांतरण का प्रभाव: मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, मध्य प्रदेश से साक्ष्य। (फरवरी 2020 और जून 2021)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश	भाबेश हजारिका, दिनेश कुमार नायक, एन.आर. भानुमूर्ति, कनिका गुप्ता, मनीष प्रसाद
3	मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम, 2017-18 और 2018-19 के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा (फरवरी 2021 से जून 2021)	मध्य प्रदेश सरकार	प्रताप आर. जेना
4	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई): डिजाइन रूपरेखा, उभरते पैटर्न और सरकार को लागत (अक्टूबर 2020 - अक्टूबर 2021)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए), भारत सरकार	मीता चौधरी,द्वीपोबोती ब्रह्मा और प्रीतम दत्ता
5	तमिलनाडु छठे राज्य वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे (दिसंबर 2020 से आगे))	छठा राज्य वित्त आयोग, तमिलनाडु सरकार	पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, संप्रीत कौर
6	भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी के लिए संशोधित नियमावली (जनवरी 2020 से अगस्त 2021) (MoF)	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग	अमर नाथ एचके, मनीष गुप्ता, श्रीहरि नायडू
7	अर्थव्यवस्था की स्थिति: ईएसी-पीएम को तिमाही मूल्यांकन और विकास आउटलुक रिपोर्ट (नवंबर, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक)	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी)	पिनाकी चक्रवर्ती, आर. कविता राव, लेखा चक्रवर्ती, सब्यसाची कर, पीआर जेना, मनीष गुप्ता, रुद्रानी भट्टाचार्य, अमेय सप्रे, दिनेश कुमार नायक, श्रुति त्रिपाठी
8	भारत में सार्वजनिक खरीद तंत्र: एल1 के लिए विकल्प तलाशना (फरवरी 2020 और जून 2021)	स्वयं पहल	भाबेश हजारिका, आयुषी जैन

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
9	भूमि बाजारों को बेहतर बनाना (8 अप्रैल 2019 - 31 दिसंबर 2021)	ओमिदयार नेटवर्क	इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, करण गुलाटी, विराज जोशी, विशाल त्रेहन, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सारंग मोहरीर, गुंटास कौर उप्पल, नमिता गोयल, आंशी शर्मा
10	न्याय चुनौती के लिए डेटा (दिसंबर 2020 - जून 2021)	वयम फोरम फॉर सिटिजनशिप	इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, करण गुलाटी
1 1	फार्मास्युटिकल दवाओं की सार्वजनिक खरीद और गुणवत्ता नियंत्रण पर एक अध्ययन, (जून 2020 - अप्रैल 2021)	ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, इंक।	इला पटनायक, हरलीन कौर, मधुर मेहता, आशिम कपूर, सिद्धार्थ श्रीवास्तव
12	'विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों' पर आईसीएसएसआर-एमएचए परियोजना के लिए दस्तावेज़ीकरण केंद्र, (मई 2018 - 31 दिसंबर 2021)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	इला पटनायक, आशिम कपूर, रचना शर्मा
13	वैश्विक दक्षिण में राजकोषीय संघवाद (अगस्त 2019- दिसंबर 2021)	सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बीएमजीएफ	लेखा चक्रवर्ती, गुरलीन कौर, अमनदीप कौर, जेनेट फरीदा जैकब, अनिंदिता घोष, दिव्य रंगन
14	बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त: राज्य स्तरीय विश्लेषण_ गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना"। (अगस्त 2019- दिसंबर 2021)	सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार के तहत बीएमजीएफ	लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर (अनिंदिता घोष के साथ (दिसंबर 2020 तक) और जेनेट फरीदा जैकब)
15	"पर्यावरण/पारिस्थितिकी वित्तीय हस्तांतरण" (अगस्त 2019 या अगस्त 2020)	स्वयं पहल	लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, दिव्या रंगन
16	अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय नीति"। (फरवरी 2019- दिसंबर 2021)	स्व-पहल (अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी के साथ अनुसंधान सहयोग)	लेखा चक्रवर्ती
17	शिक्षा और स्वास्थ्य में लैंगिक समानता और वित्तीय स्थान पर लैंगिक बजट की क्षेत्रीय खर्च प्रभावशीलता: एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अध्ययन (सितंबर 2019 - दिसंबर 2021)	स्व-आरंभ की गई परियोजना (पहले संस्करण अटलांटा में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की बैठकों में प्रस्तुत किया गया था)	लेखा चक्रवर्ती
18	कोविड -19 और एशिया प्रशांत में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का विश्लेषण (2020अगस्त – 2021 मई)	स्वयं पहल	लेखा चक्रवर्ती (अमनदीप कौर, दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)
19	भारत में श्रम के बीज (डिस) संतोष (मई 2020)	स्वयं की पहल	मुकेश आनंद और राहुल चक्रवर्ती
20	भारत में सामाजिक पेंशन: यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम का अग्रदूत (जुलाई 2021)	स्वयं की पहल	मुकेश आनंद और राहुल चक्रवर्ती

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
21	कर नीति और अनुपालन के प्रति दृष्टिकोण का आकलन (मार्च 2021 - मार्च 2022)	बीएमजीएफ	आर कविता राव
22	डेटा गवर्नेंस नेटवर्क (अप्रैल 2019 - सितंबर 2021)	आईडीएफसी फाउंडेशन और ओमिदयार नेटवर्क	रेणुका साने, ऋषभ बेली; स्मृति परशीरा; फैज़ा रहमान; वरुण सेन बहल; त्रिशी गोयल
23	भारत के लिए उपभोक्ता वित्त में शिकायत निवारण प्रबंधन ढांचे की ओर (5 नवंबर 2019 - 31 अक्टूबर 2022)	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	रेणुका साने, मिथिला ए सारा, अनन्या गोयल, सुदीप्तो बनर्जी, सृष्टि शर्मा, कार्तिक सुरेश, सुरेश कुमार, मधुर मेहता, कुसन बिस्वास, करण गुलाटी, अदिति डिमरी
24	स्कूली शिक्षा पर जेंडर संवेदनशील बजट पर अध्ययन (2019)	शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन	सुकन्या बोस और अनुराधा डे, सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रसार (कॉर्ड)
25	सरकारी स्कूलों से बाहर निकलने की जांच (अप्रैल 2019)	अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट, 2018	सुकन्या बोस, प्रियंता घोष, मनोहर बोड़ा और अरविंद सरदाना (एकलव्य)
26	भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रोइकोनोमेट्रिक मॉडलिंग (निरंतरता) (फरवरी 2021)	एसईएफएल-आरंभिक	एनआर भानुमूर्ति और सुकन्या बोस
27	महामारी वर्ष 2020 में राज्यों के राजस्व और व्यय की रूपरेखा (सितंबर 2020 संभावित समाप्ति तिथि अक्टूबर 2021)	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्त पोषण के दृष्टिकोण के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ): द वे	मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता, रोहित दत्ता, राशि मित्तल, गरिमा नैन, रागिनी,
28	स्वास्थ्य और शासन गुणवत्ता पर सार्वजनिक खर्च की दक्षता (अगस्त 2020 संभावित समाप्ति तिथि जून 2021)	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्त पोषण के दृष्टिकोण के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ): द वे	द्वीपोबोती ब्रह्मा, मीता चौधरी और रागिनी
29	गुजरात में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का अंतर-राज्य वितरण: क्षैतिज और लंबवत इक्विटी (नवंबर 2020 - सितंबर 2021)	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्त पोषण के दृष्टिकोण के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ): द वे	मीता चौधरी, जय देव दुबे
30	भारत में कर विवादों का विश्लेषण (31 मार्च, 2020) (निरंतरता)	बीएमजीएफ	सुरांजलि टंडन और आदित्य रेड्डी
31	भारत में वित्तीय बाजारों का कराधान (31 मार्च 2020)(निरंतरता)	बीएमजीएफ	सुरांजलि टंडन, आर कविता राव और आदित्य रेड्डी

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
32	क्या भारत में मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर टिकी है? (सितंबर, 2019-दिसंबर, 2021)	प्रोफेसर पीआर ब्रह्मानंद अनुसंधान अनुदान, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बेंगलुरु, 2018-19	रुद्राणी भट्टाचार्य:
33	भारत में विनिमय दर अस्थिरता पर विदेशी मुद्रा नीति के झटके के प्रभाव को मापना (अप्रैल, 2020---दिसंबर, 2021)	एनआईपीएफपी	रुद्रानी भट्टाचार्य, और शुभंकर मयंक (समर इंटर्न, अप्रैल-मई, 2020)
34	15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को समझें और उनका मूल्यांकन करें (फरवरी से जून 2021)	विश्व बैंक	पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, अमनदीप कौर
35	राज्यों के बजट के राज्य वित्त डेटा का अद्यतन करना:-2022-23 उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में संकाय के उपयोग के लिए सूचना का संकलन और मैक्रो टेबल बनाना (1 अप्रैल 2021, संभावित समापन तिथि 30 जून 2022)	एनआईपीएफपी	रोहित दत्ता और अमर नाथ
36	संबंधित राज्यों के वित्त लेखा-2018-19 से सार्वजनिक वित्त सूचना को अद्यतन करना और इसे डिजिटल प्रारूप में संकाय के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना। (चल रही परियोजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अद्यतन)	एनआईपीएफपी	अमर नाथ, हरि नायडू और रोहित दत्ता

नए अध्ययन शुरू किए गए

S.no	शीर्षक	प्रायोजक	लेखक/अनुसंधान दल
1	राज्य वित्त आयोग के लिए नियमावली, (फरवरी 2021)	केरल सरकार,	पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, दिनेश कुमार नायक, वासुकी नंदन, स्मृति मेहरा
2	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन: जीवीए और निवेश में योगदान, (4, मार्च 2021)	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	इला पटनायक, प्रमोद सिन्हा, मधुर मेहता
3	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन: ज्ञान और नवाचार नेटवर्क, (फरवरी 2021),	विश्व बैंक,	पिनाकी चक्रवर्ती, लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, दिनेश कुमार नायक, अमनदीप कौर
4	महामारी के बाद बजट प्रबंधन: उप-राष्ट्रीय स्तर पर बजट विश्वसनीयता के अनुभव से सीखना, (मार्च 20021)	एनआईपीएफपी	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह

अनुलग्नक II: एनआईपीएफपी: कार्यशील लेख श्रृंखला

क्रमांक	शीर्षक	लेखक
1	COVID-19 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता: राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया (अप्रैल, 2020, संख्या 302)	लेखा चक्रवर्ती और इमैनुएल थॉमस
2	उभरती राजकोषीय प्राथमिकताएं और संसाधन संबंधी चिंताएं: मध्य प्रदेश से वित्तीय प्रबंधन पर एक परिप्रेक्ष्य (अप्रैल, 2020, संख्या 303)	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
3	COVID-19: वैश्विक निदान और भविष्य नीति परिप्रेक्ष्य (अप्रैल, 2020, संख्या 304)	दिव्य रंगन और लेखा चक्रवर्ती
4	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (मई, 2020, संख्या 305) के तहत संपत्ति के हस्तांतरण में लिंग भेदभाव	देवेंद्र दामले, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, तुषार आनंद, विराज जोशी और विशाल त्रेहान
5	पिरामिड के तल पर बाहर निकलें: दिल्ली में प्राथमिक स्कूली शिक्षा के संदर्भ में अनुभवजन्य अन्वेषण (मई, 2020, संख्या 306)	सुकन्या बोस, प्रियंता घोष और अरविंद सरदाना
6	उभरते एशियाई बाजारों पर नकारात्मक ब्याज दर नीति का प्रभाव: एक अनुभवजन्य जांच (जून, 2020, संख्या 307)	अभिषेक आनंद और लेखा चक्रवर्ती
7	COVID-19 महामारी के दौरान फसल पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता में वृद्धि को संबोधित करना: पंजाब का एक मामला (जून, 2020, संख्या 308)	रीता पांडे, शैली केडिया, और अनुजा मल्होत्रा
8	नए कोरोनावायरस का जवाब: एक भारतीय नीति परिप्रेक्ष्य (11 मार्च, 2020 को प्रस्तुत) (जुलाई, 2020, संख्या 309)	अजय शाही
9	भारतीय राज्यों में माल और सेवा कर दक्षता: पैनल स्टोकेस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण (जुलाई, 2020, संख्या 310)	सच्चिदानंद मुखर्जी
10	भारत में जैव विविधता संरक्षण: प्रमुख स्रोतों और निधियों की मात्रा का मानचित्रण (जुलाई, 2020, संख्या 311)	रीता पांडे, मनीष गुप्ता, पवनी सचदेवा, अभिषेक सिंह और शिवली सुगंधा
1 1	क्या सार्वजनिक निवेश ने भारत में निजी निवेश को पीछे छोड़ दिया? (जुलाई, 2020, संख्या 312)	ह्नी करुण, ऋषिकेश विनोद, और लेखा चक्रवर्ती
12	भारत में प्राकृतिक संसाधन राजस्व उछाल: राज्य-विशिष्ट खनन व्यवस्था से अनुभवजन्य साक्ष्य (जुलाई, 2020, संख्या 313)	लेखा चक्रवर्ती, इमैनुएल थॉमस, और पीयूष गांधी
13	ई-कोर्ट डेटा के साथ समस्याएं (जुलाई, 2020, संख्या 314)	देवेंद्र दामले और तुषार आनंद
14	स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च के अंतर-राज्यीय वितरण में इक्विटी: बिहार और तमिलनाडु का मामला (जुलाई, 2020, संख्या 315)	मीता चौधरी और जय देव दुबे
15	मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर बढ़ना (अगस्त, 2020, संख्या 316)	इला पटनायक और राधिका पांडेय
16	राज्यों के स्वास्थ्य व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भूमिका: उपलब्धियां और मुद्दे (अगस्त, 2020, संख्या 317)	मीता चौधरी और रंजन कुमार मोहंती
17	लॉकडाउन के दौरान रिवर्स माइग्रेशन: सार्वजनिक नीतियों का एक स्नैपशॉट (सितंबर, 2020, संख्या 318)	सतद्रु सिकदर और प्रेक्षा मिश्रा
18	भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव: वित्तीय परिदृश्यों का विश्लेषण (सितंबर, 2020, संख्या 319)	इला पटनायक और राजेश्वरी सेनगुप्ता
19	प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्र-राज्य खर्च: क्या यह पूरक या स्थानापन्न है? (सितंबर, 2020, नंबर 320)	सुकन्या बोस, मानसी बेरा और प्रियंता घोष

क्रमांक	शीर्षक	लेखक
20	समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण (अक्टूबर, 2020, संख्या 321)	रुद्राणी भट्टाचार्य, अभिजीत सेन गुप्ता और सतद्रू सिकदर
21	भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के मौसमी समायोजन से हमें क्या लाभ होता है? (अक्टूबर, 2020, संख्या 322)	राधिका पांडे, अमेय सप्रे और प्रमोद सिन्हा
22	भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान: वेक्टर त्रुटि सुधार तंत्र बनाम। गैर-स्थिर समय श्रृंखला के लिए गतिशील कारक मॉडल दृष्टिकोण (अक्टूबर, 2020, संख्या 323)	रुद्राणी भट्टाचार्य, और मृगांक्षी कपूर
23	स्वास्थ्य देखभाल की मांग की आय लोच और समय के साथ इसमें बदलाव: भारत में आय समूहों और स्वास्थ्य व्यय के स्तरों में (अक्टूबर, 2020, संख्या 324)	जय देव दुबे
24	मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के चार साल (नवंबर, 2020, संख्या 325)	इला पटनायक और राधिका पांडेय
25	भारत में अनिगमित उद्यमों के औपचारिक ऋण तक पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक: एनएसएसओ के यूनिट-स्तरीय डेटा का विश्लेषण (दिसंबर, 2020, संख्या 326)	शिवानी बडोला और सच्चिदानंद मुखर्जी
26	महामारी और जीएसटी राजस्व: संघ और राज्यों के लिए एक आकलन (दिसंबर, 2020, संख्या 327)	सच्चिदानंद मुखर्जी
27	केंद्रीय बजट 2021-22 का व्यापक आर्थिक ढांचा: राजकोषीय नियमों पर पुनर्विचार (मार्च, 2020, संख्या 328)	लेखा चक्रवर्ती
28	भारत में बांध सुरक्षा (मार्च, 2020, संख्या 329)	देवेंद्र दामले
29	आयकर डेटा में प्रतिबिंबित अर्थव्यवस्था (मार्च, 2020, संख्या 330)	आर कविता राव
30	उपभोक्ता वित्त विवादों में न्यायालयों द्वारा शिकायत निवारण (मार्च, 2020, संख्या 331)	करण गुलाटी और रेणुका साने
31	पारिस्थितिक वित्तीय हस्तांतरण और राज्य-स्तरीय बजटीय खर्च: भारत में फ्लाईपेपर प्रभाव के लिए साक्ष्य (मार्च, 2020, संख्या 332)	अमनदीप कौर, रंजन कुमार मोहंती, लेखा चक्रवर्ती और दिव्या रंगन
32	कोविड -19 आर्थिक प्रोत्साहन और राज्य-स्तरीय बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन: दक्षता मापदंडों का विश्लेषण (मार्च, 2020, संख्या 333)	अमनदीप कौर, लेखा चक्रवर्ती, दिव्या रंगन
33	राजकोषीय संघवाद, व्यय असाइनमेंट और लैंगिक समानता (मार्च, 2020, संख्या 334)	लेखा चक्रवर्ती
34	भारत में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण का वित्तपोषण: प्रयासों और परिणामों के लिए निहितार्थ (मार्च, 2020, संख्या 335)	रीता पांडे, मनीष गुप्ता, पवनी सचदेवा, अभिषेक सिंह और सुमित अग्रवाल

अनुलग्नक III: एनआईपीएफपी: आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला

दिन दिनांक	विषय
गुरूवार 13 अगस्त, 2020	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस: अधिक साइबर संप्रभुता की ओर
गुरूवार 03 सितंबर, 2020	जीआरएम वार्ता: वित्त में शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण पर एक वेबिनार श्रृंखला
गुरूवार 17 सितंबर, 2020	जीआरएम वार्ता: वित्त में शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण पर एक वेबिनार श्रृंखला
गुरूवार 01 अक्टूबर, 2020	जीआरएम वार्ता: वित्त में शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण पर एक वेबिनार श्रृंखला
गुरूवार 15 अक्टूबर, 2020	जीआरएम वार्ता: वित्त में शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण पर एक वेबिनार श्रृंखला
बुधवार 28 अक्टूबर, 2020	छठा तिमाही गोलमेज - डेटा गवर्नेंस नेटवर्क
गुरूवार 05 नवंबर, 2020	जीआरएम वार्ता: वित्त में शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण पर एक वेबिनार श्रृंखला
गुरूवार 12 नवंबर, 2020	जीआरएम वार्ता: वित्त में शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण पर एक वेबिनार श्रृंखला

अनुलग्नक IV: शासी निकाय के सदस्यों की सूची

18 जून, 2020 को हुई अपनी बैठक में शासी निकाय को 4 साल की एक और अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया, यानी 5 अप्रैल, 2020 से 4 अप्रैल, 2024 तक।

1

1 दिसंबर 2021 को शासी निकाय

डॉ उर्जित पटेल एनआईपीएफपी 18/2 सत्संग विहार मार्ग विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के पास) नई दिल्ली- 11 0067	**अध्यक्ष**
नियम 7 (बी) (i) के तहत **वित्त मंत्रालय के तीन नामित**	
श्री तरुण बजाज राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001	**सदस्य**
श्री अजय सेठ, आईएएस सचिव (आर्थिक मामले) वित्त मंत्रालय भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001	**सदस्य**
डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली 110001	**सदस्य**
नियम 7 (बी) (ii) के तहत **आरबीआई का एक नामांकित व्यक्ति**	

डॉ राजीव रंजन **सदस्य**
प्रभारी सलाहकार
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
24वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई-400 001

नियम 7 (बी) (iii) के तहत
योजना आयोग का एक नामांकित व्यक्ति

सुश्री अन्ना रॉय **सदस्य**
वरिष्ठ सलाहकार
नीति आयोग
पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली-110001

नियम 7 (बी) (iv) के तहत
राज्य सरकारों को प्रायोजित करने वाले तीन नामांकित व्यक्ति।

श्री समीर कुमार सिन्हा, आईएएस **सदस्य**
प्रमुख सचिव
वित्त विभाग
असम सरकार
असम सचिवालय
दिसपुर, गुवाहाटी-781005

श्री संजय एम कौल, आईएएस **सदस्य**
सचिव (वित्त-व्यय)
वित्त विभाग
केरल सरकार
सचिवालय
तिरुवनंतपुरम-695001

श्री मनोज सौनिक, आईएएस, **सदस्य**
अपर मुख्य सचिव (वित्त)
वित्त विभाग
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय
मुंबई 400,032

नियम 7 (बी) (vi) के तहत
आईसीआईसीआई बैंक का एक नामांकित व्यक्ति

श्री बी प्रसन्ना **सदस्य**
प्रमुख - वैश्विक बाजार
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व
मुंबई-400 051

नियम 7(बी)(vii) के तहत
संस्थाओं के दो नामांकित व्यक्ति

श्री विनीत अग्रवाल **सदस्य**
अध्यक्ष
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
5, सरदार पटेल मार्ग
चाणक्यपुरी
(होटल डिप्लोमैट के पास)
नई दिल्ली-110 021

श्री उदय शंकर **सदस्य**
अध्यक्ष
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110001

नियम 7 (बी) (viii) के तहत
तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री

डॉ माला लालवानी **सदस्य**
प्रोफ़ेसर
मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी
मुंबई विश्वविद्यालय
विद्यानगरी परिसर, कलिना
सांताक्रूज (ई)
मुंबई 400 098

डॉ. एम गोविंदा राव **सदस्य**
14वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य
निवास: 8 बी, शोभा एमराल्ड, जक्कुर,
बैंगलोर 560064

डॉ ज्योत्सना जालान **सदस्य**

अर्थशास्त्र के प्रोफेसर
सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज, कलकत्ता आर-1,
वैष्णबघाट पटुली टाउनशिप,
कोलकाता- 700 094

नियम 7 (बी) (ix) के तहत
सहयोगी संस्थान के तीन प्रतिनिधि।

डॉ पूनम गुप्ता **सदस्य**
महानिदेशक
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
11, पेरिसिला भवन
आईपी एस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली - 110 002

सुश्री यामिनी अय्यर **सदस्य**
अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी
नीति अनुसंधान केंद्र
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली 110 021

नियम 7 (बी) (एक्स) के तहत
शासी निकाय द्वारा सहयोजित किए जाने वाले दो सदस्य

सीए तरुण जे. घिया **सदस्य**
आईसीएआई के परिषद सदस्य
सी/ओ उप सचिव (परिषद मामले)
इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया
आईसीएआई भवन
आईपी मार्ग
नई दिल्ली-110002

नियम 7 (बी) (xi) के तहत
संस्थान के निदेशक (पदेन)

डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती **सदस्य**
निदेशक, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

नियम 7(बी)(xii) के तहत
संस्थान के एक प्रोफेसर रोटेशन द्वारा

डॉ लेखा चक्रवर्ती सदस्य **सदस्य**
प्रोफेसर, एनआईपीएफपी, ,नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित

श्री जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा **सदस्य**
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
वित्त मंत्रित्व
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

श्री एम. अजीत कुमार **सदस्य**
अध्यक्ष
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
वित्त मंत्रित्व
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

अनुलग्नक V: मूल्यांकित प्रकाशनों की सूची

S.no	मूल्य प्रकाशन की सूची
1	**भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की घटनाएं 1973-74,** आरजे चेलिया और आरएन लाल (1978) INR 10. हिंदी संस्करण (1981) INR 20।
2	**भारतीय संघीय वित्त में रुझान और मुद्दे,*** आरजे चेलिया एंड एसोसिएट्स (एलाइड पब्लिशर्स) (1981) INR 60।
3	**बिहार में बिक्री कर प्रणाली,*** आरजे चेलिया और एमसी पुरोहित (सोमैया प्रकाशन) (1981) INR 80।
4	**राज्य सरकारों के कर प्रयास का मापन 1973-76,*** आरजे चेलिया और एन सिन्हा (सोमैया प्रकाशन) (1982) INR 60।
5	**व्यक्तिगत आयकर का प्रभाव,** अनुपम गुप्ता और पवन के अग्रवाल (1982) INR 35।
6	**निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में संसाधन जुटाना,** विनय डी. लाल, श्रीनिवास मधुर और केके अत्री (1982) INR 50।
7	**वित्तीय प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट कर बचत,** विनय डी. लाल (1983) INR 40।
8	**निजी ट्रस्टों का कर उपचार,** के श्रीनिवासन (1983) INR 140।
9	**केंद्र सरकार का व्यय: विकास, संरचना और प्रभाव (1950-51 से 1977-78),**केएन रेड्डी, जेवीएम सरमा और एन सिन्हा (1984) INR 80।
10	**चुंगी के विकल्प के रूप में प्रवेश कर,** एमजी राव (1984) INR 40 पेपरबैक, INR 80 हार्डकवर।
11	**सूचना प्रणाली और तमिलनाडु में बिक्री कर की चोरी,** आरजे चेलिया और एमसी पुरोहित (1984) INR 50।
12	**भारत में उत्पाद शुल्क की चोरी: तांबे, प्लास्टिक और सूती वस्त्रों के कपड़े का अध्ययन,** ए बागची एट अल। (1986) INR 180।
13	**भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलू (जिसे 'ब्लैक मनी रिपोर्ट' भी कहा जाता है),** शंकर एन आचार्य एंड एसोसिएट्स, आरजे चेलिया द्वारा योगदान के साथ (1986) पुनर्मुद्रण संस्करण INR 270।
14	**मुद्रास्फीति लेखा और कॉर्पोरेट कराधान,** तापस कुमार सेन (1987) INR 90।
15	**पश्चिम बंगाल में बिक्री कर प्रणाली,** ए बागची और एसके दास (1987) INR 90।
16	**ग्रामीण विकास भत्ता (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CC): एक समीक्षा,** एचके सोंधी और जेवीएम सरमा (1988) INR 40।
17	**दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली,** आरजे चेलिया और केएन रेड्डी (1988) INR 240।
18	**निवेश भत्ता (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32ए): एक अध्ययन,** जेवीएम सरमा और एचके सोंधी (1989) INR 75 पेपरबैक, INR 100 हार्डकवर।
19	**धर्मार्थ योगदान के लिए कर प्रोत्साहन के अनुकरणीय प्रभाव: भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक अध्ययन,**पवन के अग्रवाल (1989) INR 100।
20	**भारत में डाक सेवाओं का मूल्य निर्धारण,** राघबेंद्र झा, एमएन मूर्ति और सत्य पॉल (1990) INR 100।
21	**भारत में घरेलू बचत - रुझान और मुद्दे,#** उमा दत्ता रॉय चौधरी और अमरेश बागची (सं.) (1990) INR 240।
22	**मध्य प्रदेश में बिक्री कराधान,#** एम गोविंदा राव, केएन बालासुब्रमण्यम और वीबी तुलसीधर (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 125।
23	**मोडवैट का संचालन,#** एवीएल नारायण, अमरेश बागची और आरसी गुप्ता (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 250।
24	**राजकोषीय प्रोत्साहन और संतुलित क्षेत्रीय विकास: धारा 80 एचएच का मूल्यांकन,#** पवन के. अग्रवाल और एचके सोंधी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 195।
25	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर: एक प्रोफ़ाइल** (वॉल्यूम I और II) INR 100।
26	**भारत में एल्युमीनियम उद्योग के लिए प्रभावी प्रोत्साहन मोनोग्राफ श्रृंखला - I,** बी गोल्डर (1991) INR 100।

S.no	मूल्य प्रकाशन की सूची
27	**भारत में राजकोषीय संघवाद पर अनुसंधान का सर्वेक्षण मोनोग्राफ श्रृंखला - II,** एम गोविंदा राव और आरजेचेलिया (1991) INR 100।
28	**राजस्व और व्यय अनुमान: मूल्यांकन और कार्यप्रणाली,#** वीजी राव, अतुल सरमा द्वारा संशोधित और संपादित (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992) INR 195।
29	**भारत में बिक्री कर प्रणाली: एक प्रोफाइल** (1991) 150 रुपये।
30	**भारत में राज्य वित्त#,** अमरेश बागची, जेएल बजाज और विलियम ए. बर्ड (सं.) (1992) INR 450.
31	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राजकोषीय नीति,#** महेश सी. पुरोहित, सी. साई कुमार, गोपीनाथ प्रधान और ओ.पी. बोहरा (1992) INR 225।
32	**विनिर्माण क्षेत्र मोनोग्राफ श्रृंखला III में आयात प्रतिस्थापन,** हाशिम एन सलीम (1992) INR150।
33	**भारत में बिक्री कर प्रणाली: एक प्रोफाइल** (1993) INR 150।
34	**नौवां वित्त आयोग: मुद्दे और सिफारिशें (कागजात का चयन)** (1993) INR 490।
35	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर: एक प्रोफ़ाइल (खंड III),** के. कन्नन और ममता शंकर द्वारा संकलित (1993)INR 80।
36	**आर्थिक विकास और जीवन स्तर में अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय बदलाव** (मोनोग्राफ सीरीज IV) (1993) उमा दत्ता रॉय चौधरी INR 200।
37	**विकासशील देशों में कर नीति और योजना,*** अमरेश बागची और निकोलस स्टर्न (सं.) (1994) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) INR 435।
38	**भारत में घरेलू व्यापार करों में सुधार: मुद्दे और विकल्प अध्ययन दल** (1994) INR 250।
39	**निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र: धन का सृजन और पुनर्जनन,** उमा दत्ता रॉय चौधरी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1996) INR 395।
40	**प्रदूषण को नियंत्रित करना: प्रोत्साहन और विनियम,** शेखर मेहता, सुदीप्तो मुंडले और यू. शंकर (सेज प्रकाशन) (1997) INR 250।
41	**भारत: नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कर नीति (1997-98 से 2001-02),#** (वित्तीय संसाधन अध्यक्ष पार्थसारथी शोम पर संचालन समूह की कर नीति पर कार्य समूह की रिपोर्ट) (सैंटैक्स प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 350।
42	**भारत में मूल्य वर्धित कर: एक प्रगति रिपोर्ट,#** पार्थसारथी शोम (सं.) (सैंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 250।
43	**राजकोषीय नीति सार्वजनिक नीति और शासन,#** पार्थसारथी शोम (सं.) (सैंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 400।
44	**भारत में सरकारी सब्सिडी,** डीके श्रीवास्तव और तापस के. सेन (1997) INR 285।
45	**पर्यावरण स्थिरता के लिए आर्थिक उपकरण,** यू. शंकर और ओम प्रकाश माथुर (1998) INR150।
46	**भारत: शहरी शासन की चुनौती,** ओम प्रकाश माथुर (सं.) (1999) INR 400.
47	**राज्य वित्तीय अध्ययन - असम,** डीके श्रीवास्तव, सौमेन चट्टोपाध्याय और टीएस रंगमन्नार (1999) INR200।
48	**राज्य वित्तीय अध्ययन - पंजाब,** इंदिरा राजारमन, एच. मुखोपाध्याय और एच.के. अमरनाथ (1999) INR 200.
49	**राज्य वित्तीय अध्ययन – केरल,** डीके श्रीवास्तव, सौमेन चट्टोपाध्याय और प्रप रंजन जेना (1999) INR200।
50	**दिल्ली राजकोषीय अध्ययन,** ओम प्रकाश माथुर और टीएस रंगमन्नार (2000) INR 250।
51	**भारत में राजकोषीय संघवाद ग्यारहवें वित्त आयोग के समक्ष समसामयिक चुनौतियां मुद्दे,#** डीके श्रीवास्तव (सं.) (हर आनंद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड) (2000) INR 695।
52	**राज्य वित्तीय अध्ययन - हरियाणा,** तापस के. सेन, आर. कविता राव (2000) INR 200।
53	**सार्वजनिक धन का नियंत्रण: विकासशील देशों में राजकोषीय तंत्र,*** ए प्रेमचंद (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (2000) INR 745।

S.no	मूल्य प्रकाशन की सूची
54	**मूल्य वर्धित कर पर प्राइमर,#** आरजे चेलिया, पवन, के अग्रवाल, महेश सी. पुरोहित और आर कविता राव (हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड) (2001) INR 195।
55	**भारत में केंद्रीय बजटीय सब्सिडी,** डीके श्रीवास्तव और एचके अमरनाथ (2001) INR 170।
56	**राज्य-नगरपालिका वित्तीय संबंधों के लिए दृष्टिकोण: विकल्प और परिप्रेक्ष्य** ओम प्रकाश माथुर (2001) INR200.
57	**व्यापार और उद्योग: एनआईपीएफपी-फोर्ड फाउंडेशन फेलो द्वारा निबंध,#** एके गुहा, केएल कृष्णा और अशोक, के.लाहिरी (सं.) (विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड) (2001) INR 450।
58	**भारत के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और विनियम: अनुमोदन और विकल्प,#** एसपी सिंह और अमरेश बागची आरके बजाज द्वारा योगदान के साथ (यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड) (2002) INR 395।
59	**विदेशी उत्पादों की तुलना में घरेलू का भेदभावपूर्ण कर व्यवहार: एक आकलन,** पवन के. अग्रवाल और वी. सेल्वाराजू (2002) INR 200।
60	**नियमन का अभ्यास और राजनीति: भारतीय विद्युत में नियामक शासन,*** नवरोज के. दुबाशंद डी. नरसिम्हा राव (2007) INR 290. (स्टॉक में: 32)
61	**मानव विकास पर गरीबी की कमी से निपटना: मध्य प्रदेश में वित्तीय रणनीतियाँ (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के सेन, एचके अमरनाथ, मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी (2007) INR 150। (स्टॉक में: 56)
62	**तमिलनाडु में मानव विकास का वित्तपोषण: उपलब्धि पर समेकित और निर्माण (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी (2008) INR 150। (स्टॉक में: 22)
63	**भारतीय संघ में स्वास्थ्य व्यय का अंतर-राज्यीय समानता,** एम. गोविंदा राव और मीता चौधरी (2008) INR, 75. (स्टॉक में: 94)
64	**भारत में व्यय प्रबंधन के 50 वर्षों के इनकार के आराम क्षेत्र में फंस गया,** ए प्रेमचंद (2008) आईएनआर, 150. (स्टॉक में: 86)
65	**राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जेंडर बजटिंग,** एम. गोविंदा राव, लेखा चक्रवर्ती, अमरेश बागची (2008) INR, 250. (स्टॉक में: 96)
66	**वित्तीय सुधार, लगातार गरीबी और मानव विकास: उड़ीसा का मामला (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोतिवा कुंडू (2008) INR 150। (स्टॉक में: 98)
67	**पश्चिम बंगाल में मानव विकास के सार्वजनिक वित्त पोषण पर वित्तीय बाधाओं से निपटना (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)** – तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोतिवा कुंडू (2009) INR 150। (स्टॉक में: 148)
68	**भारत के निम्न कार्बन आर्थिक विकास की संभावनाएं और नीतियां,** रामप्रसाद सेनगुप्ता (2010) 150 रुपये (स्टॉक में: 114)
69	**भारत में निम्न कार्बन और उच्च विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत साधन,** यू. शंकर (2010) 150 रुपये। (इनस्टॉक: 120)
70	**राजस्थान: आर्थिक और मानव विकास को समवर्ती रूप से बढ़ावा देना (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR 150. (स्टॉक में: 147)
71	**भारत: सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट,** प्रताप रंजन जेना (2010) INR 150। (स्टॉक में: 29)
72	**हिमाचल प्रदेश में सतत मानव विकास के लिए संसाधन (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR 150. (स्टॉक में: 142)

S.no	मूल्य प्रकाशन की सूची
73	**एक युवा राज्य का परिपक्वता में तेजी से संक्रमण: छत्तीसगढ़ में मानव विकास के लिए संसाधन (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण**), तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR, 150. (स्टॉक में: 151)
74	**केरल में मानव विकास का वित्तपोषण: मुद्दे और चुनौतियाँ (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण**), पिनाकी चक्रवर्ती, लेखा चक्रवर्ती, एचके अमरनाथ, और सोना मित्रा (2010) INR। 150. (स्टॉक में: 153)
75	**अपने आर्थिक विकास के साथ पूरे महाराष्ट्र में मानव विकास का मिलान (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),**तापस के. सेन, अमरनाथ एच.के., मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) 150 रुपये। (स्टॉक में: 157)
76	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अव्ययित शेष और निधि प्रवाह तंत्र,** एनआर भानुमूर्ति, एचके अमरनाथ, अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता (2014) INR 200। (स्टॉक में: 98)
77	**मध्य प्रदेश राज्य एमडीजी रिपोर्ट 2014-15**, एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, सुकन्या बोस, परमा चक्रवर्ती और अक्राज्योति जाना (2015)। (स्टॉक में: 98)
78	**मध्य प्रदेश में मानव विकास परिणामों में विचलन: राजकोषीय नीति और शासन की भूमिका**, एनआर भानुमूर्ति, एचके अमरनाथ, मनीष प्रसाद, शाइनी चक्रवर्ती और ऋचा जैन (2017)। (स्टॉक में: 37)
79	**राज्य के वित्त में उभरते मुद्दे चौदहवें वित्त आयोग के बाद: राज्य बजट 2016-17 का विश्लेषण,**मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती और पिनाकी चक्रवर्ती (2018)। (स्टॉक में: 165)
80	**राज्य के बजट 2017-18 का विश्लेषण: उभरते मुद्दे (विद्युत क्षेत्र के ऋण का प्रभाव - राज्य के वित्त पर उदय),** पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर (2018) INR 200।
81	**राज्य के बजट 2018-19 का विश्लेषण - प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ (बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियाँ) मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर** (2020)

*संबंधित प्रकाशकों के साथ सह-प्रकाशित/उपलब्ध।

एनआईपीएफपी के साथ सह-प्रकाशित/उपलब्ध।

ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के खिलाफ प्रकाशन भेजे गए। डाक खर्च INR 80 प्रति प्रति।

नोट: क्रमांक से प्रकाशन। नंबर 1 से 69 तक, बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसे एनआईपीएफपी लाइब्रेरी से एक्सेस किया जा सकता है

अनुलग्नक VI: एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री

(किताबें, पत्रिकाएं, मोनोग्राफ और अन्य लोकप्रिय लेख)

चक्रवर्ती, पिनाकी

1. 'राजस्व घाटे को कम करना सही रास्ता नहीं लगता' / पिनाकी चक्रवर्ती द्वारा, बिजनेस स्टैंडर्ड में, 15/01/2021, पृष्ठ 6
2. भारत में 28 राज्यों की राजकोषीय पूर्वानुमान त्रुटियों का विश्लेषण करने वाली सबनेशनल सरकार की बजट साख, (पिनाकी चक्रवर्ती और रुज़ेल श्रेष्ठ के साथ), वर्किंग पेपर सीरीज़ 964 (2020) - एनआईपीएफपी और लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क।
3. पन्द्रवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का विश्लेषण: स्थिरता, निरंतरता और परिवर्तन (माइमोग्राफ)।
4. पोस्ट कोविड राजकोषीय वास्तुकला और एफआरबीएम: पंद्रहवें वित्त आयोग (माइमोग्राफ) की सिफारिशों का विश्लेषण।

रॉय, रथिन

1. "चेंजिंग फिस्कल डायनेमिक्स", जर्नल सेमिनार, नई दिल्ली में, 30 अप्रैल 2019।
2. भारत की आयात निर्भरता का मिथक" बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 जुलाई 2020, पृ.-09
3. "बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन यह जल्द ही होगा" बिजनेस स्टैंडर्ड, 7 अगस्त 2020, पृ.11
4. अंतर्ज्ञान, भविष्यवाणी नहीं" बिजनेस स्टैंडर्ड, 5 जून 2020, पी-11
5. "कोविड -19 लॉकडाउन: प्रशासनिक रणनीति को भूल जाइए, एक आर्थिक रणनीति पर शिफ्ट हो जाइए" बिजनेस स्टैंडर्ड, 8 मई 2020।
6. "खर्च बढ़ाने के लिए राजकोषीय परिषद की स्थापना करें" बिजनेस स्टैंडर्ड, 8 अप्रैल, 2020

राव, आर कविता

1. द इकोनॉमी ऐज़ रिफ्लेक्टेड इन इनकम टैक्स डेटा, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 330, मार्च 2021।
2. "स्वच्छ ऊर्जा शिफ्ट का वित्तपोषण", बिजनेस लाइन, 12 मार्च, 2021, पृष्ठ 5

पटनायक, इला

1. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के चार साल, (राधिका पांडे के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 325, नवंबर 2020।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव: राजकोषीय परिदृश्यों का विश्लेषण, (राजेश्वरी सेनगुप्ता के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 319, सितंबर 2020।
3. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर बढ़ना, (राधिका पांडे के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 316, एनआईपीएफपी, अगस्त 2020।
4. पटनायक, इला, राजेश्वरी सेनगपा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव: राजकोषीय परिदृश्यों का विश्लेषण, भारतीय सार्वजनिक नीति समीक्षा: अर्थशास्त्र, राजनीति और रणनीति का एक जर्नल (आईपीपीआर), 1(1): 41-52।

शाह, अजय

1. नए कोरोनावायरस का जवाब: अजय शाह द्वारा एक भारतीय नीति परिप्रेक्ष्य, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 309, जुलाई 2020।

मीडिया लेख

2. नई शिक्षा नीति के विचारों को अमल में लाना, बिजनेस स्टैंडर्ड, 10 अगस्त 2020।
3. आइडियाज ऑफ इंडिया: लिबर्टेरियनिज्म बाय नेसेसिटी, श्रुति राजगोपालन द्वारा पॉडकास्ट आइडियाज ऑफ इंडिया का उद्घाटन एपिसोड, 6 अगस्त 2020।
4. कार्य, घर और कार्यालय पर पुनर्विचार, बिजनेस स्टैंडर्ड, 27 जुलाई 2020।
5. रिश्तों की अर्थव्यवस्था अनुबंधों की अर्थव्यवस्था के विपरीत, बिजनेस स्टैंडर्ड, 13 जुलाई 2020।
6. वर्तमान आर्थिक मुद्दों के बारे में एक बातचीत, सीज़नल पत्रिका के साथ, 1 जुलाई 2020।
7. अधिक प्रतिभूतिकरण से मदद मिलेगी, बिजनेस स्टैंडर्ड, 29 जून 2020।
8. चरम कोविड -19, के लिए कमर कस रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, 15 जून 2020 ।
9. आने वाले वर्ष के लिए स्वास्थ्य नीति, बिजनेस स्टैंडर्ड, 1 जून 2020।
10. क्या निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करने से हमारे स्वास्थ्य देखभाल बिल कम हो जाएंगे?, पूजा मेहरा द्वारा पॉडकास्ट एवरीडे इकोनॉमिक्स का उद्घाटन एपिसोड, 30 मई 2020।
11. कृषि में आर्थिक स्वतंत्रता, बिजनेस स्टैंडर्ड, 18 मई 2020।
12. डी-लॉकडाउन को एक बेहतर संस्थागत आधार की जरूरत है, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4 मई 2020।
13. क्या अधिक विदेशी वित्तपोषण की आवश्यकता होगी?, बिजनेस स्टैंडर्ड, 20 अप्रैल 2020।
14. 2020 की महामारी: वी-आकार की वसूली के लिए पाठ्यक्रम, बिजनेस स्टैंडर्ड, विजय केलकर और अजय शाह द्वारा, 7 अप्रैल 2020।
15. फाइनेंस टू द फोर, बिजनेस स्टैंडर्ड, 6 अप्रैल 2020।

एन.आर. भानुमूर्ति

1. भारत में उपराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक व्यय दक्षता का आकलन: क्या शासन मायने रखता है? (आरके मोहंती के साथ), जर्नल (जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, वॉल्यूम 21, नंबर 2, ई2173)।

चक्रवर्ती, लेखा

1. चक्रवर्ती, लेखा, मनीष गुप्ता और अमनदीप कौर, (2020)। राज्य बजट 2018-19 का विश्लेषण: बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियां, मोनोग्राफ, एनआईपीएफपी - राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली।
2. चक्रवर्ती, लेखा और इसहाक, आर. मोहन, "भारतीय राजकोषीय संघवाद की चुनौतियां", पुस्तक - दूसरा संस्करण, वामपंथी प्रकाशन।
3. कौर, अमनदीप, लेखा चक्रवर्ती, रुजेल श्रेष्ठ, जेएफ जैकब, ए घोष, (2020)। पोषण-सार्वजनिक व्यय समीक्षा: गुजरात से साक्ष्य, मोनोग्राफ, एनआईपीएफपी - राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली।
4. चक्रवर्ती, लेखा हृषिकेश विनोद, और एच. करुण, भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहित करना: MEBOOT पद्धति का उपयोग कर अर्थमितीय अनुमान, (संस्करण।) ऋषिकेश डी विनोद और सीआर राव, सांख्यिकी पर हैंडबुक में: वित्तीय मैक्रो-माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स आर वॉल्यूम 42 का उपयोग कर , एल्सेवियर यूएसए।
5. चक्रवर्ती, लेखा, वीना नय्यर और कोमल जैन, लिंग बजट की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य "(सं।) जिल विकर्स, जोन ग्रेस और चेरिल एन। कोलियर, हैंडबुक ऑन जेंडर, डायवर्सिटी एंड फ़ेडरलिज़्म, इंटरनेशनल हैंडबुक्स ऑन लिंग श्रृंखला, एडवर्ड एल्गर प्रकाशन, यूएसए।
6. चक्रवर्ती, लेखा. लिंग बजट और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बीच उलटा संबंध" (ईडी) चिंडू में "होल्ड योर स्टोरी, बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी, यूके और यूनेस्को।
7. चक्रवर्ती, लेखा, और ई. थॉमस, कोविड 19 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता: राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं, (ईडी)   उमा कपिला, 'भारत में आर्थिक विकास (ईडीआई) श्रृंखला, खंड 250, अकादमिक फाउंडेशन में।
8. चक्रवर्ती, लेखा, भारतीय वित्तीय संघवाद' उमा कपिला में (एड) "भारत में आर्थिक विकास", खंड 249, अकादमिक फाउंडेशन।
9. चक्रवर्ती, लेखा और दिव्य रंगन, कोविड 19: ग्लोबल डायग्नोसिस एंड फ्यूचर पॉलिसी पर्सपेक्टिव, प्रजान, जर्नल ऑफ सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेज (सेज)।
10. चक्रवर्ती, लेखा और इमैनुएल थॉमस, कोविड -19 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता: राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55(15) 11 अप्रैल।
11. आनंद, अभिषेक और लेखा चक्रवर्ती, उभरते एशियाई बाजारों पर नकारात्मक ब्याज दर नीति का प्रभाव: एक अनुभवजन्य जांच, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55 (24), 17 जून।
12. टीएम थॉमस इसाक आर मोहन, और लेखा चक्रवर्ती, फिस्कल कंसॉलिडेशन एक्स पोस्ट फिफ्टीनवें फाइनेंस कमीशन अवार्ड फॉर 2020-21 इंप्लीकेशंस फॉर स्टेट्स कमेंट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 55 (45), नवंबर 2020।
13. ए जेंडर लेंस टू रिकवरी पैकेज: एविडेंस फ्रॉम एशिया पैसिफिक, (अमनदीप कौर, दिव्य रंगन, जेनेट फरीदा जैकब के साथ), फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 12 मार्च, 2021

14. लैंगिक असमानताओं के निवारण के लिए राजकोषीय हस्तक्षेप की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: अनुभवजन्य साक्ष्य, (वीना नैयर और कोमल जैन अमनदीप कौर, दिव्य रंगन, जेनेट फरीदा जैकब के साथ), ऑसटैक्स नीति संस्थान, 2021।
15. भारत में 28 राज्यों की राजकोषीय पूर्वानुमान त्रुटियों का विश्लेषण करने वाली सबनेशनल सरकार की बजट साख, (पिनाकी चक्रवर्ती और रुज़ेल श्रेष्ठ के साथ), वर्किंग पेपर सीरीज़ 964 (2020) - एनआईपीएफपी और लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क।
16. राजकोषीय संघवाद, व्यय असाइनमेंट और लैंगिक समानता, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 334, मार्च, 2021।
17. कोविड -19 आर्थिक प्रोत्साहन और राज्य-स्तरीय बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन: दक्षता मापदंडों का विश्लेषण, (अमनदीप कौर और दिव्य रंगन के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 333, मार्च, 2021।
18. इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर एंड स्टेट-लेवल बजटरी स्पेंडिंग इन इंडिया: एनालिसिस द फ्लाईपेपर इफेक्ट्स इन इंडिया, (अमनदीप कौर, रंजन कुमार मोहंती और दिव्य रंगन के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 332, मार्च, 2021।
19. केंद्रीय बजट 2021-22 का व्यापक आर्थिक ढांचा: राजकोषीय नियमों पर पुनर्विचार, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 328, फरवरी, 2021।
20. भारत में प्राकृतिक संसाधन राजस्व उछाल: राज्य-विशिष्ट खनन व्यवस्था से अनुभवजन्य साक्ष्य, (इमैनुएल थॉमस और पीयूष गांधी के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 313, जुलाई, 2020।
21. क्या सार्वजनिक निवेश ने भारत में निजी निवेश को बढ़ा दिया? (ऋषिकेश विनोद और हनी करुण), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 312, जुलाई, 2020।
22. उभरते एशियाई बाजारों पर नकारात्मक ब्याज दर नीति का प्रभाव: एक अनुभवजन्य जांच, (अभिषेक आनंद के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 307, जून, 2020।
23. COVID-19: ग्लोबल डायग्नोसिस एंड फ्यूचर पॉलिसी पर्सपेक्टिव, (दिव्य रंगन के साथ), NIPFP वर्किंग पेपर नंबर 304, मई, 2020।
24. COVID-19 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता: राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया, (इमैनुएल थॉमस के साथ), NIPFP वर्किंग पेपर नंबर 302, अप्रैल, 2020।

<u>अन्य गतिविधियां / लोकप्रिय लेखन</u>

25. एक असमान वसूली: बिडेन का आर्थिक प्रोत्साहन, द इंडियन एक्सप्रेस में, मार्च 2021, अभिषेक आनंद के साथ
26. पर्स स्ट्रिंग्स को ढीला करें, द इंडियन एक्सप्रेस में, मार्च 2021, इमैनुएल थॉमस के साथ
27. द हिंदू, जनवरी 31, 2021 में, रिकवरी के पहियों को चालू रखें
28. द वायर, 1 फरवरी, 2021 में राजकोषीय घाटे की शारीरिक रचना को समझना।
29. द शैडो महामारी: महिलाओं के खिलाफ हिंसा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, 2020

30. "आउटपुट गैप" विवादास्पद क्यों है? (पब 23/12/2020 फाइनेंशियल एक्सप्रेस), लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर
31. लेखा चक्रवर्ती ने @Forbes में "द हार्डर-हिट हाफ: व्हाई इंडिया नीड ए जेंडर अप्रोच टू कोविड-19", 2020 मई
32. प्रवासी मजदूरों के लिए राहत, बहुत देर से, बहुत कम, (पब। 29/05/2020 फाइनेंशियल एक्सप्रेस), रामजी एस कृष्णन, लेखा चक्रवर्ती और विद्या बी रामजी
33. इक्विटी का वादा, (पब। 07/05/2020 फाइनेंशियल एक्सप्रेस), लेखा चक्रवर्ती और विद्या बी रामजी
34. कोरोनावायरस संकट: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी राहत, (पब। 09/04/2020 फाइनेंशियल एक्सप्रेस), इमैनुएल थॉमस और लेखा चक्रवर्ती
35. कोविड -19 प्रभाव: आशा के बीज रोपण (1 जुलाई, 2020), फाइनेंशियल एक्सप्रेस शिवरामकृष्ण शर्मा, लेखा चक्रवर्ती और विद्या बी रामजी
36. निर्वाह बनाम सहायता: राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ, पीडीएस में सुधार किया जा सकता है "- द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 20/7/2020, रामजी कृष्णन, लेखा चक्रवर्ती और विद्या रामजी
37. केंद्रीय बैंकों ने इस संकट पर कैसे प्रतिक्रिया दी है? in (द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 26/6/2020), लेखा चक्रवर्ती और हरिकृष्णन एस
38. लॉकडाउन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, (द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 2 जून, 2020), हरिकृष्णन एस और लेखा चक्रवर्ती
39. जेंडर बजटिंग अधिकार प्राप्त करना, (पब। 16/10/2020 फाइनेंशियल एक्सप्रेस), लेखा चक्रवर्ती, वीना नैयर और कोमल जैन (वर्ल्ड एयर सर्विस, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)
40. कमेंट्री: "इंडिया आइडियाज समिट" को संबोधित करते हुए भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करना। 25/7/2020, ऑल इंडिया रेडियो का बाहरी सेवा प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
41. कमेंट्री: इन्वेस्ट इंडिया, नवंबर 2020, ऑल इंडिया रेडियो का बाहरी सेवा प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
42. कमेंट्री: भारत में आर्थिक सुधार, अक्टूबर 2020, आकाशवाणी का बाहरी सेवा प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

<u>पॉडकास्ट</u>

43. द हिंदू पार्ले में पॉडकास्ट का लिंक है https://www.thehindu.com/podcast/is-the-idea-of-freebies-an-elitist-construct-the-hindu-parley-podcast/article30870980.ece, 2020।

<u>लेवी ब्लॉग</u>

44. 2020 द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया' मल्टीप्लायर इफेक्ट ब्लॉग में, द लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, न्यूयॉर्क - हरिकृष्णन एस और लेखा चक्रवर्ती, जून 2020
45. 2020। आरबीआई महामारी की स्थिति, गुणक प्रभाव ब्लॉग, द लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, न्यूयॉर्क। -लेखा चक्रवर्ती और हरिकृष्णन एस

46. 2020। आउटपुट गैप अपर्याप्त क्यों है? आगामी मल्टीप्लायर इफेक्ट ब्लॉग, द लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, न्यूयॉर्क। - लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर, दिसंबर 2020

<u>ऑस्टैक्स नीति ब्लॉग</u>

47. जेंडर बजटिंग इन मल्टी-लेवल गवर्नेंस, ऑस्टैक्सपॉलिसी: टैक्स एंड ट्रांसफर पॉलिसी ब्लॉग, 28 सितंबर 2020, चक्रवर्ती, लेखा, नैयर, वीणा और जैन, कोमल।
48. 2020 COVID-19 के दौरान चाइल्ड बजटिंग: द केस ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक, ऑस्टैक्सपॉलिसी: टैक्स एंड ट्रांसफर पॉलिसी ब्लॉग, 6 अगस्त 2020 जैकब, जेनेट फरीदा और चक्रवर्ती, लेखा, (2020)।

कर, सब्यसाची

1. कर, सब्यसाची और सोन रे, "भारत में समावेशी संरचनात्मक परिवर्तन: पिछले एपिसोड और भविष्य के प्रक्षेपवक्र" आर्मिडा अलिसजाबाना, कुणाल सेन, एंडी सुमनेर, और एरीफ यूसुफ, एड "डेवलपर की दुविधा", एक पुस्तक में अध्याय (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) आगामी।
2. कर, सब्यसाची और मौसमी दास, "अनटंगलिंग पॉलिसी मिशैप्स: हाउ टू मेक पॉलिसीज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग ए पैन्डेमिक", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 56(7):35-39।
3. कर, सब्यसाची और मौसमी दास, "अनमेकिंग 'मेक इन इंडिया': कमजोर शासन, अच्छे सौदे, और उनके आर्थिक प्रभाव", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55(11):43-53।

<u>प्रकाशन (मीडिया)</u>

4. कर, सब्यसाची, राजेश राज, एसएन और कुणाल सेन, अनमेकिंग मेक इन इंडिया, आइडियाज फॉर इंडिया, 10 जुलाई, 2020।
5. कर, सब्यसाची, और सोन रे, "भारत में डेवलपर की दुविधा - राजनीति और आर्थिक विचारधारा की भूमिका", वाइडर एंगल, दिसंबर, 2020।
6. कर, सब्यसाची, "एक आघात-अवशोषक के रूप में कृषि", हिंदुस्तान टाइम्स, 11 दिसंबर, 2020।
7. कर, सब्यसाची और रुद्रानी भट्टाचार्य, क्या बजट 2021 मजबूत व्यापक आर्थिक स्तंभों पर टिका है?, ब्लूमबर्ग क्विंट, 2 फरवरी, 2021।

जेना, प्रताप रंजन

1. उभरती राजकोषीय प्राथमिकताएं और संसाधन संबंधी चिंताएं: मध्य प्रदेश से राजकोषीय प्रबंधन पर एक परिप्रेक्ष्य, (अभिषेक सिंह के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 303, अप्रैल, 2020।
2. जेना, प्रताप रंजन, डॉली गौर, और दीप्ति रंजन महापात्रा, "नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स: ड्रैग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च।

3. जेना, प्रताप रंजन, डॉली गौर, और दीप्ति रंजन महापात्रा, "भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति की गुणवत्ता और सरकार द्वारा निर्देशित क्रेडिट योजनाओं की भूमिका", जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यू, वित्त मंत्रालय।

चौधरी, मीता

1. स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च पर अंतर-राज्य वितरण में इक्विटी: बिहार और तमिलनाडु का मामला, (जय देव दुबे के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर: 315, जुलाई, 2020।
2. राज्यों के स्वास्थ्य व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भूमिका: उपलब्धियां और मुद्दे, (रंजन कुमार मोहंती के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर: 317, अगस्त, 2020।
3. चौधरी, मीता, और प्रीतम दत्ता, "निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के लिए निहितार्थ", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55 (17), 25 अप्रैल, 2020।
4. स्वास्थ्य व्यय अधिकार प्राप्त करना, वित्तीय एक्सप्रेस, 2020

मुखर्जी, सच्चिदानंद

1. महामारी और जीएसटी राजस्व: संघ और राज्यों के लिए एक आकलन, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 327, दिसंबर 2020।
2. भारत में अनिगमित उद्यमों के औपचारिक ऋण तक पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक: एनएसएसओ के यूनिट-स्तरीय डेटा का विश्लेषण, (शिवानी बडोला के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 326, दिसंबर 2020।
3. भारतीय राज्यों में माल और सेवा कर दक्षता: पैनल स्टोकेस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 310, जुलाई 2020।
4. विकासशील देशों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक, एमपीआरए पेपर नंबर 99607/अप्रैल 2020।
5. मुखर्जी, सच्चिदानंद, 2020। क्या राज्यों के पास जीएसटी मुआवजा अवधि के दौरान जीएसटी संग्रह में अनुमानित वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता है? बाजार एकीकरण की समीक्षा, 11(1-2): 30-53, 25 मई 2020।
6. __________, 2020। राजस्व अनिश्चितता की उपस्थिति में अंतर-सरकारी वित्तीय हस्तांतरण: भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का मामला, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 5 (10): 74-102, अप्रैल 2020।
7. __________, 2020। भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र से पेट्रोलियम मांग और कर संग्रह का अनुमान और प्रक्षेपण, बुनियादी ढांचा विकास जर्नल, 12(1): 39-68, 26 जून 2020।
8. __________, 2020। अंतरराज्यीय बिक्री, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक के कराधान में खामियों को दूर करना, 55(19): 18-20, 18-20, 9 मई 2020।
9. __________, 2020। भारतीय राज्यों में माल और सेवा कर दक्षता: पैनल स्टोकेस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण, भारतीय आर्थिक समीक्षा, 55 (2): 225-251, दिसंबर 2020।

10. __________, 2020। विकासशील देशों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल थॉट, 7 (2): 92-19, जून 2020।
11. मुखर्जी, सच्चिदानंद, और देबाशीष चक्रवर्ती, 2020। व्यापार और पर्यावरण: मुद्दे और उभरते परिप्रेक्ष्य (रायचौधुरी, अजिताव, प्रबीर डे और सुरंजुआन गुप्ता (सं।), "विश्व व्यापार और भारत: बहुपक्षवाद, प्रगति और नीति प्रतिक्रिया", अध्याय 8 , पीपी. 176-198, सेज प्रकाशन: नई दिल्ली। नवंबर 2020)।
12. बडोला, शिवानी, और सच्चिदानंद मुखर्जी, 2021। भारत में अनिगमित उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक, प्रजन-जर्नल ऑफ सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेज, 49 (4): 353-385, मार्च 2021।
13. ___________, 2021। STATA® (अमेज़ॅन किंडल संस्करण, 13 दिसंबर 2020, पेपरबैक - नोटियन प्रेस, 27 फरवरी 2021) का उपयोग करके एनएसएसओ के सर्वेक्षण से यूनिट स्तर डेटा निकालने के लिए मैनुअल।

अमरनाथ, एच.के

1. अमरनाथ, एच.के. 2020. 'संवैधानिक प्रावधान, समानता और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध में मुद्दे: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य" और सभी में बीपी सिंह सहगल, "भारतीय संविधान के तहत केंद्र राज्य संबंध" यूनिवर्सल अकादमिक पुस्तकें प्रकाशक और वितरक, दिल्ली, 2020। (संपादित पुस्तक), पीपी 117-130

साने, रेणुका

1. उपभोक्ता वित्त विवादों में न्यायालयों द्वारा शिकायत निवारण, (करण गुलाटी के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 331, मार्च 2021।
2. साने, रेणुका और एडम फेबेलमैन, 2020। "डिजाइनिंग ए पर्सनल इन्सॉल्वेंसी रिजीम: ए बेसलाइन फ्रेमवर्क", आईबीबीआई ईयरबुक 2020, चैप्टर 31, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रिजीम इन इंडिया: ए नैरेटिव, अक्टूबर 2020।
3. साने, रेणुका, ऋषभ बेली, त्रिशी गोयल, रिधि वर्मा, एनालिसिस इंडियाज केवाईसी फ्रेमवर्क: कैन वी डू थिंग्स बेटर?, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क।

गुप्ता, मनीषो

1. गुप्ता, मनीष, पवनी सचदेवा, अभिषेक सिंह और सुमित अग्रवाल, 2021। भारत में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण का वित्तपोषण: प्रयासों और परिणामों के लिए निहितार्थ, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 335, मार्च 2021।

2. गुप्ता, मनीष, पावनी सचदेवा, अभिषेक सिंह और शिवली सुगंध, 2020। भारत में जैव विविधता संरक्षण: प्रमुख स्रोत और फंड की मात्रा का मानचित्रण, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 311, जुलाई 2020।
3. गुप्ता, मनीष, लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर, राज्य बजट 2018-19 का विश्लेषण - प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां: बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियां, मोनोग्राफ।
4. गुप्ता, मनीष, क्या राज्यों को 14% राजस्व गारंटी उचित है?, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम में। एलवी, नंबर 47, पेज 18-21, नवंबर 2020।
5. FC-XV अनुशंसाओं का विश्लेषण: स्थिरता, निरंतरता और परिवर्तन (माइमोग्राफ)।
6. पोस्ट कोविड राजकोषीय वास्तुकला और एफआरबीएम: पंद्रहवें वित्त आयोग (माइमोग्राफ) की सिफारिशों का विश्लेषण।

भट्टाचार्य, रुद्राणी

1. समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, (सताद्रू सिकदर और अभिजीत सेन गुप्ता के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 321, अक्टूबर, 2020।
2. भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान: वेक्टर त्रुटि सुधार तंत्र बनाम। गैर-स्थिर समय श्रृंखला के लिए गतिशील कारक मॉडल दृष्टिकोण, (मृगांक्षी कपूर के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 321, अक्टूबर, 2020।
3. भट्टाचार्य, रुद्रानी और ऋचा जैन, 2020। क्या मौद्रिक नीति खाद्य मुद्रास्फीति को स्थिर कर सकती है? उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से साक्ष्य, आर्थिक मॉडलिंग, 89: 122-141, जुलाई, 2020।
4. भट्टाचार्य, रुद्रानी और अजय के, साहू, 2020। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की कीमतों और अल्पकालिक पूर्वानुमानों का विश्लेषण, अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा, 2020-21: Q1 (15 मई, 2020)।
5. भट्टाचार्य, रुद्रानी और अजय के, साहू, 2020। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की कीमतों और अल्पकालिक पूर्वानुमानों का विश्लेषण, अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा, 2020-21: Q1 (25 जून, 2020 अपडेट)
6. भट्टाचार्य, रुद्रानी और अजय के, साहू, 2020। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की कीमतों और अल्पकालिक पूर्वानुमानों का विश्लेषण, अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा, 2020-21: दूसरी तिमाही (25 सितंबर, 2020 अपडेट)
7. भट्टाचार्य, रुद्रानी और सुदीप्तो मुंडले, 2020। हिस्टैरिसीस और त्रैमासिक, वार्षिक और मध्यम से लंबी अवधि के विकास आउटलुक, अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा, 2020-21: दूसरी तिमाही (25 सितंबर, 2020 अपडेट) .
8. भट्टाचार्य, रुद्रानी और अजय के, साहू, 2020। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की कीमतों और अल्पकालिक पूर्वानुमानों का विश्लेषण, भारतीय अर्थव्यवस्था की एनसीएईआर 2020-21 मध्य-वर्ष की समीक्षा। (21 दिसंबर, 2020)।
9. भट्टाचार्य, रुद्रानी और सुदीप्तो मुंडले, 2020। जीडीपी पूर्वानुमान, हिस्टैरिसीस और सुधार, भारतीय अर्थव्यवस्था की एनसीएईआर 2020-21 मध्य-वर्ष की समीक्षा। (21 दिसंबर, 2020)।

बोस, सुकन्या

1. प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्र-राज्य खर्च: क्या यह पूरक या स्थानापन्न है? (मानसी बेरा और प्रियंता घोष के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 320, सितंबर, 2020।
2. पिरामिड के तल पर बाहर निकलें: दिल्ली में प्राथमिक स्कूली शिक्षा के संदर्भ में अनुभवजन्य अन्वेषण, (प्रियंता घोष और अरविंद सरदाना के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 306, मई, 2020।
3. बोस, सुकन्या, प्रियंता घोष और अरविंद सरदाना, 2020। आरटीई और संसाधन आवश्यकताएँ: अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलोर द्वारा प्रायोजित द वे फॉरवर्ड, एनआईपीएफपी और एकलव्य सहयोगी अध्ययन। एक पुस्तक में, एकलव्य प्रकाशक, मध्य प्रदेश, 2020
4. बोस, सुकन्या, प्रियंता घोष और अरविंद सरदाना, 2020। शिक्षा के अधिकार का वित्तपोषण: पंद्रहवें वित्त आयोग की भूमिका, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55 (37): 44-52, 12 सितंबर, 2020।
5. बोस, सुकन्या और प्रियंता घोष, 2020। इक्विटेबल फाइनेंसिंग की ओर, "इंडिया स्पॉटलाइट रिपोर्ट ऑन एसडीजी4, 2020" में, एचएलपीएफ 2020 के लिए तैयार, एशिया साउथ पैसिफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एंड एडल्ट एजुकेशन द्वारा प्रकाशित। क्वेज़ोन सिटी, फिलीपींस और राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन, दिल्ली।
6. ई-प्रकाशन। http://nceindia.org.in/wp-content/uploads/2021/09/Spotlight-Report-2020.pdf

सप्रे, अमेय

1. नीली अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के लिए कार्यप्रणाली और आकलन ढांचा। TERI-KAS चतुर्भुज संवाद श्रृंखला में, फरवरी, 2021
2. बिहार और उसके निर्धारकों में कृषि उत्पादकता: महेंद्र सिंह, दीप मुखर्जी के साथ एक जिला स्तरीय विश्लेषण, सतत विकास में समकालीन मुद्दों में पुस्तक अध्याय: भारत का मामला, रूटलेज, 2021, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, जनवरी, 2021
3. महामारी के समय में नीति विश्लेषण के लिए डेटा, अनुच्छेद, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (आईएसपीपी), 21 दिसंबर, 2020।
4. भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के मौसमी समायोजन से हमें क्या हासिल होता है?, (राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 322, अक्टूबर, 2020।

टंडन, सुरांजलि

1. पिलर वन ब्लूप्रिंट: टुवड्र्स ग्लोबल सॉल्यूशन?, ओईसीडी में, अक्टूबर 2020
2. टंडन, सुरांजलि और स्मारक स्वैन, 2020। ट्रांसफर प्राइसिंग में टर्नओवर फ़िल्टर लागू करना, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग जर्नल, आईबीएफडी, सितंबर 2020।

3. टंडन, सुरांजलि , 2020। क्या कर प्रणाली तटस्थ है: भारत में चुनिंदा निवेश कोषों का विश्लेषण, वित्त और पूंजी बाजार, आईबीएफडी, नीदरलैंड, 2020।
4. कंपनियां भारत में पूंजी कैसे जुटाती हैं? (अक्षय गर्ग के साथ सह-लेखक), (माइमोग्राफ)
5. अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एजेंडा COVID-19 के बाद (माइमोग्राफ)
6. राष्ट्रमंडल में कर विवाद समाधान (माइमोग्राफ)
7. IFSC में सस्टेनेबल मंगेतर का भविष्य (माइमोग्राफ)
8. चुनिंदा उभरते देशों में पूंजीगत लाभ के लिए कर उपचार (माइमोग्राफ)

सिकदर, सतद्रु

1. समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, (रुद्रानी भट्टाचार्य और अभिजीत सेन गुप्ता के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 321, अक्टूबर, 2020।
2. लॉकडाउन के दौरान रिवर्स माइग्रेशन: सार्वजनिक नीतियों का एक स्नैपशॉट, (प्रेक्षा मिश्रा के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 318, सितंबर, 2020।
3. (प्रेक्षा मिश्रा के साथ सह-लेखक), 2020। रिवर्स माइग्रेशन: महामारी, श्रम और विकास के दौरान चुनौतियां और सार्वजनिक नीतियां, 27 (2), दिसंबर 2020।
4. मुंडले, सुदीप्तो और सतद्रू सिकदर, 2020। सब्सिडी, मेरिट गुड्स एंड द फिस्कल स्पेस फॉर रिवाइविंग ग्रोथ: एन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया (ईडीआई), वॉल्यूम 249, उमा कपिला द्वारा संपादित, अकादमिक फाउंडेशन, 2020)
5. ________________, 2020। रिवाइविंग ग्रोथ के लिए समावेशी राजकोषीय समायोजन: भारत की अर्थव्यवस्था में 2019-20 के बजट का आकलन: महान मंदी?, भारत में आर्थिक विकास (ईडीआई), खंड 248, उमा कपिला द्वारा संपादित, अकादमिक फाउंडेशन, 2020।
6. (प्रवीन झा के साथ सह-लेखक), 2020। कंटेम्परेरी कैपिटलिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज: सम रिफ्लेक्शन्स ऑन इंडिया, इन डेवलपमेंट चैलेंजेज ऑफ इंडिया आफ्टर पच्चीस इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स: इनइक्वलिटी, लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, नृपेंद्र किशोर मिश्रा द्वारा संपादित, स्प्रिंगर, सिंगापुर, 2020।
7. ____________, 2020। भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक प्रावधान: भारत में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा में एक स्थिति आकलन: मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं, जंध्याला बीजी तिलक, स्प्रिंगर, 2020 द्वारा संपादित।

मोहंती, रंजन कुमारी

1. राज्यों के स्वास्थ्य व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भूमिका: उपलब्धियां और मुद्दे, (मीता चौधरी के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर: 317, अगस्त, 2020।
2. मोहंती, रंजन कुमार और एस. पांडा, 2020। "सार्वजनिक ऋण भारतीय मैक्रोइकॉनॉमी को कैसे प्रभावित करता है? एक संरचनात्मक VAR दृष्टिकोण "। मार्जिन: द जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 14 (3): 253-284, अगस्त।

3. मोहंती, रंजन कुमार, और एनआर भानुमूर्ति, 2020। "भारत में उप-राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक व्यय क्षमता का आकलन: क्या शासन मायने रखता है?, सार्वजनिक मामलों के जर्नल, 21 (2), 11 जून 2020, e2173।
4. मोहंती, आरके, बीके साहू, पीके चौधरी। 2020 "भारत के (इको) मैक्रोइकॉनॉमिक प्रदर्शन सूचकांक का आकलन: एक डेटा लिफाफा विश्लेषण दृष्टिकोण"। जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, 21(1), e2122.

अमनदीप कौर

1. पारिस्थितिक वित्तीय हस्तांतरण और राज्य-स्तरीय बजटीय व्यय: भारत में फ्लाईपेपर प्रभाव के लिए साक्ष्य, (रंजन कुमार मोहंती, लेख चक्रवर्ती, दिव्य रंगन के साथ) एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 332, मार्च 2021
2. कोविड -19 आर्थिक प्रोत्साहन और राज्य-स्तरीय बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन: दक्षता मापदंडों का विश्लेषण, (लेखा चक्रवर्ती, दिव्य रंगन के साथ), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 333, मार्च 2021
3. राज्य के बजट 2018-19 का विश्लेषण: प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां (लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता के साथ), (2020 .)
4. पोषण सार्वजनिक व्यय समीक्षा: वित्त मंत्रालय और अन्य संस्थान के लिए गुजरात से साक्ष्य (लेखा चक्रवर्ती, रुजेल श्रेष्ठ, कोमल जैन, जेनेट फरीदा जैकब, अनिंदिता घोष के साथ) (यह रिपोर्ट गुजरात में अनुसंधान परियोजना "पोषण-प्रति" का एक परिणाम है। वित्त विभाग, गुजरात सरकार और यूनिसेफ गुजरात द्वारा शुरू किया गया)।

पांडे, रीटा (सेवानिवृत्त) - सीनियर फेलो

1. "ग्रीनिंग पोस्ट कोविड -19 इकोनॉमिक रिकवरी इन इंडिया-ए न्यू वायरस ए न्यू इंडिया", डिस्कशन पेपर, टेरी, नई दिल्ली, मई 2020 (सह-लेखक)।
2. "कोविड-19 महामारी के दौरान फसल पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता में उछाल को संबोधित करना: पंजाब का एक मामला", (शैली केडिया और अनुजा मल्होत्रा के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 308, जून 2020; और पंजाब की अर्थव्यवस्था पर सीडीईआईएस नीति संक्षिप्त श्रृंखला, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, अक्टूबर 2020।
3. "भारत में जैव विविधता संरक्षण: प्रमुख स्रोतों और फंड की मात्रा का मानचित्रण", (मनीष गुप्ता, पावनी सचदेवा, अभिषेक सिंह और शिवाजी सुगंध के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 311, जुलाई 2020।
4. "भारत में वित्त पोषण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण: प्रयासों और परिणामों के लिए निहितार्थ", (मनीष गुप्ता, पावनी सचदेवा, अभिषेक सिंह और सुमित अग्रवाल के साथ सह-लेखक), एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर 335, मार्च 2021।
5. "कोविड-19 के समय के दौरान भारत में पराली जलाने और खराब वायु गुणवत्ता का प्रभाव", ग्रीन ग्रोथ नॉलेज प्लेटफॉर्म, यूएनईपी, जुलाई 2020। (शैली केडिया और अनुजा मल्होत्रा के साथ सह-लेखक)।

6. “शेपिंग पोस्ट COVID-19 डेवलपमेंट पैराडाइम इन इंडिया: सम इम्पेरेटिव्स फॉर ग्रीनिंग द इकोनॉमिक रिकवरी, मिलेनियल एशिया, सेज प्रकाशन, अक्टूबर 2020। (शैली केडिया और रिया सिन्हा के साथ सह-लेखक)।
7. पुस्तक में अध्याय: पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन में नवाचारों की आवश्यकता: सुखपाल सिंह, लखविंदर सिंह और कमल वट्टा द्वारा संपादित खंड "कोविड -19 महामारी और आर्थिक विकास - भारतीय पंजाब के लिए उभरते सार्वजनिक नीति पाठ" में COVID-19 महामारी से सबक। , स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर के तहत पालग्रेव मैकमिलन द्वारा प्रकाशित (शैली केडिया और अनुजा मल्होत्रा के साथ सह-लेखक) (आगामी)।

पांडे, राधिका (फेलो-I)

1. इला पटनायक, और राधिका पांडे, 2020। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के चार साल, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर: 325, नवंबर, 2020।
2. इला पटनायक, और राधिका पांडे, 2020। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर बढ़ते हुए, एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर नंबर: 316, अगस्त, 2020।
3. भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के मौसमी समायोजन से हमें क्या लाभ होता है? WP 322, अक्टूबर, अक्टूबर, 2020, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, अमेय सप्रे

अनुलग्नक VII: स्टाफ सदस्यों की सूची (31 मार्च 2021 तक)

संकाय

1. डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती	2. निदेशक (15.10.2020 को शामिल हुए)
3. डॉ. रथिन रॉय	निदेशक (31.08.2020 को इस्तीफा दे दिया)
4. डॉ. सब्यसाची कर	प्रोफेसर (आरबीआई चेयर) (01.07.2020 को शामिल हुए)
5. डॉ (सुश्री) आर कविता राव	प्रोफ़ेसर
6. डॉ.(सुश्री) इला पटनायक	प्रोफ़ेसर
7. डॉ अजय शाह	प्रोफेसर (15.08.2020 को इस्तीफा दे दिया)
8. डॉ. एन.आर. भानुमूर्ति	प्रोफेसर (22.06.2020 से प्रतिनियुक्ति पर)
9. डॉ. (सुश्री) लेख चक्रवर्ती	प्रोफ़ेसर
10. डॉ प्रताप रंजन जेना	एसोसिएट प्रोफेसर
11. डॉ. (सुश्री) मीता चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर
12. डॉ सच्चिदानंद मुखर्जी	एसोसिएट प्रोफेसर
13. डॉ मुकेश कुमार आनंद	एसोसिएट प्रोफेसर
14. डॉ. एच.के. अमरनाथ	एसोसिएट प्रोफेसर
15. डॉ. रेणुका साने	एसोसिएट प्रोफेसर
16. डॉ मनीष गुप्ता	सहायक प्रोफेसर
17. डॉ रुद्रानी भट्टाचार्य	सहायक प्रोफेसर
18. डॉ भारती भूषण दास	सहायक प्रोफेसर (04.06. 2020 को इस्तीफा दे दिया)
19. डॉ सुकन्या बोस	सहायक प्रोफेसर
20. डॉ. सतद्रु सिकदर	सहायक प्रोफेसर
21. डॉ. रंजन कुमार मोहंती	सहायक प्रोफेसर (30.09.2020 को इस्तीफा दे दिया)
22. डॉ अमेय सप्रे	सहायक प्रोफेसर
23. डॉ. सुरांजलि टंडन	सहायक प्रोफेसर
24. डॉ श्रुति त्रिपाठी	अर्थशास्त्री
25. डॉ. दिनेश कुमार नायक	अर्थशास्त्री
26. डॉ. ए. श्री हरि नायडू	अर्थशास्त्री
27. डॉ. भाबेश हजारिका	अर्थशास्त्री
28. सुश्री अमनदीप कौर	अर्थशास्त्री

प्रशासनिक कर्मचारी

1. सुश्री अलका माटा	सचिव
2. श्री अशोक कुमार खंडूरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (29.12.2020 को इस्तीफा दिया)
3. श्री विक्रम सिंह चौहान	निदेशक के निजी सचिव
4. श्री प्रवीण कुमार	निजी सचिव
5. श्री परविंदर कपूर	निजी सचिव
6. श्री बीएस रावत	लेखा अधिकारी

7. सुश्री प्रोमिला राजवंशी	आशुलिपिक ग्रेड I
8. सुश्री कविता इस्सार	आशुलिपिक ग्रेड I
9. श्री अनुरोध शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड II
10. श्री दर्शन सिंह पंवार	आशुलिपिक ग्रेड II (प्रतिनियुक्ति पर)
11. सुश्री अमिता मन्हास	आशुलिपिक ग्रेड II
12. श्री कपिल कुमार आहूजा	आशुलिपिक ग्रेड II
13. सुश्री रुचि आनंद	सहायक
14. सुश्री उषा माथुर	आशुलिपिक ग्रेड II
15. श्री वसीम अहमद	स्टेनो टाइपिस्ट-
16. सुश्री दीपिका राय	सहायक
17. श्री शुभम कुमार वर्मा	क्लर्क (लेखा)
18. सुश्री मोनिका माथुर	रिसेप्शनिस्ट-सह- दूरभाष ऑपरेटर
19. श्री राजू	चालक
20. श्री परशु राम तिवारी	चालक
21. श्री मोहन सिंह बिष्ट	फोटोकॉपी ऑपरेटर
22. श्री के.एन.मिश्रा	छात्रावास परिचारक
23. श्री किशन सिंह	छात्रावास परिचारक
24. श्री शिव बहादुर	माली (30.06.2020 को सेवानिवृत्त)
25. श्री शिव प्रताप	माली
26. श्री रमेश कुमार	माली
27. सुश्री कमला तिवारी	मैसेंजर (30.04.2020 को सेवानिवृत्त)
28. श्री हरीश चांद	मैसेंजर
29. श्री अजय कुमार	मैसेंजर
30. श्री मुकेश	मैसेंजर
31. श्री राजेंद्र कुमार	मैसेंजर
32. श्री बिशम्बर पाण्डेय	चौकीदार
33. श्री सुरेंद्र सिंह यादव	चौकीदार

कंप्यूटर यूनिट

1. श्री एन.के. सिंह	ईडीपी प्रबंधक
2. श्री रॉबी थॉमस	अधीक्षक

पुस्तकालय कर्मचारी

1. सुश्री सोनम सिंह	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (15.02.2021 को कार्यभार ग्रहण)
2. सुश्री सारिका गौर	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
3. श्री पी सी यूपाध्याय	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
4. सुश्री मंजू ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक

5. सुश्री आजाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
6. श्री राजन ढाका	सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट
7. श्री नदीम अली	जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट
8. श्री पूरन सिंह	मैसेंजर

शैक्षणिक कर्मचारी: संविदा

1. श्री डी.पी.सेनगुप्ता	फैलो I
2. डॉ. राधिका पाण्डेय	फैलो I
3. श्री प्रमोद सिन्हा	फैलो II
4. सुश्री रचना शर्मा	फैलो II
5. श्री जय देव दुबे	फैलो II
6. श्रीमान दीवान चंद	फेलो-II (31.12.2020 को कार्यमुक्त)
7. श्री देवेंद्र दामले	रिसर्च फैलो
8. श्री आशिम कपूर	रिसर्च फैलो
9. सुश्री फैजा रेहमान	रिसर्च फेलो (09.11.2020 को कार्यमुक्त)
10. सुश्री हरलीन कौर	रिसर्च फेलो (06.11.2020 को कार्यमुक्त)
11. श्री विशाल त्रेहान	रिसर्च फेलो (31.07.2020 को कार्यमुक्त)
12. श्री सुदीप्तो बनर्जी	रिसर्च फेलो (31.12.2020 को कार्यमुक्त)
13. सुश्री बिदिशा मंडल	रिसर्च फैलो
14. सुश्री भव्या शर्मा	रिसर्च फैलो
15. सुश्री तन्वी ब्रम्हे	रिसर्च फैलो
16. सुश्री कनिका गुप्ता	रिसर्च फैलो
17. श्री प्रीतम दत्ता	फैलो II
18. सुश्री प्रिया यादव	रिसर्च फेलो (31.03.2021 को कार्यमुक्त)
19. सुश्री राशि मित्तल	रिसर्च फैलो
20. सुश्री डी प्रियदर्शिनी	फेलो-II (31.03.2021 को कार्यमुक्त)
21. सुश्री अमृता पिल्लै	रिसर्च फैलो
22. सुश्री अनमोल राठौर	रिसर्च फेलो (07.02.021 को कार्यमुक्त)
23. श्री रघुनाथ शेषाद्री	रिसर्च फेलो (30.06.2020 को कार्यमुक्त)
24. श्री ऋषभ बेली	फैलो II
25. श्री सारंग मोहरि	रिसर्च फेलो (13.11.2020 को कार्यमुक्त)
26. सुश्री मनप्रीत कौर	रिसर्च फेलो (02.11.2020 को कार्यमुक्त)
27. श्री रत्नेश	सीनियर फेलो
28. डॉ रीता पाण्डेय	सीनियर फेलो (31.03.2021 को कार्यमुक्त)
29. सुश्री मधुर मेहता	रिसर्च फैलो
30. श्री मोहम्मद अजहरुद्दीन खान	रिसर्च फेलो (30.06.2020 को कार्यमुक्त)
31. श्री राहुल चक्रवर्ती	रिसर्च फैलो
32. श्री अभिषेक	रिसर्च फेलो (01.02.021 को कार्यमुक्त)
33. सुश्री सुनेत्रा घटक	रिसर्च फैलो
34. श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव:	रिसर्च फेलो (28.06.2020 को कार्यमुक्त)

35. सुश्री सृष्टि शर्मा	रिसर्च फैलो
36. श्री रोहित दत्ता	रिसर्च फैलो
37. सुश्री मेधा राजू	रिसर्च फेलो (13.11.2020 को कार्यमुक्त)
38. श्री कार्तिक सुरेश	रिसर्च फैलो
39. सुश्री मौमिता दास	रिसर्च फेलो (20.01.2020 को कार्यमुक्त)
40. सुश्री रजनी पाण्डेय	रिसर्च फेलो (07.12.2020 को कार्यमुक्त)
41. श्री वरुण सेन बहल	रिसर्च फेलो (29.02.2020 को कार्यमुक्त)
42. श्री तुषार आनंद	रिसर्च फैलो
43. सुश्री त्रिशी गोयल	स्वतंत्र सलाहकार (31.05.2020 को कार्यमुक्त)
44. सुश्री कुसन बिस्वास	रिसर्च फेलो (23.07.2020 को कार्यमुक्त)
45. डॉ. जेनेट फरीदा जैकब	रिसर्च फेलो (18.01.2021 को कार्यमुक्त)
46. सुश्री सबरनी चौधरी:	रिसर्च फैलो
47. सुश्री वंदना टीआर	रिसर्च फेलो (4.8.2020 को कार्यमुक्त)
48. श्री नीरव पंड्या	कानूनी स्वतंत्र सलाहकार
49. सुश्री अनिंदिता घोष	रिसर्च फेलो (20.12.2020 को कार्यमुक्त)
50. सुश्री गुंतास कौर उप्पल	रिसर्च फैलो
51. सुश्री अंशी शर्मा	रिसर्च फेलो (27.8.2020 को कार्यमुक्त)
52. श्री मयंक जैन	रिसर्च फेलो (31.03.2021 को कार्यमुक्त)
53. सुश्री संप्रीत कौर	रिसर्च फैलो
54. सुश्री विभा कुमारी	रिसर्च फेलो (30.10.2020 को कार्यमुक्त)
55. सुश्री शिवानी बडोला	रिसर्च फैलो
56. श्री गणेश गोपालकृष्णन	रिसर्च फैलो
57. सुश्री स्मृति मेहरा	रिसर्च फैलो
58. श्री प्रियंता घोष	रिसर्च फेलो (09.12.2020 को कार्यमुक्त)
59. सुश्री मिथिला ए सारा	रिसर्च फेलो (13.01.2020 को शामिल हुए)
60. सुश्री अमानी बशीर	रिसर्च फेलो (31.03.2021 को कार्यमुक्त)
61. श्री मनोहर बोडा	रिसर्च फेलो (18.08.2020 को कार्यमुक्त)
62. सुश्री कनिका कुमार	रिसर्च फेलो (17.03.2021 को कार्यमुक्त)
63. सुश्री मौलश्री सिंह	रिसर्च फेलो (13.11.2020 को कार्यमुक्त)
64. सुश्री अंशु शुक्ला	रिसर्च फेलो (05.03.2020 को कार्यमुक्त)
65. श्री उत्कर्ष	रिसर्च फेलो (22.10.2020 को कार्यमुक्त)
66. सुश्री आयुषी जैन	रिसर्च फेलो (11.09.2020 को कार्यमुक्त)
67. श्री विराज जोशी	रिसर्च फेलो (15.06.2020 को कार्यमुक्त)
68. श्री दिव्य रंगन	रिसर्च फैलो
69. श्री आदित्य रेड्डी नल्लावेली	रिसर्च फेलो (17.03.2021 को कार्यमुक्त)
70. श्री अक्षय गर्ग	रिसर्च फेलो (26.02.2021 को कार्यमुक्त)
71. डॉ.द्वीपोबोती ब्रह्मा	फेलो- II (01.07.2020 को शामिल हुए)
72. सुश्री रिधि वर्मा	रिसर्च फेलो (07.07.2020 को शामिल हुए)
73. श्री सिद्धार्थ नायडू	रिसर्च फेलो (08.12.2020 को कार्यमुक्त)
74. सुश्री अनन्या गोयल	रिसर्च फेलो (01.08.2020 को शामिल हुए)
75. श्री करण गुलाटी	रिसर्च फेलो (01.07.2020 को शामिल हुए)

76. सुश्री नमिता गोयल	रिसर्च फेलो (31.10.2020 को कार्यमुक्त)
77. सुश्री गरिमा जसुज	रिसर्च फेलो (02.09.2020 को कार्यमुक्त)
78. सुश्री रागिनी	रिसर्च फेलो (04.01.2021 को शामिल हुए)
79. सुश्री गरिमा नैन	रिसर्च फेलो (21.01.2021 को शामिल हुए)
80. श्री एम. वासुकी नंदन	रिसर्च फेलो (15.02.2021 को शामिल हुए)
81. सुश्री अनुजा मल्होत्रा	रिसर्च फेलो (26.02.2021 को कार्यमुक्त)
82. श्री यश जालुका	रिसर्च फेलो (01.03.2021 को शामिल हुए)
83. श्री मनीष कुमार प्रसाद	रिसर्च फेलो (10.03.2021 को शामिल हुए)

प्रशासनिक कर्मचारी: संविदा

1. सुश्री लता बालासुब्रमण्यम	कार्यक्रम सहायक
2. सुश्री मीना	डाटा एंट्री ऑपरेटर (02.07.2020 को कार्यमुक्त)
3. श्री कौशल पायल	सलाहकार (प्रशासन) (08.09.2020 को कार्यमुक्त)
4. श्री कुलदीप सिंह	तथ्य दाखिला प्रचालक
5. सुश्री दीपिका गुप्ता	सलाहकार (लेखा)
6. श्री रोहित भदौरिया	सलाहकार (प्रशासन)
7. श्री हरि शंकर गुप्ता	सलाहकार (प्रशासन)
8. श्री नवीन भल्ला	सलाहकार (प्रशासन) (29.12.2020 को शामिल हुए)
9. श्री आर. मानिक	सलाहकार (प्रशासन) (29.12.2020 को शामिल हुए)
10. श्री मनीष वी ऍम	आईटी सलाहकार)
11. श्री सुरेश कुमार	सलाहकार (कार्यक्रम सहायक)
12. सुश्री श्रेया चंद्र	तथ्य दाखिला प्रचालक

अनुलग्नक VIII: प्रायोजक, कॉर्पोरेट, स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची (31 मार्च 2021 तक)

प्रायोजक सदस्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. कर्नाटक
3. केरल
4. महाराष्ट्र

7. ओडिशा
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
1 1. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य

1. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
3. आई सी आई सी आई बैंक प्राइवेट लिमिटेड

स्थायी सदस्य-राज्य/संघ शासित प्रदेश

1. अरुणाचल प्रदेश
2. गोवा, दमन और दीव
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नगालैंड

साधारण सदस्य - राज्य/संघ क्षेत्र

1. हरियाणा
2. त्रिपुरा सरकार

अन्य

1. मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

अनुलग्नक IX: वित्त और लेखा

वित्तीय वर्ष -202-21 के लिए संस्थान के खातों का विवरण, संस्थान के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित, मेसर्स। अनीश आशीष एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिश आशीष एंड कंपनी

के -28, तीसरी मंजिल, सरिता विहार, नई दिल्ली -110076
हैंडसेट: + 91-9818395893, + 91-9810261432
लैंडलाइन: 011-29942700, 011-41033026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान जनरल बॉडी के सभी सदस्य,

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

मत

हमारे द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (इकाई) के अंतर्गत पंजीकृत विनय के वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार संक्षेप सहित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार, प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2021 की यथास्थिति को इकाई की वित्तीय स्थिति एवं वर्ष के दौरान इसके वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मत का आधार

हमारे द्वारा किया गया लेखापरीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसरण में किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में प्रस्तुत लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में वर्णित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में हम इकाई से स्वतंत्र हैं तथा हमारे द्वारा अपने अन्य आचार उत्तरदायित्वों का निर्वाह आचार संहिता के अनुरूप किया गया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षण प्रमाण हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व

भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई के इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के प्रति प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सत्य एवं स्वच्छ स्वरूप में एवं किसी भी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्याकथन, किसी जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति करने से संबद्ध डिजाइन, आंतरिक नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया जाना शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सोसायटी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने,गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से संबंद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा इकाईको बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए

गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारी ही इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं-:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्य परक हों । पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठगांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं ।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना ।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए इकाई की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसीप्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परिक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम इकाईकी प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित इंडएएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंडएएस वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य अपेक्षाओं की रिपोर्ट

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने, वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

(ii) हमारे मतानुसार, इकाई द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण विधि अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है तथा ऐसा इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है; तथा

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

अनीश आशीष एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर 002535N

--ह./---

आशीष गुप्ता

साझेदार

सदस्यता संख्या- 503829

यूडीआईएन: 21503829AAAAHQ8464

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23 दिसंबर 2021

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31-मार्च-21 की स्थिति	31-मार्च-20 की स्थिति
कोरप्स/पूंजी निधि तथा देनदारियां			
कोरप्स/पूंजी निधि	1	133,376,532	126,287,325
आरक्षित तथा अधिशेष	2	210,810,714	178,810,714
आस्थगित आय	3	16,764,168	16,887,656
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	4	341,547,253	326,361,894
वर्तमान देनदारियां तथा प्रावधान	5	168,209,034	140,739,109
जोड़		**870,707,701**	**789,086,698**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	6	63,493,588	65,240,074
निवेश–धर्मादा/विनिश्चित निधियां	7	391,887,062	353,116,215
निवेश–अन्य	8	230,765,770	210,626,008
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	9	184,561,281	160,104,401
जोड़		**870,707,701**	**789,086,698**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान की ओर से

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(बीएस रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डॉ पिनाकी चक्रवर्ती)	(डॉ उर्जित पटेल)।
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

अनीश आशीष एंड कंपनीलिए
सनदी लेखाकार
फर्म के पंजीकरण संख्या 002535N

(आशीष गुप्ता)
भागीदार
एम. संख्या 503829
यूडीआईएन: 21503829AAAAHQ8464
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसंबर 2021

राष्टीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2019 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31-मार्च-21 की स्थिति	31-मार्च-20 की स्थिति
आय			
केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान	10	88,926,623	98,058,997
अकादमिक कार्यकलापों से आय	11	130,967,871	169,025,136
अर्जित ब्याज	12	19,089,972	17,772,546
अन्य आय	13	18,105,683	23,890,633
जोड़		**257,090,149**	**308,747,312**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	61,714,931	85,379,889
अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय	15	120,170,070	162,794,356
प्रशासनिक व्यय	16	32,313,708	39,620,361
मूल्यह्रास	6	3,782,326	3,365,313
जोड़		**217,981,035**	**291,159,919**
शेष वर्ष के संबंध में व्यय की तुलना में आय की अधिकता के नाते शेष		39,109,114	17,587,393
घटा : पिछली अवधि की मदें		19,907	281,015
व्यय की तुलना में आय की अधिकता		**39,089,207**	**17,306,378**
घटा : अतिरिक्त देनदारी के लिए अंतरित राशि		16,000,000	9,000,000
घटा : साधारण रिजर्व के लिए अंतरित राशि		16,000,000	7,000,000
कोरप्स/पूंजी निधि में ले जाया गया अधिशेष के नाते शेष		**7,089,207**	**1,306,378**
महत्वपूर्ण रेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

राष्टीय लोक वित्त नीति संस्थान की ओर से

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(बीएस रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डॉ पिनाकी चक्रवर्ती)	(डॉ उर्जित पटेल)।
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

अनीश आशीष एंड कंपनीलिए
सनदी लेखाकार
फर्म के पंजीकरण संख्या 002535N

(आशीष गुप्ता)

भागीदार
एम. संख्या 503829
यूडीआईएन: 21503829AAAAHQ8464
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसंबर 2021

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

धनराशि रूपए में

		31-मार्च-21 की स्थिति		31-मार्च-20 की स्थिति
अनुसूची 1 . कोरप्स/पूंजी निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	126,287,325		124,980,947	
जमा : आय और व्यय खाते से अंतरित अधिशेष	7,089,207		1,306,378	
		133,376,532		126,287,325
जोड़		**133,376,532**		**126,287,325**
अनुसूची-2 : रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	71,189,863		62,189,863	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	16,000,000		9,000,000	
		87,189,863		71,189,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	107,120,851		100,120,851	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	16,000,000		7,000,000	
		123,120,851		107,120,851
ग. : मृत कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायतार्थ रिजर्व के लिए अंतरित राशि		**500,000**		**500,000**
जोड़		**210,810,714**		**178,810,714**
अनुसूची-3 : आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए इमारत के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	16,444,537		16,758,416	
घटा : ऐसी परिसंपत्तियों पर मूलह्रास के समकक्ष राशि आय और व्यय खाते को अंतरित	313,879		313,879	
		16,130,658		16,444,537
पूंजी परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	443,119		683,887	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	498,320		-	
घटा : आय और व्यय खाते को अंतरित ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के समकक्ष राशि	307,929		240,768	
		633,510		443,119
जोड़		**16,764,168**		**16,887,656**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र् का भाग है

अनुसूची-4 : विनिश्चित/धर्मादा निधियां

धनराशि रूपयों में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन धर्मादा निधि	सरकारी धर्मादा निधि	भारतीय रिजर्व बैंक धर्मादा निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	बिमल बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कोरप्स निधि	राजा चेलैय्रया वार्षिक व्याख्यान माला और भ्रमणकारी प्रोफेसरशिप निधि	जोड़
प्रारंभिक निधि	6,177,924	10,000,000	40,000,000	727,406	420,000	50,000	29,300	120,000,000	20,000,000	
क- निधियों का प्रारंभ	15,768,986	10,000,000	66,865,258	2,576,967	1,485,498	111,208	71,250	195,127,989	34,354,738	326,361,894
ख-निधि में अभिवृद्धियां										
(i)-निधि में अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)-निवेशों से आय	1,152,521	768,253	5,048,080	157,916	92,111	6,774	4,065	13,116,999	2,370,471	22,717,190
जोड. -क+ख	**16,921,507**	**10,768,253**	**71,913,338**	**2,734,883**	**1,577,609**	**117,982**	**75,315**	**208,244,988**	**36,725,209**	**349,079,084**
ग-निधि के उद्रदेश्य हेतु उपयोग/व्यय	111,986	768,253	3,434,723	-	-	-	-	3,206,750	10,119	7,531,831
जोड. - ग	**111,986**	**768,253**	**3,434,723**	-	-	-	-	**3,206,750**	**10,119**	**7,531,831**
वर्ष के अंत में निवल शेष										
वर्ष का - क+ख+ग	**16,809,521**	**10,000,000**	**68,478,615**	**2,734,883**	**1,577,609**	**117,982**	**75,315**	**205,038,238**	**36,715,090**	**341,547,253**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

		31.3.2021 की स्थिति	31.3.2020 की स्थिति
अनुसूची-5 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
क. वर्तमान देयताएं			
1	वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	4,051,241	5,076,221
2	बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	997,613	1,605,066
3	परियोजना अनुदान-(देखें अनुसूची-5 - क)	61,903,757	63,941,814
4	केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान (देखें अनुसूची-5-ख)	32,636,540	-
5	सांविधिक देय	4,871,529	4,892,479
6	अन्य वर्तमान देयताएं	17,182,220	18,731,529
	जोड़	**121,642,900**	**94,247,109**
ख. प्रावधान			
1	छुट्टी नकदीकरण	46,566,134	46,492,000
	जोड़	**46,566,134**	**46,492,000**
	कुल जोड़	**168,209,034**	**140,739,109**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

		1 अप्रैल, 2020 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2020 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2021 को वसूली योग्य	31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त
1	आर्थिक वैश्वीकरण एवं आर्थिक विकास -आईसीएसएसआर	177,433	-	-	177,433	-	-	-	-	177,433
2	स्वास्थ्य एवं इसके वित्तीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	10,095,978	-	-	10,095,978	-	-	-	-	10,095,978.00
3	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- स्वास्थ्य एवं इसके वित्तीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	4,811,683	-	709,305	5,520,988	-	-	-	-	5,520,988
4	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण – यूएनडीपी	512,553	-	-	512,553	-	-	-	-	512,553
5	डिजीटल लैंड के प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन – एनसीईएआर उप-अनुदान	927,993	-	-	927,993	-	-	-	-	927,993
6	एनआईपीएफपी – ट्राई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम	42,521	-	-	42,521	-	-	-	-	42,521
7	क्या मौद्रिक नीति से भारत में वित्तीय स्थिरता संभव है-आईसीएसएसआर	161,916	-	-	161,916	-	-	-	-	161,916
8	भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन की पद्धति : आगे की दिशा - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	9,084,412	-	34,311,585	43,395,997	28,263,732	302,670	28,566,402	-	14,829,595
9	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- भारत में स्वास्थ्य पर लोक वित्तीयन की पद्धति : आगे की दिशा - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,974,256	-	656,247	2,630,503		-	-	-	2,630,503
10	लोक वित्तीयन पर नवोपायों के परिणाम - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	6,448,908	-	31,189,805	37,638,713	37,638,713	-	37,638,713	-	-
11	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- लोक वित्तीयन पर नवोपायों के परिणाम - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	5,454,650	-	335,585	5,790,235	4,514,275	-	4,514,275	-	1,275,960
12	डेटा रक्षण के लिए सहमति फ्रेमवर्क में सुधार -ओमिदयार नेटवर्क	121,098	-	-	121,098		-	-	-	121,098
13	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण – यूएनडीपी II	187,710	-	-	187,710		-	-	-	187,710
14	प्रभावशाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना के संगठनात्मक डिजाइन एवं आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसंधान अध्ययन में सहयोग-ओमिदयार नेटवर्क	39,354	-	-	39,354	39,354	-	39,354	-	-
	कुल आगे ले जाया गया	40,040,465	-	67,202,527	107,242,992	70,456,074	302,670	70,758,744	-	36,484,248

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

		1 अप्रैल, 2020 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2020 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2021 को वसूली योग्य	31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त
	कुल आगे ले जाया गया	40,040,465	-	67,202,527	107,242,992	70,456,074	302,670	70,758,744	-	36,484,248
15	हिमालय संरक्षण के लिए सहायता सेवा, हिमाचल प्रदेश – यूएनडीपी	1,135,087	-	1,138,500	2,273,587	2,375,390	-	2,375,390	101,803	-
16	हिमालय संरक्षण के लिए सहायता सेवा, सिक्किम– यूएनडीपी	1,140,583	-	1,138,500	2,279,083	2,507,163	-	2,507,163	228,080	-
17	विशेष क्षेत्र अनुसंधान के विशिष्ट मुद्दों पर गृह मंत्रालय के साथ सहयोग कार्यक्रम के संबंध में डिजीटल लाइब्रेरी/दस्तावेज केन्द्र का निर्माण एवं अनुरक्षण – आईसीएसएसआर	-	299,694	-	(299,694)	-	-	-	(Refer to Note 1 below)	-
18	एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार 2019-20	-	4,413,170	4,413,170	-		-	-	-	-
19	एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार 20120-21	-		5,260,150	5,260,150	10,185,040	-	10,185,040	4,924,890	-
20	भारत के लिए उपभोक्ता वित्त में एक शिकायत निवारण प्रबंधन ढांचे की व्यवस्था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	12,490,121	-	22,400,307	34,890,428	11,903,758	-	11,903,758	-	22,986,670
21	अनुदान पर ब्याज विनियोजन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	114,726	-	989,852	1,104,578	-	-	-	-	1,104,578
22	डेटा गवर्नेंस नेटवर्क - आईडीएफसी संस्थान	1,689,624	-	915,200	2,604,824	2,604,824	-	2,604,824	-	-
23	आधार व्यवस्था मैं दिव्यांगों की प्रतिभागिता - इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस	-	271,876	381,800	109,924	109,924	-	109,924	-	-
24	भूमि और संपत्ति के अधिकारों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए - ओमिडयार नेटवर्क III	6,829,979	-	2,905,200	9,735,179	8,752,939	-	8,752,939	-	982,240
25	सरकारी स्कूलों से निर्गम एक जांच - अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय	158,009	-	505,516	663,525	606,758	-	606,758	-	56,767
26	न्याय चुनौती के लिए डेटा: वयं फोरम फॉर सिटीजनशिप	343,220	-	-	343,220	301,816	-	301,816	-	41,404
27	भारत में सार्वजनिक खरीद और दवा की गुणवत्ता: ठाकुर फाउंडेशन	-	-	3,012,700	3,012,700	2,764,850	-	2,764,850	-	247,850
	जोड़	**63,941,814**	**4,984,740**	**110,263,422**	**169,220,496**	**112,568,536**	**302,670**	**112,871,206**	**5,254,773**	**61,903,757**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची 5–ख–केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020को
अप्रयुक्त अनुदान का अग्रशेष	(68,735,837)	(71,876,840)
जमा : वर्ष के दौरान वेतन एवं भत्तों के लिए प्राप्त अनुदान	189,100,000	100,000,000
वर्ष के दौरान आवर्ती व्यय के लिए प्राप्त अनुदान	-	-
	120,364,163	**28,123,160**
घटा : वेतन और भत्तों के लिए प्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखे आय के रुप में प्रभारित)	87,727,623	96,858,997
आवर्ती व्ययों का अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखे आय के रुप में प्रभारित)	-	
योग - अप्रयुक्त अनुदान (प्राप्ति योग्य) अनुदान	**32,636,540**	**(68,735,837)**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र् का भाग है

अनुसूची 6 - अचल परिसंपत्तियां

धनराशि रूपयों में

	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2020 का	अभिवृद्धियां	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 2021 का	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 का	31 मार्च 2020 का
	स्वयं की निधियों में से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां										
1	लीजहोल्ड भूमि	18,809,202	-	-	18,809,202	-	-	-	-	18,809,202	18,809,202
2	भवन	33,295,716	609,644	-	33,905,360	13,011,766	820,842	-	13,832,608	20,072,752	20,283,950
3	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	30,622,466	57,354	-	30,679,820	27,052,142	1,481,321	-	28,533,463	2,146,357	3,570,324
4	कार्यालय उपस्कर	9,997,478	6,500	-	10,003,978	8,762,825	338,681	-	9,101,506	902,472	1,234,653
5	फर्नीचर और सज्जा	11,628,425	912,114	-	12,540,539	10,862,196	127,737	-	10,989,933	1,550,606	766,229
6	होस्टल, पुस्तकालय, कंप्यूटर तथा सेमिनार	3,641,172	-	-	3,641,172	3,638,568	406	-	3,638,974	2,198	2,604
7	एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	6,665,875	885,075	-	7,550,950	5,617,371	195,789	-	5,813,160	1,737,790	1,048,504
8	विद्युत संस्थापन	6,786,144	247,277	-	7,033,421	6,219,603	80,702	-	6,300,305	733,116	566,541
9	वाहन	1,424,148	-	-	1,424,148	534,181	115,040	-	649,221	774,927	889,967
10	बागवानी उपस्कार	109,780	-	-	109,780	109,780	-	-	109,780	-	-
11	प्रगति में पूंजीगत कार्य	1,180,444	-	1,180,444	-	-	-	-	-	-	1,180,444
	जोड़	**124,160,850**	**2,717,964**	**1,180,444**	**125,698,370**	**75,808,432**	**3,160,518**	**-**	**78,968,950**	**46,729,420**	**48,352,418**
	केंद्रीय सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1	इमारत-अनुसधान प्रशिक्षण केंद्र	21,289,579	-	-	21,289,579	4,845,042	313,879	-	5,158,921	16,130,658	16,444,537
2	विद्युतीय, अग्नि-शमन आर एचवाएसा कार्य-अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	6,900,850	-	-	6,900,850	6,900,850	-	-	6,900,850	-	-
	जोड़	**28,190,429**	**-**	**-**	**28,190,429**	**11,745,892**	**313,879**	**-**	**12,059,771**	**16,130,658**	**16,444,537**
	विभिन्न प्रायोजको से सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	4,156,385	-	-	4,156,385	4,024,368	-	-	4,024,368	132,017	132,017
2	कार्यालय उपस्कर	216,380	-	-	216,380	197,600	9,606	-	207,206	9,174	18,780
3	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-आईसीएसएसआर	51,500	-	-	51,500	39,273	9,652	-	48,925	2,575	12,227
4	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर- मध्य प्रदेश	-	89,000	-	89,000		12,509	-	12,509	76,491	0
5	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-आर बी आई	-	106,650	-	106,650		21,929		21,929	84,721	0
	जोड़	**4,424,265**	**195,650**	**-**	**4,619,915**	**4,261,241**	**53,696**	**-**	**4,314,937**	**304,978**	**163,024**
	विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	9,880	-	-	9,880	9,880	-	-	9,880	-	-
2	फर्नीचर और सज्जा	1,523,860	-	-	1,523,860	1,523,860	-	-	1,523,860	-	-
3	बागवानी उपस्कर	624,980	-	-	624,980	624,980	-	-	624,980	-	-
	जोड़	**2,158,720**	**-**	**-**	**2,158,720**	**2,158,720**	**-**	**-**	**2,158,720**	**-**	**-**
	विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-आईडीआरसी	154,571	-	-	154,571	146,842	-	-	146,842	7,729	7,729
2	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-बीएमजीएफ-||	478,283	302,670	-	780,953	288,204	198,674	-	486,878	294,075	190,079
3	कार्यालय उपस्कर-एनसीईएआर-उप ग्राण्ट-|||	22,000	-	-	22,000	12,437	4,180	-	16,617	5,383	9,563
4	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-बीएमजीएफ-|||	162,250	-	-	162,250	89,526	51,379	-	140,905	21,345	72,724
	जोड़	**817,104**	**302,670**	**-**	**1,119,774**	**537,009**	**254,233**	**-**	**791,242**	**328,532**	**280,095**
	कुल जोड़	**159,751,368**	**3,216,284**	**1,180,444**	**161,787,208**	**94,511,294**	**3,782,326**	**-**	**98,293,620**	**63,493,588**	**65,240,074**
	पिछला वर्ष	**154,818,437**	**6,378,401**	**1,445,470**	**159,751,368**	**92,591,451**	**3,365,313**	**1,445,470**	**94,511,294**	**65,240,074**	**-**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

		31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को
अनुसूची-7 : निवेश-धर्मादा/विनिश्चित निधियां				
दीर्घावधि निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियों में		95,813,079		91,813,079
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		169,731,349		198,930,977
वर्तमान निवेश				
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		126,342,634		62,372,159
जोड़		**391,887,062**		**353,116,215**
अनुसूची-8 : निवेश - अन्य				
दीर्घावधि निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियों में		65,010,000		73,323,544
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		92,400,963		122,400,963
वर्तमान निवेश				
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		73,276,308		14,823,002
प्रतिभूति जमा के विरूद्ध अनुसूचित बैंक के पास सावधि जमा		78,499		78,499
जोड़		**230,765,770**		**210,626,008**
अनुसूची-9 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क. **वर्तमान संपत्ति**				
1. इनवेंटरीज				
प्रकाशनों का भंडार		90,937		90,937
2. विविध देनदार		120,780		342,198
3. हाथ में नकद शेष -चेक/अप्रदाय सहित		16,435		27,308
4. बैंक शेष				
बचत खाता-अनुसूचित बैंकों के पास				
केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484101001555	31,240,580		20,867,497	
केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484106026094	95,574,281		74,281	
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू खाता सं. 10596549875	18,180		17,694	
अनुसूचित बैंकों के पास-चालू खाता				
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू, एफसी खाता सं. 10596547368	10,105,117		21,327,810	
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू चालू खाता सं. 10596547335	42,658		43,307	
		136,980,816		42,330,589
ख ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां,				
1. अग्रिम व अन्य राशि-नकद अथवा समान अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के रूप में वसूली योग्य:				
क. पूर्वप्रदत्त व्यय	7,479,570		3,944,043	
ख व्यय के लिए स्टाफ को अग्रिम	63,174		310,554	
ग. अन्य अग्रिम	547,642		326,712	
घ प्रतिभूति जमा	588,719		588,719	
ड. इनपुट कर क्रेडिट	4		147,107	
		8,679,109		5,317,135
2. उपार्जित आय				
क. विनिश्चित/धर्मादा निधियों में निवेशों पर आय	4,078,363		4,132,180	
ख. निवेशों पर - अन्य	1,725,239		2,210,646	
ग. राज्य सरकार अनुदान	500,000		100,000	
घ. पाठ्यक्रम कार्यक्रम और परियोजना आय	13,881,715		5,687,387	
ड. परियोजना अनुदान (अनुसूची 5 (क) देखें)	5,254,773		4,984,740	
च. केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान (अनुसूची 5 (ख) देखें)	-		68,735,837	
		25,440,090		85,850,790
3. प्राप्ति योग्य दावे				
क आय कर वसूली योग्य		13,233,114		26,145,444
जोड़		**184,561,281**		**160,104,401**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
अनुसूची-10 : केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. केंद्रीय सरकार से अनुदान		
वेतन अनुदान - देखें अनुसूची 5-ख	87,727,623	96,858,997
जोड़-क	**87,727,623**	**96,858,997**
ख. राज्य सरकारों से अनुदान		
सामान्य सहायता अनुदान		
उड़ीसा सरकार	500,000	500,000
महाराष्ट्र सरकार	99,000	100,000
तमिलनाडु सरकार	100,000	100,000
गुजरात सरकार	500,000	500,000
जोड़-ख	**1,199,000**	**1,200,000**
कुल जोड़-क+ख	**88,926,623**	**98,058,997**
अनुसूची-11 : अकादमिक कार्यकलापों से आय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	18,096,665	17,528,888
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान - संदर्भ अनुसूची 5-क	112,871,206	151,496,248
जोड	**130,967,871**	**169,025,136**
अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज		
बैंको/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित ब्याज		
अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा पर	1,564,650	1,692,727
अनुसूचित बैंकों के पास बचत खातों पर	434,286	692,474
सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों पर	12,548,297	12,601,128
आयकर वापसी पर ब्याज	4,468,779	2,704,397
अन्य ब्याज	73,960	81,820
जोड	**19,089,972**	**17,772,546**
अनुसूची-13 : अन्य आय		
प्रकाशनों की बिक्री	-	200
वसूलियां	15,409,442	22,566,398
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	-	310,375
विविध आय	1,497,737	191,810
मकान किराया वसूलियां	142,820	166,678
रा.जो.वि.नी.सं. स्टाफ से प्राप्त परामर्श फीस	410,433	15,254
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	23,443	85,271
आस्थगित आय से अंतरित राशि (अनुसूची 3 देखें)	621,808	554,647
जोड	**18,105,683**	**23,890,633**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
अनुसूची-14 : स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	79,869,171	88,530,623
बोनस	241,780	262,504
पीएफ व पेंशन निधि के लिए अंशदान	7,838,639	8,564,658
उपदान	7,398,130	6,295,114
छुट्टी वेतन	2,625,265	11,499,650
स्टाफ लाभ तथा कल्याण	3,587,839	4,166,366
ईडीएलआई तथा प्रशासनिक प्रभार	172,971	188,192
परामर्श फीस	282,500	754,647
	102,016,295	**120,261,754**
घटा : अकादमिक कार्यकलापों को प्रभारित	40,301,364	34,881,865
जोड़	**61,714,931**	**85,379,889**
अनुसूची-15 : अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना खर्च	7,298,864	11,298,108
परियोजना अनुदान का उपयोग-अनुसूची 5-क देखें	112,871,206	151,496,248
जोड़	**120,170,070**	**162,794,356**
अनुसूची-16 : प्रशासनिक व्यय		
यात्रा और सवारी	129,619	1,000,766
दरें और कर	1,203,556	1,201,179
विद्युत प्रभार	6,045,931	8,079,869
जल प्रभार	833,230	1,112,808
मुद्रण और लेखन सामग्री	328,667	784,342
टेलीफोन और डाकखर्च	1,289,133	1,451,538
मरम्मत और अनुरक्षण	13,536,841	14,490,865
कार संचालन और अनुरक्षण	118,430	262,459
आडिट फीस	186,448	193,718
ऑडिट फीस-आंतरिक	112,844	124,797
आडिट फीस-पीएफ ट्रस्ट	22,000	22,564
आडिट फीस-उपदान ट्रस्ट	26,064	20,000
विविध व्यय	306,069	331,110
विधिक व्यय	444,695	422,876
विज्ञापन पर व्यय	416,390	276,922
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	46,000	95,850
ब्याज की कमी और अन्य व्यय (पीएफ निधि)	-	880,766
पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	10,420,334	8,395,238
प्रकाशनों की लागत	140,878	122,460
बैठक और सेमिनार	8,578	226,386
साधारण/शासी निकाय बैठक	930	149,949
बीमा व्यय	139,479	139,169
वसूली योग्य-बट्टे खाते डाला गया	366,187	442,500
व्यावसायिक फीस	159,658	198,064
	36,281,961	40,426,195
घटा : धर्मादा/विनिश्चित निधियों के लिए प्रभारित	768,253	805,834
घटा : धर्मादा/विनिश्चित निधियों के लिए प्रभारित	3,200,000	-
जोड़	**32,313,708**	**39,620,361**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची17-लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों का निर्माण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक अभिसमय के अधीन उपचय आधार पर और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखाकरण मानकों, यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, के अनुसार किया जाता है। सामान्य सदस्यता शुल्क को नकद आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

2. वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने के लिए ऐसे प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है जिनसे प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों,राजस्व और व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित होती है। यद्यपि ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम परिणत होते हैं।

3. दीर्घावधिक निवेशों को ह्रास, अस्थाई के अलावा, के समायोजन के पश्चात उनकी वहन लागत पर अग्रेनित किया जाता है। चालू निवेश लागत और उचित मूल्य में से न्यूनतर के आधार पर अग्रेनित किए जाते हैं। निवेशों की लागत में, यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रीमियम सहित सभी अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई चेयर ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए दी गई कायिक निधि में से प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों, जब इन्हें प्रीमियम पर अधिग्रहीत किया गया हो, का उल्लेख आरबीआई और संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार आरबीआई काय निधि से उपार्जित ब्याज आय के सापेक्ष किया गया है।

4. प्रकाशनों की मालसूची का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर किया गया है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशन और परियोजना अनुदानों से वित्तपोषित प्रकाशनों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है।

5. अचल परिसम्पत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आनुशंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं। अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है।

6. प्रबंधन द्वारा पॉच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार के पश्चात परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर सरल रेखा पद्धति से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:-

परिसम्पति विवरण	उपयोज्यता काल
भवन	60 वर्ष
डेटा संसाधन उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्निचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
होस्टल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	8 वर्ष
एयर कंडीनर एवं वाटर कूलर	10 वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
बागवानी उपकरण	5 वर्ष

7. प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से किसी परिसम्पत्ति का क्षय होने के संबंध में आकलन किए जाते हैं। ऐसे क्षय के किसी संकेत के मामले में, प्रबंधन परिसम्पत्ति द्वारा वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वाहित राशि से कम है, तो परिसम्पत्ति की वाहित राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और अंतर को अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

8. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीद के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. अल्पावधिक कर्मचारी लाभों को आय एवं व्यय के लेखे में छूट न दी गई राशि के व्यय के रूप में सेवाएं प्रदान किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया गया है।

10. रोजगार के बाद के और अन्य दीर्घावधिक लाभों को उस वर्ष के आय व्यय लेखे में छूट न दी गई राशि पर हुए व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर स्वीकृति दी गई है। रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को सामान्यतः संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखा पुस्तिकाओं में लेखाबद्ध किया गया है।

12. चिह्नित/वृत्ति निधियों से निवेशों पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट उद्देष्यों के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि के शेष को, यदि कोई हो, संबंधित चिह्नित/वृत्ति निधियों में रखा गया है।

13. विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभिक तौर पर देनदारी माना गया है और वर्ष के दौरान उपयोगिता के अुनसार समायोजित किया गया है। अनुदानों को, मूल्यह्रास के योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक, आस्थगित आय माना गया है और इन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखे में स्वीकृति दी गई है। राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त सीमा तक वेतनों और परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय माना गया है। आवर्ती व्ययों के लिए अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

14. प्रावधानों को वहां स्वीकृति दी गई है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी हो तथा जिसके लिए यह संभव हो कि देनदारी के समाधान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा और विश्वसनीय प्राक्कलन संभव हो सकेगा। देनदारी के समाधान के लिए अपेक्षित प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और जहां देनदारी के चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन के लिए आवश्यक हो, समायोजित किया गया है।

15. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया गया है जब एक संभावित देनदारी या वर्तमान देनदारी हो जिसके लिए संसाधनों का वह बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो सकता हो, जो संभावित रूप से अपेक्षित नहीं है। उस वर्तमान देनदारी के संबंध में भी प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो, जहां संबंधित बर्हिप्रवाह का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जाना संभव न हो।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 - खातों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं / परिसम्पत्तियां

   संस्थान के विरूद्ध एवं संस्थान द्वारा दायर किए न्यायिक मामलों के संबंध में देयता : राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं: शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संज्ञान की गई एवं एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के खंड 22 में अनुपालन में संस्थान में उपलब्ध देयताएं:

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि	991270	659126
वर्ष के दौरान ब्याज उपचय की राशि तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदात्ता को खंड 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता किए गए ब्याज की राशि	-	-
भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित चुकता न किया गया बकाया ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय बढ़त ब्याज की राशि जो वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक के लिए खंड 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को चुकता की जानी है।	-	-

4. संस्थान के प्रबंधन के मतानुसार, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम से उस राशि के समान है जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो और सभी ज्ञात देयताओं के लए प्रावधान वित्तीय विवरणिका में किया गया है।

   31 मार्च, 2021 को कुल ₹ 1,32,35,017 की वसूली योग्य आयकर में से, ₹ 38,77,570 की वसूली योग्य आयकर वित्तीय वर्ष 2012-13 और पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं।

5. वृत्ति/चिह्नित निधियों के निवेशों में ₹ 5,15,93,962 रूपए के उद्धृत निवेश और ₹ 34,02,93,100 के अनुद्धृत निवेशशामिल हैं। उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य रूपए ₹ 5,80,34,505 है।

   अन्य निधियों में ₹ 23,07,65,770 रूपए की राशि का निवेश अनुद्धृत निवेश है।

   वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदायी योजना का विवरण निम्नानुसार है

   भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान रु.70,04,889 (पिछले वर्ष रु. 76,29,658)

   पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान रु. 8,33,750 (पिछले वर्ष रु. 9.35,000)

   एक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है। देनदारी के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के रूप में स्वीकृत किया गया है और अंतिम देनदारी निर्मित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा गया है। छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी को इसी तरीके से ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत किया गया है।

   तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मूल बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार हैः

   क) आर्थिक अनुमान

   मूल पूर्वानुमान इस प्रकार हैं (1) छूट की दर (2) वेतन वृद्धि। छूट वृद्धि लेखाकरण तिथि को सरकारी बंधपत्रों पर उपलब्ध बाजार अर्जन पर उस शर्त पर आधारित है जो देयताओं की शर्तों से मिलती हों और वेतन वृद्धि में मूल्यवृद्धि, वरिष्ठता, प्रोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, अक्षमता के लिए कोई सुस्पष्ट भत्ते का उपयोग नहीं किया गया है।

	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
i)	छूट की दर	6.75%	6.75%
ii)	भावी वेतन वृद्धि	9.00%	8.00%
iii)	ग्रैचुइटी के लिए योजना परिसम्पत्तियों की प्रत्याशित प्रतिफल दर (वित्त पोषित)	6.75%	6.75%
ख)	जन सांख्यिकी अनुमान	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
i)	सेवा निवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
ii)	मृत्यु सारणी	आई ए एल एम 2012-14	आई ए एल एम 2012-14
			अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रतिवर्ष)	2.00%	2.00%

6. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी इन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक हो, पुनर्निर्मित, पुनप्रतिशत समूहबद्ध, पुनः व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बीएस रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती	(डॉ. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकार्र	निदेशक	अध्यक्ष

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

अनीश आशीष एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म के लिए पंजीकरण संख्या 002535N

(आशीष गुप्ता)

सहभागी

एम सं 503829

यू डी आई एन: 21503829AAAAHQ8464

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23 दिसंबर 2021

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान,
18/2, सत्संग विहार मार्ग,
विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के पास),
नई दिल्ली 110067, भारत
दूरभाष. नंबर: 011 26569303, 26569780, 26569784
वेबसाइट: https://nipfp.org.in/